सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा | वृहस्पतिवार, तिथि 17 मार्च, 2022 ई॰

पंचम सत्र | 26 फाल्गुन, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्य स्थगन है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, आचार समिति को जो...

अध्यक्ष : समय पर उठाइयेगा । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाय, आचार समिति की दुहाई देकर मंत्री महोदय ......

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-84 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-372(4)/रा॰, दिनांक- 30 जून, 2015 द्वारा राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्त किया गया है ।

बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 के अनुसार बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1597 है । मूल कोटि के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों का राजस्व कर्मचारी संवर्ग के स्नातक अथवा समकक्ष योग्यताधारी कर्मियों के राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है ।

सम्प्रति राज्य सरकार के सभी संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई पर रोक के मद्देनजर राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राजस्व अधिकारी का अभी वर्तमान में 534 अंचलों में से कितने अंचलों में इनके अभी राजस्व अधिकारी हैं और जो उसमें रिटायर कर गये, अवकाश प्राप्त कर गये, उसको छोड़कर उसमें अद्यतन स्थिति क्या है ? महोदय, दूसरा है कि राजस्व अधिकारी के लिए 12 वर्ष बीत गये और केवल एक परीक्षा हुई है तो जब राजस्व अधिकारी नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भूमि सुधार का काम सरकार जिस गति से चाहती है उसमें तो बिल्कुल नहीं हो पायेगा । माननीय मंत्री जी, कृपया बतायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तुरंत विगत दो महीने पहले बी0पी0एस0सी0 से 566 राजस्व पदाधिकारी प्राप्त हुए थे जिनमें से 440 को ज्वाइनिंग करा दिया गया है, पोस्टिंग भी हो गयी है । 440 अंचलों में राजस्व अधिकारी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसके पहले 4 हमारे राजस्व अधिकारी थे वे भी हैं और जहां अंचलों में नहीं हैं तो वहां पर कर्मचारी को चार्ज दिया गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रोन्नति पर सरकार ने रोक लगा दी है, महोदय, जब परीक्षा ही नहीं हुआ है तो प्रोन्नति से कितना भरा जायेगा राजस्व अधिकारी को । माननीय मंत्री जी परीक्षा 12 वर्षों में एक बार लिये हैं तो उस परीक्षा को नियमित करना चाहते हैं और अगर यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो जो प्रमोशन की स्थिति है महोदय, आज तक एक भी डी0सी0एल0आर0 प्रमोशन से नहीं हुआ है तो जब राजस्व अधिकारी हमारे पास नहीं होगा तो राजस्व और भूमि सुधार की बात करना हमलोगों के लिए बेईमानी हो जायेगी महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी इसको बतायें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, प्रमोशन का मामला रूका हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया में है। आदेश आते ही प्रमोशन हेतु एग्जाम लिया जायेगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि जब वर्ष 2010 में राजस्व विभाग का नया सेवा संवर्ग बना, फिर उसमें वर्ष 2019 में संशोधन किया गया और 25 प्रतिशत को प्रमोशन से बढ़ना था जो मूल विषय है, जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अभी भी सभी अंचलों में सी0ओ0 पदस्थापित नहीं हैं तो 25 प्रतिशत जो इनको प्रमोशन से भरना था तो आज कोर्ट के द्वारा रोक लगी हुई है लेकिन क्या ये 25 प्रतिशत से सभी अंचलों को भर सकेंगे ? जब भी यह रोक हटती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल ऐसी प्रक्रिया नहीं है । एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट का आदेश आयेगा तो प्रमोशन देकर किया जायेगा लेकिन हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर आ गये हैं बी0पी0एस0सी0 से तो उनको हमलोग प्रभारी अंचलाधिकारी बनाकर सभी जगह काम लेते हैं और काम कर भी रहे हैं । कहीं भी काम बाधित नहीं है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ । वर्ष 2019 में जो संशोधन किया गया विभाग के द्वारा, उसमें इन्होंने तय किया कि 25 प्रतिशत को हम प्रमोशन से उस पद को भरेंगे । सभी प्रखंडों में वर्ष 2010 में नई व्यवस्था लागू हुई, प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी नया सेवा संवर्ग बना और अंचलाधिकारी का भी बना लेकिन उसके बाद भी जो मूल प्रश्न है कि सभी अंचलों में क्या अंचल पदाधिकारी आज के समय में पदस्थापित नहीं हैं और जो प्रमोशन से नहीं हो पा रहे हैं तो इनकी रिक्तियां जितनी हैं, क्या प्रमोशन पर रोक के हट जाने के बाद सभी रिक्तियां इनकी भर जायेंगी ? यह मेरा मूल प्रश्न है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, 25 परसेंट से पूरा नहीं भरेगा लेकिन नियमानुकूल जो हो सकता है कार्रवाई करूंगा, एग्जामिनेशन लूंगा या पदाधिकारी आयेंगे तो मैं भरने का प्रयास करूंगा ।

अध्यक्ष : चलिये, ठीक है । श्री तेजस्वी प्रसाद यादव । प्राधिकृत हैं डॉ॰ रामानुज प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-85 (श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या-128, राघोपुर)

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न संसदीय कार्य विभाग में स्थानांतरित हुआ है ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब इसी सत्र में आ जाय । महोदय, इसी सत्र में इसको सोमवार को लिया जाय ।

अध्यक्ष : जिस दिन रहेगा आ जायेगा । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-86 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- L-12013/02/2021-I&P, दिनांक- 19 अप्रील, 2021 द्वारा चरणबद्ध तरीके से अगले तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण करने हेतु भारत सरकार के स्तर से प्रायोजित योजना का प्रारूप प्रेषित करते हुए मंतव्य की मांग की गई है । प्रस्तावित योजनान्तर्गत प्रति पैक्स व्यय 4.37 लाख निर्धारित है । व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य का शेयर निर्धारित है । योजना के संबंध में विभागीय पत्रांक-2515, दिनांक-4 मई, 2021 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया जा चुका है ।

2- उपरोक्त कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

3- उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब के कंडिका-1 को देखा जाय । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 2020-21 और 2021-22 में राज्य के कितने पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण हुआ है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-L-12013/02/2021-I&P, दिनांक- 19.04.2021 द्वारा चरणबद्ध तरीके से अगले तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण करने हेतु भारत सरकार के स्तर से प्रायोजित योजना का प्रारूप प्रेषित करते हुए मंतव्य की मांग की गई है । महोदय, वर्ष 2021 में मांग की गई है और इस प्रस्तावित योजनांतर्गत प्रति पैक्स व्यय 4.37 लाख निर्धारित है । व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का शेयर निर्धारित है । योजना के संबंध में विभागीय पत्रांक-2515, दिनांक-04.05.2021 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया जा चुका है तो महोदय इसमें स्पष्ट है।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्री जी उस चीज को नहीं समझें । मेरा यह प्रश्न है कि भारत सरकार का जो पत्र है वह दिनांक- 19.04.2021 का है कि राज्य के सभी पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है । यह वर्ष 2021 का पत्र है, सहकारिता विभाग में एक वर्ष में 2021-22 में कितने पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण राज्य में किया गया है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ और नहीं हुआ है तो दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो अभी प्रस्ताव ही है । अभी प्रस्ताव फाईनल नहीं हुआ है, मंतव्य में ही है तो फिर आगे कार्रवाई की बात कैसे करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, एक साल हो गया । यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, राज्य के किसानों से जुड़ा हुआ है, सहकारिता का मामला है और दिनांक 19.04.2021 को भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय का पत्र आया । एक वर्ष में राज्य में यह चीज क्यों नहीं हुआ ? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें । एक साल बहुत समय होता है । पांच साल के लिए हमलोग जीत कर आते हैं ।

अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मंत्री जी बतायेंगे, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं । मंत्री जी बतायेंगे, अवगत करायेंगे या नहीं करायेंगे, कब तक होगा यह काम, राज्य सरकार कब तक इसको करने का विचार रखती है कोई लक्ष्य होगा न ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है । राज्य सरकार के जो हमारे उप निबंधक हैं वे वर्ष 2022 में चिट्ठी भी भेजे हैं । महोदय, दिनांक-07.03.2022 को चिट्ठी भेजकर राज्य सरकार द्वारा स्मार पत्र भारत सरकार को दिया गया है कि आप इस मंतव्य का शीघ्र किया जाय तो महोदय जैसे ही उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी तो हम करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, प्रश्न करने के बाद विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है । मेरा यह कहना है कि एक वर्ष तक भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विभाग ने क्यों रोक कर रखा ? 40 परसेंट राज्य सरकार को देना है और 60 परसेंट भारत सरकार का है तो विभाग ने ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को दबा कर क्यों रखा ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह योजना कई वर्षों से चर्चा में है, करीब-करीब 6-7 वर्षों से चर्चा में है और भारत सरकार के पास प्रस्ताव, यह लगता है कि तीसरी बार यह प्रस्ताव जा रहा है और गया है । एक वर्ष बीत गये, तीन वर्ष की योजना है महोदय तो क्या इससे प्रतीत होता है कि सरकार, या तो यहां की सरकार या फिर केन्द्र की सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है । पैक्स की गतिविधियों पर हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात किसानों की तरफ से उठती रही है । संगठनों ने और माननीय विधायाकों ने कई बार उठाया है तो मेरा निवेदन होगा कि इसको परश्यू कर जल्द-से-जल्द इस योजना को लागू करते हुए सारे पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण हो ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-87 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-3-1/2015-M&T(I&P), दिनांक-24.02.2021 द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना हेतु केन्द्रांश 1617.80 लाख रुपये एवं पत्रांक-3-6(KKA)/2020-M&T(I&P) Part, दिनांक-24.02.2021 द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजनांतर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज-।।। हेतु केन्द्रांश 1574.40 लाख रुपये का विमुक्ति आदेश निर्गत किया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति नजदीक रहने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष 2021-21 की योजना 31 मार्च, 2021 के पूर्व स्वीकृत नहीं हो पायी । तदोपरांत उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-3-1(Bihar)/2015-M&T(I&P) (27719), दिनांक- 13.04.2021 द्वारा पुनर्वैद्यीकृत (Revalidate) किया गया ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उक्त दोनों योजनाएं- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजनांतर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज-।।। वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की राशि को न खर्च करने एवं उपयोगिता भेजने पर है जो कि जवाब में नहीं है । मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि राज्यांश नहीं देने के कारण योजना स्वीकृत नहीं हुई । इसके लिए कोई दोषी है तो महोदय, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे ? महोदय, दूसरा है कि वर्ष 2021-22 में 395.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं किया जो कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजे हैं तो यह राज्य के किसानों के समृद्धि के लिए इस तरह की लापरवाही सरकार द्वारा क्यों बरती गई है?

टर्न-2/संगीता/17.03.2022

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है और जो राशि आयी है 2020-21 में वह 2021 मार्च में आयी है । अब ये संभव नहीं हो पाया कि उस प्राप्त राशि का वो करके और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेज दिया जायेगा इसलिए उसको रिवैलिडेट किया गया है और उन तमाम राशि का जितना आपने जिक्र किया है तो उन सबका उपयोग हो जायेगा और मेकेनाईजेशन योजनांतर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज-III वर्तमान में उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : हमने यह भी कहा आपको कि 2021-22 में 395.48 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं किया, जो आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे उसके कारण, आप राज्यांश नहीं दिए उसके कारण तो आप यह बताइये कि इसके लिए क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं क्या आप दोषी को चिन्हित कर रहे हैं इसमें ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है वह समय का है, जिस समय में आया, अब समय नहीं बचा था सारी औपचारिकताओं को पूरा करने का और इस राशि से राज्य और किसान वंचित भी नहीं हुए हैं महोदय । इस राशि का उपयोग भी उसी प्रकार से जैसा पहले होता उसी प्रकार से इस राशि का भी उपयोग हो जाएगा और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं, राज्यांश नहीं दिए आप उसके कारण आपको फिर दूसरी किस्त नहीं मिली, लैप्सेज हुआ एक साल किसान के समृद्धि योजना के लिए ऐसे योजना राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आप केन्द्रांश तो मिला राज्यांश नहीं दिए उसके कारण आपका एक साल का आपका राशि नहीं मिला केन्द्र सरकार से, जिसमें राज्य सरकार दोषी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं कोई इसमें कोई दोषी नहीं है और इसमें कहीं राज्य को नुकसान भी नहीं हुआ है न किसानों को कोई क्षति हुई है उसका रिवैलिडेशन उसका कर दिया है अब पुनर्वैधीकरण हो जाने के बाद अब वो राशि फिर...

अध्यक्ष : आ जाएगी, चलिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : हमें उपलब्ध है और आगे की राशि भी लैप्श नहीं होगी वह राशि हमें मिलने वाली है वह भी मिलेगी ।

अध्यक्ष : श्री भाई वीरेन्द्र ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-88 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187 मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अन्तर्गत वर्षवार प्राप्ति योग्य राशि एवं प्राप्त राशि की विवरणी निम्नवत है :-

वित्तीय	विपत्र की राशि	प्राप्त राशि	प्राप्ति योग्य राशि	अभ्युक्ति
2013-14	14.61	14.40	0.21	लेखा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से राशि रोक ली जाती है, जिसे सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त विमुक्त किया जाता है । उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह जून, 2020 से अंकेक्षित लेखा तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुये लेखा तैयार करने एवं उसके सांविधिक अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है । इस क्रम में लेखाओं का अद्यतन स्थिति निम्नवत है:- (1) वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2019-20 तक का वार्षिक लेखाओं को तैयार कर निगम निदेशक पर्षद से अनुमोदित कराया गया है । (2) वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ।
2014-15	1808.32	1782.06	26.26	
2015-16	3621.30	3566.62	53.82	
2016-17	2801.54	2758.70	42.84	
2017-18	2940.02	2897.61	42.41	
2018-19	2046.81	2001.74	45.07	

				(3) वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लेखाओं का सांविधिक अंकेक्षण एवं सी0ए0जी0 अंकेक्षण का कार्य किया गया है । (4) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं तत्संबंधी अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है । (5) वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है । अत: निगम के स्तर से लम्बित सांविधिक अंकेक्षण के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर भारत सरकार द्वारा रोकी गई राशि विमुक्त करा ली जायेगी ।
Total	13232.6	13021.13	210.61	

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो मूल प्रश्न है और सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा जो जवाब आया है उसमें कहीं भी कोई मेल नहीं है वह सारा जवाब जो है गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, जो महालेखाकार का आंकड़ा है उससे परे सरकार ने गलत तरीके से जवाब देने का काम किया है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि महालेखाकार के प्रतिवेदन में आंकड़ा 212.50 करोड़ है जबकि माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में आंकड़ा 210.61 करोड़ बता रहे हैं । दोनों आंकड़ों में महालेखाकार का प्रतिवेदन में अंकित आंकड़ा सही है कि माननीय मंत्री जी का आंकड़ा सही है यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मुझे जानना है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में 2013-14 में जो राशि भारत सरकार के यहां हमारा बाकी है हमने विस्तार से इसमें बताया है महोदय, यह विभाग का सही है महोदय जैसे- 2013-14 में 0.21 करोड़ है, 2014-15 में 26.26 करोड़ है, 2015-16 में 53.82 करोड़ है, 2016-17 में 42.84 करोड़ है, 2017-18 में 42.41 करोड़ है, 2018-19 में 45.07 करोड़ है, यह महोदय टोटल कुल होता है 210.61 करोड़ महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमने इसी आंकड़े को चैलेंज किया है कि माननीय मंत्री जी का सरकार का जो जवाब है वह गलत है और सही आंकड़ा मांगा गया है जो महालेखाकार का आंकड़ा है उससे मिलान इनका नहीं खाता है इसलिए हम चाहते हैं कि...

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : नहीं महोदय, हमने तो विस्तार से बताया है महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ये आंकड़े जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया है वह सरासर गलत है और सदन को गुमराह करने वाला यह जवाब है ।

अध्यक्ष : चलिए । पूरक क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मंत्री जी के उत्तर में आंकड़े से संबंधित प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक दिया गया है परन्तु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई सरकार करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो 2002-03 से पेंडिंग था ऑडिट नहीं हुआ था, लगातार 2014 का हो गया है और 2014-15 का अंतिम चरण में ऑडिट हो रहा है तो हम जुलाई महीने तक महोदय, 2020-21 तक का ऑडिट करा लेंगे । ये तो पहले से पेंडिग आ रहा है...

अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य का पूरक है कि जो ये गलत आंकड़ा दिया है उसपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : दिखवा लेते हैं महोदय पहले, पहले मिलवा लेते हैं एक बार ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ये सिरियस और बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई का मामला है और हमेशा पता नहीं डिपार्टमेंट इनलोगों को आंकड़े पेश करते हैं और सदन को गुमराह करने वाले जवाब ये लोग देते हैं । हमारा यह कहना है कि दोषी पदाधिकारियों पर यह सरकार जिम्मेवारी तय करे कि ...

अध्यक्ष : ये तो बता रहे हैं कि दिखवा लेते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : 48.09 करोड़ रुपया अगर पदाधिकारियों की लापरवाही से धनराशि की जो यह हुई है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कहे कि दिखवा लेते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं, दिखवा नहीं लेते हैं इसको या तो स्थगित कीजिए हुजूर या नहीं तो विधान सभा की...

अध्यक्ष : फिर झमेला कराईयेगा क्या?

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं, कमिटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए, वित्तीय अनियमितता का मामला है, यह वित्तीय मामला है, यह वित्तीय अनियमितता का मामला है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, हम दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप दिखवा करके इसको स्थगित करेंगे, सदन में आप बतायेंगे, प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले पदाधिकारी पर किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखी जाएगी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो वर्षवार जो विभाग में...

अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है, आप दिखवा करके जवाब लेकर बता दीजिएगा चलते सदन में। अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'अ'-470 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226, शेरघाटी)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर परिषद्, शेरघाटी को 15वें वित्त आयोग मद में कुल राशि 234.82654 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख बेरासी हजार छह सौ चौबन रु0) मात्र आवंटित की गई है । साथ ही षष्ठम् वित्त आयोग से कुल 397.81505 लाख (तीन करोड़ संतानवे लाख एकासी हजार पांच सौ पांच रु0) मात्र राशि आवंटित की गई है । इनसे पार्क का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है । पुनःश्य जल जीवन हरियाली अन्तर्गत उपलब्ध राशि से तालाब का जीर्णोद्धार किया जा सकता है । यदि प्रश्नांकित तालाब एवं पार्क का जीर्णोद्धार की योजना, नगर परिषद्, शेरघाटी बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में प्राथमिकता के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर परिषद्, शेरघाटी द्वारा विचार किया जाएगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुगलकालीन तालाब है जो विगत 8 वर्ष पूर्व इस ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार हेतु लाखों रुपये की निविदा निकाली गई थी लेकिन स्थानीय ठेकेदार के द्वारा पैसों का...

अध्यक्ष : आप, प्रश्न तो है ही...

श्रीमती मंजु अग्रवाल : जी, जी पैसों का...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, प्रश्न का जवाब आ गया है ?

श्रीमती मंजु अग्रवाल : हां, जवाब आ गया है ।

अध्यक्ष : तब अब पूरक पूछिए न ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : जी, तो वह पैसा गबन कर लिया गया गया था तो मैं उन ठेकेदारों के प्रति जांच की मांग करती हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी के द्वारा अतिशीघ्र जीर्णोद्धार क आग्रह करती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, आग्रह आपका स्वीकार कर लेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये दोनों के संबंध में माननीय सदस्या ने जो आग्रह किया है और वह बोर्ड की बैठक में इसको पारित कराकर स्थानीय जो नगर निकाय उसको करेगी । ये दोनों महत्वपूर्ण है...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : हम निदेशित भी किए हुए हैं ।

अध्यक्ष : श्रीमती रश्मि वर्मा ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : पूछती हूं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2252 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र संख्या-3, नरकटियागंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् नरकटियागंज का पत्रांक-440, दिनांक-12.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोखरा चौक पर आदर्श पोखरा के सौन्दर्यीकरण एवं अन्य मद में नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश सं0-192, दिनांक- 17.02.2022 द्वारा जल जीवन हरियाली योजनान्तर्गत कुल राशि 36.22800 लाख (छतीस लाख बाईस हजार आठ सौ रु0) मात्र का आवंटित की गई है । उक्त आदर्श पोखरा पर छठ घाट सिढ़ी निर्माण, पेभर ब्लॉक तथा अन्य सौन्दर्यीकरण संबंधित कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग उत्तर पढ़ें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् नरकटियागंज का पत्रांक-440, दिनांक-12.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोखरा चौक पर आदर्श पोखरा के सौन्दर्यीकरण एवं अन्य मद में नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश सं0-192, दिनांक- 17.02.2022 द्वारा जल जीवन हरियाली योजनान्तर्गत कुल राशि 36.22800 लाख (छतीस लाख बाईस हजार आठ सौ रु0) मात्र का आवंटित की गई है । उक्त आदर्श पोखरा पर छठ घाट सिढ़ी निर्माण, पेभर ब्लॉक तथा अन्य सौन्दर्यीकरण संबंधित कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-3/सुरज/17.03.2022

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूं पहला कि यह कब तक संभव होगा और मात्र 36 लाख राशि आवंटित हुई है जो बहुत ही कम है और यह पोखरा हमारे शहर की हृदयस्थली है और काफी लंबा-चौड़ा पोखरा है, काफी चिर-परिचित डिमांड रही है पब्लिक की इसलिए जितनी जल्दी हो सके । कब तक यह योजना पूरी होगी ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो कार्य हम शीघ्र प्रारंभ करवा देते हैं और माननीय सदस्या ने कहा है कि जो तालाब है उसके अनुसार प्राक्कलन नहीं है तो उसको भी हम दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2253 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : खण्ड-(1)- अस्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, पटना के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि मौजा-महुली, थाना नं0-06 अन्तर्गत पोस्टल कॉपरेटिव, टेलीग्राफ कॉपरेटिव, आई0ए0एस0 कॉपरेटिव, पी0एन0टी0 कॉपरेटिव को भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर हस्तान्तरण/दस्तावेजों द्वारा दिया गया है । नागेश्वर कॉपरेटिव (नागेश्वर कॉलोनी) प्राईवेट कॉलोनी है, जो रैयती भू-खण्ड पर अवस्थित है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर जमाबन्दी भी चलती है । उक्त वर्णित कॉपरेटिव पी0डब्लू0डी0, पी0एम0सी0 भवन निर्माण विभाग से मुक्त है । साथ ही उक्त कॉपरेटिव को भूमि बन्दोबस्त नहीं की गई है ।

पाटलिपुत्रा कॉपरेटिव रैयती भूमि का अर्जन कर सरकार के द्वारा विधिवत पाटलिपुत्रा कॉपरेटिव को हस्तान्तरित की गई है ।

पी0डब्लू0डी0, पी0एम0सी0, भवन निर्माण विभाग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया कांउसिल (खासमहल) की किसी भी भूमि का फ्री होल्ड कर किसी संस्था/कॉपरेटिव को हस्तान्तरित/बन्दोबस्त नहीं की गई है ।

अतिक्रमणवाद की कार्रवाई सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, यह जो उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है बिल्कुल भ्रामक है, इस उत्तर में कहीं भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक के द्वारा स्पष्ट कीजिये कि कैसे भ्रामक है ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : सीधे कह देना कि भ्रामक है, गलत है यह उचित नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं आगे पूरक पूछ रहा हूं लेकिन यह आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों को उजाड़कर...

अध्यक्ष : फिर भूमिका मत बनाईये, फिर हम आगे बढ़ जायेंगे पूरक का मौका समाप्त हो जायेगा । सीधे पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, पूरक पूछ रहा हूं । यह मेरे सवाल में ही है सरकार कहती है कि यह विधिवत दिया गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 1956 आदेश के अनुसार सरकार कहीं भी जमीन अगर लेती है तो पहले उसको बसाने का काम करे फिर उजाड़े । क्या सरकार ने बचाने का काम किया कि उजाड़ दिया लोगों को ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, 1956 का मामला है, पूरा पढ़ दें ।

अध्यक्ष : पूरक पूछे हैं पूरक का जवाब दीजिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, किसी को उजाड़ा नहीं गया है और यह जमीन ट्रांसफर किया गया है और वह प्राईवेट कॉलोनी है या पी0डब्लू0डी0 है, पी0एम0सी0 भवन निर्माण विभाग से मुक्त है और यह जमीन जो है इस पर कहीं अतिक्रमण भी नहीं है और कोई अतिक्रमणवाद भी नहीं चल रहा है । अगर किसी माननीय सदस्य के

संज्ञान में कुछ हो तो हमसे मिलकर वह चीज दे सकते हैं मैं उस पर कार्रवाई कर दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : दूसरा पूरक है ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मंत्री जी के पास जवाब नहीं है । मैं स्पष्ट पढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि झोपड़ियां जो उजाड़ी गई उस पर महल और अपार्टमेंट बन रहा है । मंत्री जी के पास इसका जवाब है कि गरीबों की झोपड़ियां उजाड़कर महल बन रहे हैं और गरीबों को बसाया नहीं गया । दूसरा मेरा सवाल है कि जो आवंटित की गई भूमि है क्या सरकार उसकी पुन: जांच करायेगी कि वह सही आवंटित हुई है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : आप चाहें तो जांच हो जायेगी, आप जानकारी मुझे दें इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका पूरा जवाब इनको हम दे दें..

(व्यवधान)

पूरा चलेगा । सबसे पहले आप ही पर चलेगा, आपका भी प्रश्न है ।

अध्यक्ष : एक मिनट मंत्री जी । इनका भी पूरक सुन लीजिये एक ही बार पढ़ दीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, अकेले पटना के अंदर...

अध्यक्ष : कम शब्दों में पूरक पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, अकेले पटना के अंदर आर0ब्लॉक0 के पास इस तरह की झोपड़ियां बसी हुई हैं और अभी पुल निर्माण निगम के द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है उसमें दो दिन पहले नोटिस दिय जा रहा है कि आप परसों तक खाली कर दो नहीं तो उजाड़ देंगे । लाईन काट दिया गया, वाटर सप्लाई काट दिया गया और उसके बाद हमलोगों ने ज्ञापन दिया डी0एम0 साहब को । वहां से आश्वान यह मिला कि उन्हें पुनर्वासित किया जायेगा लेकिन मेरा कहना है कि इतनी सारी बस्तियां बसी हुई है क्यों नहीं सरकार उसका सर्वे कराकर और उसके पुनर्वास की व्यवस्था करती है तब अधिग्रहण का कार्य करे...

अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये आर्डर...

अध्यक्ष : अब श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उसका पुनर्वास सुनिश्चत करे समय सीमा के अंदर उसके बाद...

अध्यक्ष : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-2254 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, क्षेत्र सं0-17, पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : 1. खण्ड-(1)- अस्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण के प्रतिवेदन के अनुसार आर0डब्लू0डी0 सड़क में अतिक्रमण की सूचना नहीं है ।

उक्त सड़क में ग्राम पंचायत से नली-गली योजना के तहत सड़क ढलाई का कार्य हो रहा है । वर्तमान में 150 कड़ी की लम्बाई में सड़क का ढलाई कार्य नहीं हुआ है ।

2. खण्ड-(2)-स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मा0 सदस्य विधान सभा से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी कार्रवाई करते राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग की गई । तद्नुसार मौजा-मझरिया, थाना नं0-188, खाता नं0-146 (गैरमजरूआ आम) खेसरा नं0-631 की चौड़ाई प्रश्नगत जगह पर 25 कड़ी है, जिसमें 10 कड़ी चौड़ा एवं 150 कड़ी लम्बा भूमि अतिक्रमित है । अतिक्रमण खाली कराये जाने हेतु अतिक्रमण वाद सं0-2/21-22 के तहत प्रपत्र-01 में नोटिस निर्गत किया गया है । उक्त अतिक्रमण वाद के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को खाली करा लिया जायेगा ।

3. उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मंत्री जी स्वीकारे हैं कि वह रोड अतिक्रमण है । हम जानना चाहेंगे कि मंत्री जी उस रोड को कब तक खाली करायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, एकदम अप्रैल, मई, जून तीन महीने में पूरे बिहार का जो अतिक्रमण वाद चल रहा है, वह खाली करा दिया जायेगा । इनका दो महीने का समय हम लिये हैं ।

अध्यक्ष : अब धन्यवाद दे दीजिये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, अगर दो महीने, तीने महीने के अंदर अगर खाली नहीं होता है तो क्या मंत्री जी सी0ओ0 पर कार्रवाई करना चाहेंगे ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : बिल्कुल दो महीने के अंदर खाली हो जायेगा और आपके सामने खाली होगा ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह । श्री जनक सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-2255 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0-116, तरैया)

स्थानांतरित हुआ । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, यह प्रश्न विद्युत शवदागृह बनाने का था और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यह मेरे नगरीय क्षेत्र में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है तो क्या इस प्रश्न को स्थानांतरित करके पंचायती राज विभाग इसका उत्तर देगा ?

अध्यक्ष : स्थानांतरित हो गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2256 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र सं0-49, अररिया)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर तो इसमें दे ही दिये हैं और कुछ बताना है?

अध्यक्ष : उत्तर आपका आया नहीं है, बता दीजिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, क्रमांक 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

राज्य प्रमुख बिहार EESL का पत्रांक-652, दिनांक-09.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, अररिया क्षेत्रान्तर्गत EESL स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु EESL से दिनांक- 06.02.2018 को एकरारनामा किया गया है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, अररिया में EESL द्वारा अब तक 164 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जा चुका है । शेष स्ट्रीट लाईट मई, 2022 तक अधिष्ठापन कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आबिदुर रहमान : हुजूर यह तीन साल हो चुका है । सरकार इसको कब तक लगा देने की कोशिश करेगी ?

अध्यक्ष : कब तक ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम तो इन्कार नहीं किये हैं कि तीन साल नहीं हुआ है । हम तो कह रहे हैं कि मई 2022 तक शेष सभी का अधिष्ठापन कर देंगे और माननीय विधायक जी से स्वीच ऑन भी करवायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आबिदुर रहमान : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2257 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत कामता अन्तर्गत ग्राम कामता में 75 सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा निर्गत है ।

शेष परिवारों की जांच हेतु राजस्व अधिकारी, कलेर की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया है । जांच दल से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में शीघ्र ही नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इस सवाल का जो जवाब दिया गया है उसमें आंशिक स्वीकारात्मक है और इसमें कहा गया है कि वास एवं खेती योग्य जमीन नहीं रहने के कारण पर्चा और उनको बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है । लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वहां अभी भी करीब सैकड़ों गरीब लोग बसे हुए हैं, वे मकान बनाकर बसे हुए हैं महोदय और डी0एम0 ने जो वहां जल-जीवन-हरियाली के लिये जो जमीन तय किये हैं, उसमें 2996, 2997 प्लॉट में कई खाता है, कई खेसरा नंबर है । उसमें कुछ खेसरा नंबर की जमीन को जल-जीवन-हरियाली के लिये डी0एम0 ने चिन्हित किया है लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लॉट में, बहुत सारे खेसरा नंबर में वे गरीब लोग बसे हुए हैं और कुछ दबंगों के द्वारा, जमीन में खेती हो रही है, खेती करवाया जा रहा है । हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जो बसे हुए हैं उनको आप पर्चा देंगे और दबंगों द्वारा जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है उससे बेदखल करके जो भूमिहीन लोग हैं । वह भूमिहीन लोग जो बसे हुए हैं दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ी जाती के हैं उन लोगों को जमीन बंदोबस्त करायेंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है वह जल-जीवन-हरियाली के तहत यह जमीन को सुरक्षित रखा गया है । अगर माननीय सदस्य ने कहा है कि उस जमीन पर लोग बसे हुए हैं और वहां बसना चाहते हैं तो जल-जीवन-हरियाली के लिये जितना जमीन एक्वायर किया गया होगा, निचली जमीन जो होगी उसके अलावे कोई जमीन वहां होगा तो निश्चित रूप से अगर वे लोग आवेदन देते हैं कि मुझे उसी जगह पर चाहिये तो कोई अतिक्रमण किया है तो खाली कराकर उन गरीब लोगों को जमीन दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : श्री राजेश कुमार सिंह ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, बसे हुए हैं, बाजाब्ते मकान बनाकर के बसे हुए हैं और बहुत सारी जमीन पर खेती हो रही है

अध्यक्ष : हो गया अब बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2258 (श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-104, हथुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड फुलवरिया के वंशीवतराहा, मिश्रवतराहां ग्राम से प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लाढ़पुर, प्रखण्ड फुलवरिया की दूरी लगभग 6.5 कि0मी0 एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बड़कागांव प्रखण्ड हथुआ लगभग 6 कि0मी0 की दूरी पर है ।

प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लाढ़पुर में डॉ0 कमलेश प्रसाद सिंह एवं पशु चिकित्सालय, बड़कागांव में डॉ0 रंजीत कुमार कार्यरत हैं । इस प्रकार वंशीवतराहा, मिश्रवतराहां ग्राम के पशुपालकों को पशु चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा रही है ।

विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त ग्राम वंशीवतराहा एवं मिश्रवतराहां में नया पशु चिकित्सालय स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, जवाब मिला है लेकिन कब तक पूरा किया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : महोदय, इसको विभाग के द्वारा समीक्षा के उपरांत वंशीवतराहा एवं मिश्रवतराहां में नये अस्पताल बनाने का निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न-4/राहुल/17.03.2022

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, सुनाई नहीं दिया कुछ साफ-साफ ।

अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं कि कब तक, आपके पास जवाब नहीं है क्या ?

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : विभाग के द्वारा समीक्षा के उपरांत हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया जाएगा क्योंकि वहां पर साढ़े 6 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल ऑलरेडी उपलब्ध है। हॉस्पिटल बनाने का विभाग के द्वारा जो...

श्री राजेश कुमार सिंह : मंत्री जी को जानकारी नहीं है महोदय ?

अध्यक्ष : पूरी जानकारी है ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : प्रस्ताव जो है 7 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है विभाग के द्वारा, साढ़े 6 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल बना हुआ है और वहां पर...

अध्यक्ष : आप पूरा जवाब पढ़ दीजिये । वह आपको कह रहे हैं जानकारी नहीं है । पूरा जवाब लेकर आए हैं, पढ़िये ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड फुलवरिया के वंशीवतराहा, मिश्रवतराहां ग्राम से प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लाढ़पुर, प्रखण्ड फुलवरिया की दूरी लगभग 6.5 कि0मी0 एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बड़कागांव प्रखण्ड हथुआ लगभग 6 कि0मी0 की दूरी पर है ।

प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लाढ़पुर में डॉ0 कमलेश प्रसाद सिंह एवं पशु चिकित्सालय, बड़कागांव में डॉ0 रंजीत कुमार कार्यरत हैं । इस प्रकार वंशीवतराहा, मिश्रवतराहां ग्राम के पशुपालकों को पशु चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा रही है ।

विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त ग्राम वंशीवतराहा एवं मिश्रवतराहां में नया पशु चिकित्सालय स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिये सकारात्मक जवाब है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, इसमें दिया गया है कि मिश्रवतराहां और वंशीवतराह ग्राम से पूर्व में बड़का गावं 6 किलोमीटर है और उत्तर में लाढ़पुर 6 किलोमीटर है और वंशीवतराह, मिश्रवतराहां से दक्षिण 8 किलोमीटर की दूरी है तो 8 और 6 कुल 14 किलोमीटर हो जाता है तो 14 किलोमीटर मवेशी को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है तो मंत्री जी क्या वहां अस्पताल बनवाने का विचार करते हैं ?

अध्यक्ष : विचार किया जायेगा, बोल दिये हैं आपको, सकारात्मक जवाब है । अब श्रीमती रश्मि वर्मा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2259 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र संख्या-03, नरकटियागंज)

श्रीमती रश्मिी वर्मा : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : कृषि विभाग, माननीय मंत्री जी जवाब पढ़ दीजिये । आज भी शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया है । दो विभागों में थोड़ा कम है बाकी सबका शत प्रतिशत जवाब है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार को भी बधाई दीजिये ।

अध्यक्ष : सरकार की सजगता से शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आता है । सरकार को हम मोटिवेट करते रहते हैं, हम हतोत्साहित, डिमोरलाईज नहीं करते हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, मैं जवाब पढ़ देता हूं ।

अस्वीकारात्मक है । पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी, 2022 में खड़ी फसल में

वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान प्रतिवेदित नहीं है । आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधान के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर कृषि इनपुट अनुदान देय है । इसलिए जब नुकसान नहीं हुआ है, मतलब प्रतिवेदित भी नहीं हुआ है और जिलाधिकारी से हम लोग प्रतिवेदन मंगाते हैं और उसमें 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान नहीं है इसलिए यह इनपुट अनुदान वहां देय नहीं है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, यहां पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और पुन: मैं सर्वेक्षण की मांग करती हूं ताकि किसानों को सही क्षतिपूर्ति मिल सके, मुआवजा मिल सकते ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2260 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र संख्या-12, नरकटिया)</u>

(मुद्रित उत्तर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड की जीतपुर पंचायत के ग्राम जोलागांवा अंतर्गत वर्ष 2014-15 में किए गए एकरारनामा से सौर चालित मिनी जलापूर्ति योजना अंतर्गत 22 अदद लक्ष्य के विरुद्ध 16 अदद स्टैण्ड पोस्ट एवं 5 अदद लक्ष्य के विरुद्ध 4 अदद भैट का निर्माण कार्य नवंबर, 2016 में कराया गया। वर्तमान में 3 अदद भैट एवं 12 अदद स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2014-15 में एकरारनामा हुआ लेकिन वर्ष 2014-15 में एकरारनामा के बाद 6 महीने चलने के बाद जितनी भी जल मीनार थी वह चलनी बंद हो गई । जब प्रश्न विधान सभा में किया गया तो फिर अभी काम लगा है, अभी चालू हुई है...

अध्यक्ष : आपके प्रश्न की ताकत दिखायी पड़ी न, शाबाशी दीजिये, मंत्री जी की संवेदनशीलता को, सरकार की सजगता को शाबाशी दीजिये ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक जो इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, क्या मंत्री जी ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को सही उत्तर दिया है जो स्थिति वर्तमान में है और बाकी जो जीर्णोद्धार लायक नहीं हैं उसको नहीं करा रहे हैं। अभी यह मिनी जलापूर्ति योजना सोलर प्लांट से चल रही है जो काम लायक नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बना रहे हैं जो अभी चल रहा है शेष खत्म हो चुका है ।

जो चल रहा है उसकी हम मरम्मत कराकर जब तक चालू होगा हम करेंगे । उस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो एकरारनामा में तय हुआ है ठेकेदार से कि हम पांच साल या सात साल जो भी एकरारनामा हुआ है तो उसमें तो सरकार का जो पैसा लगा इसमें जो राशि का बंदरबांट हुआ, पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसको कैसे रिक्वरी करायेंगे?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : सरकार का जो पैसा लगा है संवेदक ने उतना काम किया है, शेष पैसा उसको नहीं मिला है वह जो हम 16 अदद स्टैण्ड पोस्ट दिये थे उसमें से मात्र 12 काम कर रहा है 4 नहीं का कर रहा है तो उसको पैसा उसको नहीं मिला है । इसीलिए कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह तय था एकरारनामा के पांच साल या सात साल हम पानी देंगे तो इस पर माननीय मंत्री जी बतायें । पैसा तो वह ले लिया, ठेकेदार लेकर फरार हो गया लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो ऐसे पदाधिकारी पर, इसी तरह का मामला एक बनकटवा में है जल मीनार करोड़ों की बनी हुई है...

अध्यक्ष : चलिये आपके तीन पूरक हो गए ।

श्री शमीम अहमद : जी, एक और मामला है सर, यह बनकटवा का मामला है करोड़ों की जल मीनार बनी है लेकिन वहां भी पानी, वर्ष-2014 में बना लेकिन अभी तक...

अध्यक्ष : इससे जुड़ा हुआ नहीं है । श्री संजय सरावगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2260 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र संख्या-12, नरकटिया)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, दरभंगा द्वारा अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा एवं अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को दरभंगा शहर स्थित अतिक्रमित तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

(3) जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत शहर के सभी तालाबों को नियमानुकूल अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु समाहर्ता, दरभंगा द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया है एवं समय-समय पर समाहर्ता के द्वारा तत्संबंधी समीक्षा की जाती है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मैंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली में जो है पूरे राज्य के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया था, माननीय मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है । फिर मैंने कहा कि जो है इसमें कि 46 तालाब जो दरभंगा शहर में सरकारी तालाब हैं उसमें अभी तक कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है और निदेशित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, निदेशित तो 3 साल पहले...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय । जनता में संदेश भी जाना चाहिए न कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पता कैसे चलेगा लोगों को । इसीलिए थोड़ा विषय बताना पड़ता है तो माननीय मंत्री जी ने कहा निदेशित किया गया है । निदेशित तो 3 साल पहले किया गया जब जल-जीवन-हरियाली योजना प्रारम्भ हुई और विभाग को पूरे जिले से रिपोर्ट आई है कि 34 हजार जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है यह विभाग का आंकड़ा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि दरभंगा शहर में, अगर 34 हजार पूरे बिहार में जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया तो क्या दरभंगा शहर के पांच भी जल निकाय आप बताएंगे इन 34 हजार में जो अतिक्रमण मुक्त अभी तक हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : दरभंगा शहर में 46 पोखर के अतिक्रमण वाद संख्या की जानकारी मिली है जिसमें से 7 पोखरों पर कार्रवाई की भी गई है, खाली नहीं हुए हैं और पूरे दरभंगा शहर में इनके जितने पोखर अतिक्रमित हैं अप्रैल, मई और जून महीने में इनके सामने तुड़वाया जायेगा बाकी का अतिक्रमण वाद हम केस भी बता रहे हैं दिग्घी पोखर, 2019-20, गंगा सागर पोखर, 03/2014-15, 19/2021-22, शुभंकरपुर हल्दी पोखर, 17/2019-20, लाल पोखर, 2019-20, 2021-22, मिर्जा खां तालाब 23/2021-22, सहलागंज पोखर, 20/2021-22, ताजपुर बिशनपुर पोखर, 2019-20 और 2022 यानी सभी को अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है बाकी पर नापी चल रही है और इनके क्षेत्र का जो पोखर है निश्चित रूप से अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीने के अंदर इनके सामने, इनको रखकर के ही खाली कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिये बहुत अच्छा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब तो इतना सकारात्मक जवाब दिए हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इन तालाबों में जो है तालाब की जमीन का इनके अधिकारी जो दाखिल-खारिज करके रसीद जनता को दे दिये हैं और इन्होंने कहा है कि 46 तालाब को मई-जून में अतिक्रमण मुक्त करा देंगे, मेरे सामने करायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी अगले सदन में इन 46 पोखर को अतिक्रमण मुक्त करायेंगे, तीन महीने और हम समय दे रहे हैं, ये तो दो-तीन ही महीना मांगे हैं तो क्या इन 46 पोखर में जो दाखिल-खारिज अधिकारी कर दिया है नंबर एक उसके दाखिल-खारिज को समाप्त करके अधिकारी पर कार्रवाई और 46 पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराकर अगले सदन में 46 पोखर के अतिक्रमण मुक्त की रिपोर्ट विधान सभा में पेश करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य भी विगत 4-5 बार से विधायक हैं वहां कंटिन्यू रह भी रहे हैं, शहर में ही रहते हैं तो कैसे अतिक्रमण हो गया, क्यों हो गया यह सब जानकारी तो मुझे प्राप्त कर ही लेनी है और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारी जमाबंदी अगर पोखर की कर दी गई है तो वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, खाली भी करायेंगे और इनके सामने में ही खाली करायेंगे।

अध्यक्ष : चलिये अब हो गया ।

टर्न-5/मुकुल/17.03.2022

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अगले विधान सभा में । अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बता दिया है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, नहीं ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये अगले सत्र में विधान सभा में रिपोर्ट करेंगे, जब ये अप्रैल-मई का समय दे रहे हैं और अगला सत्र तो जुलाई-अगस्त में होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य को सत्र शुरू होने से पहले ही सूचना दे देंगे, बता देंगे ।

अध्यक्ष : सरावगी जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये आपको सूचना दे देंगे, ठीक है ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका । महबूब जी, नहीं । बढ़ते चलिए, आपका प्रश्न अभी नहीं है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : 5 हजार एकड़ में तब्दील हो गई है, उसका क्या होगा महोदय ।

अध्यक्ष : विजय कुमार खेमका जी की भी बात सुन लीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-2262 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0-62, पूर्णियां)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है । नगर निगम पूर्णिया के बोर्ड की दिनांक-29.11.2018 को आहूत बैठक में प्रस्ताव सं0-09 द्वारा 07 (सात) वेंडिंग जोन की स्वीकृति प्रदान की गई । इन 07 (सात) वेंडिंग जोन में से प्रारंभिक रूप से 02 (दो) वेंडिंग जोन की मापी उपरांत प्रस्ताव तैयार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नगर निगम पूर्णिया के ज्ञापांक-52, दिनांक-18.01.2019 एवं ज्ञापांक-117, दिनांक-06.02.2019 से कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल पूर्णिया को भेजा गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है । पुनः नगर निगम पूर्णिया के पत्रांक-360, दिनांक-05.03.2022 द्वारा स्मारित किया गया है । शेष 05 (पांच) वेंडिंग जोन एन0एच0 की भूमि में चिन्हित है, चूंकि वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च पथ विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है फलतः राष्ट्रीय उच्च पथ विस्तार कार्य पूर्ण होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी शहर के विधायक भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं । अध्यक्ष महोदय, यह ठेला, खोमचा और सब्जी विक्रेताओं का मामला है । अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया में नासवी द्वारा सर्वे करवाकर 2500 से ज्यादा फुटपाथी दुकानदार जो हैं उनको आई कार्ड दिया गया है । मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा भी है कि दिनांक-29.11.2018 को जो बोर्ड की बैठक हुई उसमें यह प्रस्ताव लिया गया कि वेंडिंग जोन का निर्माण करवाया जायेगा और आज वर्ष 2022 है, पांच साल बीत गये और वेंडिंग जोन जहां पर बनना है उसका एन0एच0 से एन0ओ0सी0 नहीं आ सका । जो नगर निगम के अधिकारी हैं वे एन0ओ0सी0 नहीं ले सकें तो अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि पांच साल बीत गये और एन0ओ0सी0 लेने में और कितना समय लगेगा ? महोदय, मेरा

दूसरा पूरक है कि ये जो गरीब फुटपाथी सब्जी विक्रेता जो दुकानदार हैं, जिनके लिए वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव लिया गया है यह कब तक बनेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने पूरक में भी स्पष्ट किया है कि वेंडिंग जोन के लिए जो प्रस्तावित जमीन है वह पथ निर्माण विभाग की है, राष्ट्रीय उच्च पथ की है और जब तक उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक उसमें वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सड़क मुख्य रूप से आवागमन के लिए है और पूर्णिया में फोरलेन का भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है उसके विस्तारीकरण का भी निर्माण कार्य चल रहा है । एक बार विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर शेष जो अगर इस तरह की जमीन वेंडिंग जोन के लिए मिलेंगे तो उसपर भी बन सकता है । वैसे मैंने अपने विभाग के सचिव और पथ निर्माण विभाग के सचिव के साथ बैठकर के पूरे बिहार में इस तरह के जितने भी स्थानीय नगर-निकाय के प्रस्ताव गये हैं जिसपर वेंडिंग जोन बनना है और वह पथ निर्माण विभाग के अधीन है उसपर विस्तार से विमर्श करके जो स्थान वे दे सकते हैं उसे लेने का प्रयास किया गया है और हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी विभाग की ओर से पत्र जा रहा है, अगर उनकी कोई खाली जमीन शहर में उपलब्ध है तो उसे वेंडिंग जोन के लिए उपलब्ध कराया जाय । महोदय, हमारी चिंता है और भारत सरकार की भी यह महत्वाकांक्षी योजना है और हम भी चाहते हैं कि ऐसे तमाम दुकानदार, कहीं-न-कहीं वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें हम पुनर्वासित कर सकें, जिससे कि जो अतिक्रमण की समस्याएं आती हैं, बार-बार अतिक्रमण के नाम पर जो अपने छोटे-मोटे दुकानदार भाई हैं उनको खदेड़ा जाता है । ये सारी जो अफरा-तफरी हैं ये समाप्त हों । हम कई स्तरों पर भी यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने नगर-निकाय के भी अगर पूरे राज्य में जहां-जहां जमीन है उसको भी जिलावार उपलब्ध कराया जाय और सत्र समाप्त होता है तो उसकी भी हम समीक्षा करके इन सारे मामलों को स्वयं गंभीरता से भी देखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इतना सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री गंभीर हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी आपके पड़ोसी भी हैं, आप मिलकर के इनसे बात कर लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : यह आपका लास्ट पूरक है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जी । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कहा है कि दो जो सड़क है, जोकि एन0एच0 की है उनकी मापी भी हो चुकी है और वह स्थान खाली भी है तो जिसका एन0ओ0सी0 आना है, दो का । सात जगह इन्होंने चिन्हित किया, पांच का विस्तारीकरण हो रहा है लेकिन दो जगह जहां खाली है क्या उसका एन0ओ0सी0 तुरन्त मंगवाकर वहां वेंडिंग जोन का निर्माण करवायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने या प्रश्नकर्ता ने जिन दो स्थानों की चर्चा की है उसका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल वह नहीं दे रहा है इसलिए महोदय, हमने अपने प्रधान सचिव को भी निदेशित किया है कि पथ निर्माण विभाग के सचिव एवं राष्ट्रीय उच्च पथ के जो मुख्य अभियंता हैं उनके साथ बातचीत करके उसका एन0ओ0सी0 प्राप्त करे और फिर अग्रेतर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0-2263 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु 45 लाख मे0 टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था । उक्त के आलेक में निर्धारित अवधि तक 4.97 लाख किसानों से 35.58 लाख मे0 टन धान की खरीदी की गई थी । 4.97 लाख किसानों में से 2.55 लाख गैर-रैयत किसान (51 प्रतिशत) से 15.97 लाख मे0 टन (51 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई थी एवं 2.42 लाख रैयत किसानों (49 प्रतिशत) से 19.61 लाख मे0 टन (49 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई थी ।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु 45 लाख मे0 टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त के आलोक में निर्धारित अवधि तक 6.42 लाख किसानों से 44.90 लाख मे0 टन धान की खरीदी की गई है । 6.42 लाख किसानों में 3.83 लाख गैर-रैयत किसानों (60 प्रतिशत) से 23.94 लाख मे0टन (53 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है एवं 2.59 लाख रैयत किसानों (40 प्रतिशत) से 20.96 लाख मे0 टन (47 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई ।

अर्थात स्पष्ट है कि गत वर्ष जिस अनुपात में रैयत एवं गैर-रैयत किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई थी लगभग उसी अनुपात में इस वर्ष भी किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है ।

इस वर्ष कृषि विभाग के पोर्टल पर इच्छुक किसानों के आवेदन में गैर-रैयत एवं रैयत किसानों का अनुपात 63:37 है एवं उसी अनुपात के लगभग (गैर-रैयत 60 प्रतिशत एवं रैयत 40 प्रतिशत) किसानों से पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा धान की अधिप्राप्ति की गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रश्न था, बटाइदारों से इस साल 60 प्रतिशत धान की खरीद हुई है, जो धान खरीद का लक्ष्य पूरा किया गया है उसमें । लेकिन हमारा सवाल था कि उसकी जांच होनी चाहिए । लेकिन जवाब में दो सालों का तुलनात्मक एक विवरण दे दिया गया है तो हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि यह सर्वविदित है कि पूरे तौर पर खाताधारियों से तालमेल करके बिचौलिये, ऑफिसर ये सब लोग मिलकर के...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम वही पूछ रहे हैं । ये मिलकर के और पूरे तौर पर जो किसानों को धान खरीद का लाभ मिलना है वे उस लाभ को ले लेते हैं और ऐसा 60 प्रतिशत जो है यह लाभ लूट लिया गया इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे कि नहीं हम इसके बारे में पूछना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, सहकारिता विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके पास अखबार का एक समाचार था और हमने उसपर स्पष्ट जवाब दे दिया है । अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बतायेंगे, किसी स्थान का जिक्र करेंगे और इन्होंने इसमें किसी स्थान का जिक्र नहीं किया है । अगर माननीय सदस्य किसी स्थान का जिक्र करेंगे तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी से उस स्थान की जांच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल पूरे बिहार के संदर्भ में है ।

अध्यक्ष : आप पार्टिकुलर किसी स्थान के बारे में बता दीजिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम वही बोल रहे हैं कि हमारा सवाल पूरे बिहार के संदर्भ में । बटाइदारों से कहीं खरीद नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : नहीं, आप पार्टिकुलर बताइये कारण के साथ, संभावना पर नहीं चलेगा ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल संभावना के आधार पर नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री राकेश कुमार रौशन ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बटाइदारों से खरीद नहीं हुई है और एक पंचायत में सरकार जांच करावे, बिहार के सभी जिलों में ।

अध्यक्ष : आप उस पंचायत का नाम देकर बता दीजिएगा ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी जिलों में एक-एक पंचायत का, मंत्री जी बतायें ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब दूसरा प्रश्न आ गया है । श्री राकेश कुमार रौशन ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय...

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा में पुरैना पंचायत का नोट कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : अब प्रश्न आगे बढ़ गया है, आप देर कर दिये हैं । वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप मंत्री जी को लिखकर के दे दीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये बिहार के कोई....

अध्यक्ष : अब हो गया, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-2264 (श्री राकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0-174, इस्लामपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चापाकलों के उखाड़-गाड़ की कोई योजना स्वीकृत नहीं है । जिसके फलस्वरूप माननीय सदस्य से प्राप्त सूची के आलोक में चापाकलों के उखाड़-गाड़ का कार्य नहीं किया जा सका ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया है कि उखाड़-गाड़ योजना के अंतर्गत चापाकल का हमलोगों से कार्यपालक अभियंता के द्वारा लिस्ट ली गयी थी, उस लिस्ट को लेने के बाद भी अभी तक उस चापाकल को गाड़ा नहीं गया है । महोदय, इस संबंध में माननीय मंत्री का जो जवाब आया है, उसमें ये कहते हैं कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । उसके बाद फिर आगे उन्होंने बताया है कि वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चापाकलों के उखाड़-गाड़ की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर तो संलग्न है । आप पूरक पूछिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, हम वही पूछ रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि वर्ष 2021-22 में चापाकलों के उखाड़-गाड़ की कोई योजना स्वीकृत नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के द्वारा कोई उखाड़-गाड़ की योजना स्वीकृत नहीं थी तो फिर इनके विभाग के पदाधिकारियों ने माननीय विधायकों से उखाड़-गाड़ चापाकल की लिस्ट क्यों ली, मेरा पहला पूरक प्रश्न यही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न-6/यानपति/17.03.2022

श्री रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न में मैंने कहा जो उखाड़ गाड़ की कोई योजना नहीं है, विभाग का था कि जो चापाकल खराब हो गया है उसको उखाड़ कर हटा देना है और जो ठीक होने लायक है उसको ठीक करना है । आपने जो सूची दी उसको तो गाड़ना नहीं था । जहां-जहां आपने सूची दी, जो खराब था उसको हमने उखड़वा दिया और जो मरम्मत लायक था उसको हमने मरम्मत कराया, उस जगह पर नया चापाकल नहीं देना था इसीलिए सरकार ने सबों के घर में नल-जल से पानी की व्यवस्था कर दी है तो चापाकल गाड़ने का कोई...

(व्यवधान)

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, यदि...

अध्यक्ष: उनका पूरक सुन लीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, यदि उखाड़ गाड़ की कोई योजना नहीं थी तो फिर विभाग के द्वारा संविदा क्यों कराया गया, क्यों कार्यपालक अभियंता ने संविदा कराया चापाकलों के गाड़ने के लिए...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री राकेश कुमार रौशन: और यदि संविदा कराया गया तो फिर क्यों नहीं चापाकल गाड़ा गया ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री रामप्रीत पासवान, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी, यह जो संविदा हुआ है वह 50 या कहीं 75 विशेष परिस्थिति में, आपदा के समय में जहां कहीं भी चापाकल की जरूरत होती है और गांव से यदि कोई सुदूर टोला है तो वैसी जगह पर हमलोगों ने चापाकल दिया है, इसकी संविदा है । उसमें यदि आपकी कोई ऐसी जगह होगी जो आप चाहते हैं वहां चापाकल हो...

श्री राकेश कुमार रौशन: महोदय, नहीं-नहीं, संविदा यह कराया गया था कि उखाड़ गाड़ योजना के अंतर्गत जो चापाकल खराब है उसकी मरम्मती के लिए संविदा था और संविदा

होने के बाद भी सरकारी पदाधिकारी ने चापाकल नहीं गड़ाया तो मेरा प्रश्न यह है कि संविदा क्यों किया गया और दूसरा मेरा...

अध्यक्षः बता तो दिए ।

श्री राकेश कुमार रौशनः दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है महोदय कि संविदा के बाद भी यदि सरकार के विभागीय पदाधिकारियों ने कार्य नहीं कराया तो क्या दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है ।

श्री रामप्रीत पासवान, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई ऐसा स्थान हमको चिन्हित करें जहां नहीं गड़ाया है तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्षः श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2265 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या-15, केसरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, केसरिया के पत्रांक-120, दिनांक-04.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि केसरिया नगर पंचायत अंतर्गत बस/ऑटो स्टैंड बनाने हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए कार्यालय के पत्रांक-361, दिनांक-17.07.2021 तथा पत्रांक-402, दिनांक-05.08.2021 के द्वारा अंचलाधिकारी केसरिया, पूर्वी चम्पारण से पत्राचार किया गया है ।

साथ ही जिला के दिशा बैठक दिनांक-10.09.2021 के कार्यवाही के कंडिका (11) में भी अंचलाधिकारी केसरिया को नगर पंचायत केसरिया में बस/ऑटो स्टैंड हेतु जमीन चिन्हित करने का निदेश दिया गया है । अंचल अधिकारी, केसरिया से भूमि संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ऐसे अंचलाधिकारी जो पिछले 7-8 महीनों से दिशा मीटिंग जिसके चेयरमैन एम0पी0 होते हैं, सेक्रेटरी डी0एम0 होते हैं, मेरे द्वारा भी पूछा गया है, ब्लॉक द्वारा भी पूछा गया है, एम0पी0, विधायक, ब्लॉक, डी0एम0 किसी से भी पूछने पर वह जमीन चिन्हित करके नहीं दे रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई करना पसंद करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, केसरिया में बस स्टैंड के निर्माण के लिए जो भूमि की आवश्यकता है, मैंने जिला पदाधिकारी को कहा है कि वह जमीन उपलब्धता को सुनिश्चित कराएं जिससे कि बस स्टैंड के निर्माण के लिए हम राशि तुरतं भेज सकें ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मैंने सीधे जिला पदाधिकारी को कहा ।

अध्यक्ष: श्री कुमार कृष्ण मोहन...

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, मेरा क्वेश्चन था कि क्या मंत्री महोदय अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे । 8 महीने से उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरा पूरक है कि कबतक जमीन चिन्हित करके, उपलब्ध कराके केसरिया में बस स्टैंड का काम शुरू होगा, आयेदिन वहां पर जाम लगता है, आयेदिन वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं ।

अध्यक्ष: श्री कुमार कृष्ण...

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूंगी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उनका ध्यान में ले लिए हैं, संज्ञान में । कार्रवाई होगी । श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

(व्यवधान)

बोले हैं कि हम दिखवा लेते हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, जब मैंने जिला पदाधिकारी को निदेशित कर दिया है और अंचल अधिकारी के पास, उससे तो हम सहयोग ले रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार से और जब हम सीधे जिला पदाधिकारी को अधिकृत किए हैं वह जमीन उपलब्ध कराएंगे, जमीन नहीं मिलेगा तो जमीन खरीदकर बनवाने की प्रक्रिया को आगे प्रारंभ करेंगे ।

अध्यक्ष: सकारात्मक जवाब है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: इसके लिए कार्रवाई करना उद्देश्य है या बस स्टैंड बनाना उद्देश्य है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: आग्रह है जल्दी करवाएंगे ।

अध्यक्ष: सकारात्मक जवाब है, बैठ जाइये । श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2266(श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र संख्या-216, जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः (1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदति किया गया है कि नगर परिषद् के वार्ड-06, 07, 08 एवं 27 में खाली और निचली भूमियों पर मुख्यतः बरसात के दिनों में अस्थायी रूप से जल-जमाव की स्थिति आंशिक क्षेत्रों में हो जाती है ।

(2) आंशिक अस्वीकारात्मक ।

पथ निर्माण विभाग, जहानाबाद द्वारा बनाए गए पथ को एन0एच0-83 में उत्क्रमित करने के पश्चात् पूर्व से बने तीनों कलवर्ट आंशिक रूप से चालू हैं । इन कलवर्टों से वार्ड संख्या-04, 05, 06, 07, 27 एवं 28 की जल निकासी होती है ।

बरसात पूर्व उक्त तीनों कलवर्टों की सफाई कराने की नगर परिषद्, जहानाबाद की कार्य योजना बनाई गई है तथा उक्त कार्य हेतु एन0एच0-83 से संबंधित कार्यालय से समन्वय का अनुरोध किया गया है । कलवर्ट सफाई कार्य के उपरान्त जल निकासी में अपेक्षित सुधार किया जा सकेगा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, इसमें है महोदय, चूंकि हम नगर परिषद् क्षेत्र के करीब आधा दर्जन वार्ड में जल-जमाव की स्थिति सालों भर रहती है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जहानाबाद के माध्यम से जो सरकार को जवाब आया है उसमें आंशिक रूप से जल-जमाव की स्थिति को स्वीकारा है लेकिन अभी भी हम सैकड़ों भूमि में वहां जल-जमाव की स्थिति है और आधा दर्जन से अधिक वार्ड में पूरी तरह पानी भरा रहता है । हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि चूंकि सरकार एक तरफ नगर परिषद् का विस्तार कराना चाहती है, दूसरी तरफ नगर एवं आवास विभाग की जो मूल सुविधा है, नगर परिषद् क्षेत्र में वह वहां उपलब्ध नहीं है तो हम चाहते हैं कि जिन वार्डों में

जल-जमाव की स्थिति है उसको कबतक निजात दिला पाएंगे माननीय मंत्री महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, इनके प्रश्न का दो खंड है एक जो राष्ट्रीय उपतथ्य है के द्वारा कलवर्ट है, बना हुआ है उससे पानी का निकास होता है । इन्होंने दो चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, एक तो इसकी पूरी सफाई हो जाय जिससे कि जो उसके प्रवाह का वॉल्यूम है वह पूरी तरह जल निकले और इन्होंने एक बात का और ध्यान दिलाया है कि उसको हो सकता है कि अपग्रेड करना पड़े क्योंकि काफी पहले वह बना होगा । सड़क भी जब विभागीय पथ होगी अब तो वह एन0एच0 हो गया है । उसके लिए भी हम कहे हैं विभाग को दिखवाने के लिए कि जो उसका अभी वर्तमान में कलवर्ट है उससे काम चलेगा या नहीं । अगर सफाई हम बेहतर ढंग से करा दें तो जल की निकासी बेहतर ढंग से होगी कि नहीं । अगर लगेगा कि वह पर्याप्त नहीं है, जो नगर की स्थिति है या जो जल-जमाव की स्थिति है, अगर वह पर्याप्त नहीं है तो फिर विभागीय अधिकारियों से बात करके उसको कैसे हम अपग्रेड करें उसको निकासी का जो वॉल्यूम है, उसको हम कैसे बढ़ाएं इसपर हम चिंतित हैं, उसको हम करेंगे क्योंकि हम जहानाबाद गए थे तो जानकारी मिली थी और व्यक्तिगत तौर पर माननीय विधायक जी ने हमें कहा भी है तो हम उसको गंभीरता से लेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, उसको...

अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: बोलिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: उसको सफाई से नहीं होगा उसको नया बनाना ही पड़ेगा चूंकि सड़क विस्तार के समय में कलवर्ट विस्तार का कुछ ध्यान नहीं रखा गया है, वह जाम रहता है बराबर और नगर कर्मी, सफाई कर्मी उसकी सफाई आंशिक रूप से करते हैं पर पानी पूरा नहीं निकल पाता है । हम चाहते हैं कि विभाग उसको नये तरह से बनाकर उसको...

अध्यक्ष: ठीक है, आप जानकारी दे ही दिए हैं । माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा । पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2267 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38, झंझारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: स्वीकारात्मक । नगर पंचायत, झंझारपुर अन्तर्गत कुल चार फेज में 3591 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 1147 लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया जा चुका है । वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के तहत राशि भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें नगर पंचायत, झंझारपुर को खाता पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) पर मैप करा लिया गया है । जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो 710 लाभार्थियों का तत्काल भुगतान किया जाएगा, जो निम्नवत् है:- वार्ड सं0-1 में 30, वार्ड सं0-2 में 75, वार्ड सं0-3 में 80, वार्ड सं0-4 में 25, वार्ड सं0-5 में 25, वार्ड सं0-6 में 40, वार्ड सं0-7 में 10, वार्ड सं0-8 में 45, वार्ड सं0-9 में 15, वार्ड सं0-10 में 80, वार्ड सं0-11 में 40, वार्ड सं0-12 में 50, वार्ड सं0-13 में 45, वार्ड सं0-14 में 40, वार्ड सं0-15 में 75 एवं वार्ड सं0-16 में 35 । तत्पश्चात् शेष बचे 1734 लाभार्थियों को भी आवास का लाभ देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है । माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना । तीन वर्षों से झंझारपुर नगर पंचायत में 2444 आवास को स्वीकृति नहीं दी गयी है और अभी उत्तर में आया है कि 710 लाभार्थियों का तत्काल भुगतान किया जाएगा । मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि 710 लाभार्थियों का कबतक भुगतान हो जाएगा और शेष जो 1734 लाभुक हैं क्या उनकी पहचान कर ली गयी है और क्या उनकी जियो टैगिंग की कार्रवाई की जा चुकी है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो खंडों में यह प्रश्न उन्होंने किया है तो 710 लाभार्थियों का भुगतान मुझे लगता है कि इसी महीने में कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो शेष 1734

लाभार्थी हैं इसे भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, एक बड़ा आयोजन करके केंद्रीकृत पूरे बिहार में मुझे लगता है कि लगभग 40 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का एक साथ हम उन्हें सैंक्शन लेटर देनेवाले हैं तो उस समारोह में ये 1734 भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि 1734 बेनिफिशियरी की क्या लिस्ट बन चुकी है मुझको सिर्फ इतना उत्तर चाहिए, क्या पहचान हो गई है उनकी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: हां महोदय, पहचान हो गई है, विभाग से आज भी सुबह बात हुई है वह पहचान हो गई है और एक साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि अप्रील प्रथम सप्ताह में ही यह आयोजन करके सेंक्शन लेटर हम दे देंगे ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की चर्चा कर दी है क्योंकि यह क्वेश्चन तो केवल झंझारपुर का था उसी से एक पूरक निकलता है कि क्या दरभंगा शहर की भी जो सूची है लगभग 2000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास की क्या वह भी उस 40000 में समाहित है । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: श्री संतोष कुमार मिश्र ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

(व्यवधान)

टर्न-7/अंजली/17.03.2022

(क्रमशः)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री महबूब आलम, श्री अरूण सिंह, श्री महा नंद सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव, श्री सुदामा प्रसाद, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं श्री अमरजीत कुशवाहा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 172 (3) एवं 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जाएंगे । माननीय सदस्या, श्रीमती गायत्री देवी ।

(व्यवधान)

शून्यकाल

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडन्तर्गत विसनपुर पंचायत के विसनपुर से मुशहरटोली तक की कच्ची सड़क है जो बहुत खराब है आमलोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ।

अतः सरकार से मांग करती हूं कि विसनपुर से विसनपुर मुशहरटोली तक पक्की सड़क का निर्माण करावें ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंडान्तर्गत मौजा लाभगांव में राजकिशोर व विश्वनाथ सिंह की जमीन पर 700 से अधिक परिवार 35 वर्षों से बसे हुए हैं, किंतु वासगीत पर्चा नहीं मिला है ।

मैं सरकार से सभी परिवारों को वासगीत पर्चा देने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जयनगर अनुमंडल का एक भाग स्नातकस्तरीय डी0बी0 कॉलेज में नामांकित 6000 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई जर्जर भवन में होती है । 17 दिसंबर 2021 को उसी परिसर से माननीय मुख्यमंत्री ने जीर्णोद्धार हेतु शिक्षा मंत्री से पहल की बात कही थी । सरकार से जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग करती हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वीचंपारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय स्थित राजाराम उच्च विद्यालय प्लस-2 नहीं रहने के कारण वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 किलोमीटर मोतिहारी जाना पड़ता है ।

सरकार से मांग करता हूं कि विद्यालय को प्लस-2 में उत्क्रमित करावें ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर के नगर परिषद् अंतर्गत अस्थायी कार्यरत सफाई कर्मियों का वेतन लगभग 6700/- से 8000/- तक ही मासिक सीमित है ।

मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि इस महंगाई के दौर में उनका वेतन 20000/- (बीस हजार) हो ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-बाजपट्टी के ग्राम निमाही से बाचोपट्टी होते हुए सोनमनी टोल तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, अस्तु जनहित में पुन: सड़क निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला में प्रखंड कौआकोल स्वास्थ्य उपकेंद्र, विष्णुपुर का गिरकर नष्ट हुए भवन को जनहित में नए भवन का निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री रामचंद्र प्रसाद ।

श्री रामचंद्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगाए गए राजकीय नलकूप वर्षों से बंद हैं जिसके कारण किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाइयां होती हैं ।

अत: मैं सरकार से बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाये गये पाईपलाईन से घरों में किये गये कनेक्शन से

पेयजल की आपूर्ति 90 प्रतिशत ठप है, शहर में अभी से ही पेयजल का हाहाकार मचा हुआ है, अविलंब विभाग पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड के नदवां रेलवे स्टेशन के समीप रेल फाटक नहीं होने से वहां के लोगों को काफी कठिनाई होती है, मैं जनहित में उक्त स्थान पर रेल फाटक बनवाने हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग करती हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना-गया एस.एच. पर शहर तेलपा बाजार में ए.पी.एच.सी. में तीन डॉक्टर समेत कई स्वास्थ्य कर्मी बहाल हैं । अभी तक 24x7 सेवा बहाल नहीं है जिससे करीब 50 हजार आबादी प्रभावित है । शहर तेलपा ए.पी.एच.सी. में 24x7 सेवा बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में समान शिक्षा संविधान प्रदत्त सबका मौलिक अधिकार है परन्तु राज्य में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में भिन्न-भिन्न शिक्षा बोर्ड है जो कि मौलिक अधिकार का हनन है ।

अत: सरकार से राज्य के सभी प्राइवेट एवं सरकारी विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम लागू करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के घोरघट जहां 1934 में गांधीजी को लाठी भेंट की गई थी । पिछले 4 वर्षों से लाठी महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है । उक्त महोत्सव बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करता है ।

अत: उक्त महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलवाने की मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र में सभी सरकारी राशि से हो रहे कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को दंडित करने का सरकार निदेश जारी करें ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखंड में बौरी आहर उड़ाही योजना का शिलान्यास दिनांक-26.10.2019 को हुआ था । शिलापट्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी लिखा है । उक्त आहर में काम शुरू भी नहीं हुआ है और कार्य पूर्ण बताया जा रहा है । स्थल जांच कर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला-रोहतास अंतर्गत इटिम्हा नोनार पथ (PWD) जो इटिम्हा गांव के घनी आबादी के बीचों-बीच से गुजरती है । जिस कारण अक्सर जाम की

समस्या लगी रहती है । मैं जाम की समस्या से मुक्ति हेतु बाईपास बनाने की मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बौंसी प्रखंड में सिंकदरपुर पंचायत के गोलहट्टा गांव के जानकी टोला के पास जोर में पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूं ताकि अनेकों गांव के राहगीरों को झारखंड सीमा तक जाने में आसानी होगी ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत SH-75 पर स्थित टेकटार गांव जो सिंहवाड़ा प्रखंड में अवस्थित है और बाजितपुर गांव सहित अनेकों गांव जो केवटी प्रखंड में अवस्थित है और इन दोनों गांवों के बीच से अधवारा समूह नदी गुजरती है । जिस नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक है, इस हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के कस्माबाद एवं शाहाबाद दियारा थाना अकबरनगर प्रखंड सुलतानगंज में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज मंजिल ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी शून्यकाल था ।

अध्यक्ष : आपका शून्यकाल अमान्य किया गया है । बैठ जाइए ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा उर्दू TET अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत कटऑफ कम करके रिजल्ट जारी करने के आदेश के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया गया । उर्दू TET अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प0चंपारण के नौतन प्रखंड के खापटोला, श्यामपुर, शिवराजपुर गांवों में जहरीली शराब से 9, 14 एवं 15 मार्च, 2022 को हुई मौतों के जिम्मेवार पुलिस-राजनेता-शराब माफिया गठजोड़ की जांच हो और मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला अंतर्गत दारोगा प्रसाद राय कॉलेज कैंपस में कॉलेज के ही कुछ कमरों में केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण कॉलेज का पठन-पाठन बाधित होता है ।

अतः इसे अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराकर स्थानांतरित करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, आरा से मोहनियां एन॰-30 पर ट्रामा सेंटर नहीं होने से एन॰एच॰ पर दुर्घटनागस्त हुए मरीजों को काफी कठिनाई होती है, सरकार मलियाबाग में जमीन का अधिग्रहण कर ट्रामा सेंटर का निर्माण करावें ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत बंगडीहा गांव में सड़क पर जल-जमाव के कारण काफी कठिनाई होती है ।

अतः सरकार से बंगडीहा गांव में बुद्धू पासवान के घर से मनोज दास के घर तक पानी निकासी हेतु पक्की नाला निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, वृद्धा पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन बिहार राज्य में 500/- प्रति माह मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में एक-एक हजार रुपए प्रति माह सरकार देती है । अतः बिहार राज्य में भी उक्त पेंशन को 500/- से बढ़ाकर 1500/- प्रति माह देने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज शहर जिला बनने के सभी अहर्ता को पूरा करता है । अररिया के जिला पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकार के अवर सचिव सामान्य प्रशासन एवम् मुख्यमंत्री सचिवालय पटना सामान्य प्रशाखा से रिपोर्ट 2015 में भेजी जा चुकी है । सदन से फारबिसगंज अनुमंडल को जिला बनाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के 150 सहित जिला में 766 भूमिहीन परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वास भूमि हेतु स्वीकृति होने के बावजूद वर्ष 2021-22 समाप्त होने पर भी चिन्हित भूमिहीन को भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

अतः मैं सरकार से पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के 150 सहित जिला में 766 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के मनिहाट से चपरी, नाननपैर, गौरा गांव होत हुए एस.एच.-84 को जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर हो

चुकी है, आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध है, जनहित में उक्त पथ का अविलंब पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड में झखरा REO रोड से झखरा गांव होते हुए घोड़हन देवी स्थान तक पक्की सड़क जनहित में अति आवश्यक है ।

अत: मैं सदन से उपरोक्त सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं रहने के कारण आम जनता को राजकीय चिकित्सा में कठिनाई होती है, साथ भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एवं पर्यटन क्षेत्र भी है ।

मैं उपरोक्त अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लक बैंक की स्थापना की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से लोहार जाति का अस्तित्व संकट में है । मैं सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षोपरांत पुन: मजबूती से SC में पक्ष रखने की मांग करता हूं ।

महोदय, हजारों लड़के जो नौकरी कर रहे हैं रोड पर चले आएंगे महोदय, कृपया इसको सरकार संज्ञान में लें ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते राशन के साथ खाने के तेल, नमक, दाल और चीनी, साबूत देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैथिली भाषा राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है । मैथिली लिपि भी है इसलिए बिहार गीत के अंतर्गत मैथिली गीत को भी सम्मिलित किए जाने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा में हजारों एकड़ में लगी फसल को नीलगायों एवं जंगली सूअरों के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है । जिससे क्षेत्र के तमाम किसान परेशान रहते हैं ।

अत: क्षेत्र के तमाम किसानों को नीलगायों एवं जंगली सूअरों के उत्पात से निजात दिलाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री जयप्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के दरगाहीगंज पंचायत स्थित बहरदार टोला पथराहा से सिमरबनी नहर के पश्चिमी कैनाल

पर प्राथमिक विद्यालय चतुरी साह टोला फरही तक सुलभ संपर्कता योजना के तहत सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, हरिराम कॉलेज मैरवा एकमात्र स्नातक कॉलेज है जहां गुठनी, दरौली, नौतन तथा मैरवा प्रखंड के छात्र पढ़ने आते हैं । स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से गरीब, कमजोर तबकों के छात्रो को उच्च शिक्षा पाना संभव नहीं है ।

अतः हरिराम कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की जाए ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड अंतर्गत अनैला निवासी श्री सुबोध कुमार चालक को गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया । इस निर्मम हत्या की मैं निगरानी से जांच करा दोषी पर कार्रवाई एवं परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत कनौसी पंचायत के रामपुर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मैं राज्य सरकार से उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर, मोरवा एवं पटोरी प्रखंडों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का इंडियामार्क हैंडपंप दर्जनों की संख्या में बंद पड़े हुए हैं ।

जनहित में बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए बंद पड़े हैंडपंप को शीघ्र चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी प्रखंड के दामोदरपुर, पठान टोली, साहू कॉलोनी, जयप्रकाश नगर, जगदम्बानगर, हीरानगर सहित दर्जनों कॉलोनी के अतिवृष्टि के कारण जल-जमाव होने से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं । सरकार से जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने की मांग करता हूं

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लखनी चंवर के जल-जमाव से हजारों एकड़ में लगी फसल का हर साल नुकसान होता है । किसानहित में जल निकास की व्यवस्था कराए जाने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण बेतिया जिलान्तर्गत नरकटियागंज के नगर परिषद में अवस्थित सरकारी अस्पताल के A.N.M. Centre का भवन पिछले 2 वर्षो से बनकर तैयार है जिसका प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है । महिलाओं के हित में सदन के माध्यम से सरकार से अविलंब इसे प्रारंभ कराने की मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला की महत्वपूर्ण सड़कें यथा नौवागढ़ी से एन.एच.-333 भाया जवायद एन.एच.-80 के सिंधिया से मानगढ़ तथा एन.एच.-80 के लालखां से बसौनी भाया बंगलवा तक की ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-पचाढ़ी के मालती देवी, राशन कार्ड सं0-10130030085043520020 का ही दूसरा राशन कार्ड पुत्र के नाम बनाकर मालती देवी का राशन बंद है जिससे भुखमरी की स्थिति है ।

अत: मालती देवी को राशन देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अब्बू महमदपुर में आंगनबाड़ी सेविका इशरत परवीन की मंगलवार रात को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उनके परिजन को मुआवजा देने और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर : अध्यक्ष महोदय, जिला नवादा के अनुमंडल रजौली से भाया फतेहपुर वजीरगंज होते हुए जिला गया के लिए बुडको द्वारा चलने वाली दो बसों के परिचालन की मांग करता हूं ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/17-03-22

अध्यक्ष: शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय, आरा जिला के कोईलवर में एक मजदूर अर्जुन मांझी के पास पुलिस आती है और कहती है कि तुम्हारा इन्दिरा आवास पास हुआ है चलो ठेप्पा लेना है और बाईक पर बैठाकर थाना ले जाती है और उसको पीट पीटकर दोनों हाथ बांधकर मारती है और उसकी हत्या हो जाती है महोदय और एस0पी0 से जब मैंने बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि यह संवेदनशील मामला है । महोदय सरकार संज्ञान ले, न्याय मिले और उसको मुआवजा मिले ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, पशुपालन मंत्री जी विधान-सभा में है । कम्फेड वाला मामला था अध्यक्ष महोदय और उस समय प्रभारी मंत्री संतोष मांझी जी ने आपके निर्देश पर कहा था कि हम इसको संज्ञान में लेकर जवाब देंगे विधान-सभा में बहाली कर के अध्यक्ष महोदय, तो क्या हुआ पशुपालन मंत्री जी यहां हैं इनको बताना चाहिए । कबतक बहाली हो जायेगा अध्यक्ष महोदय चूंकि चलते सदन में आपने निर्देशित किया था अध्यक्ष महोदय हैं पशुपालन मंत्री जी ।

अध्यक्ष: विभाग देख लेगा ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, श्री मनोज मंजिल की सूचना पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ।

अध्यक्ष: सरकार संज्ञान ले रही है,यहां बैठी हुई है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, सदन यह जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री गंजेश्वर साह अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री गुंजेश्वर साह, नरेन्द्र नारायण एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथाउसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत प्रखंड सत्तर कटैया के सत्तर पंचायत में कैंसर रोग फैल गया है । पूरे प्रखंड के पंचायत सत्तर कटैया, विजलपुर, पटोरी, बिहरा, रकिया एवं अन्य पंचायत में लगभग 700 लोग कैंसर रोग से मर गये हैं और इतने ही संख्या में गंभीर रूप से पीड़ित हैं । ये सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं । एम्स के द्वारा 300 लोगों की जांच हुई जिसमें 126 लोग कैंसर से पीड़ित पाए गये । टाटा मेमोरियल अस्पताल के द्वारा भी 100 लोगों की जांच हुई, जिसमें 53 लोग कैंसर से पीड़ित पाये गये । पूरे प्रखंड के सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं ।

अतएव जनहित में सत्तर कटैया प्रखंड के सभी पंचायत के मजदूर वर्ग के लोगों की जांच कराकर कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए उक्त प्रखंड में कैंसर अस्पताल का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंसर रोग एक गंभीर जन स्वास्थ्य का प्रश्न है और इसके ससमय निदान और उपचार से मनुष्य का जीवन बचाया एवं बढ़ाया जा सकता है । राज्य में अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में मुख तथा स्त्रियों में स्तन तथा गर्भाशय मुख के कैंसर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं ।

सहरसा प्रखण्ड के सत्तर कटैया प्रखंड में दिनांक 5 एवं 6 मार्च, 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रशासन द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग सह जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 97 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया था । इसमें पूर्व से ज्ञात कैंसर के दस मरीज थे और स्क्रीनिंग के माध्यम से भविष्य में संभावित मुख कैंसर के 7 मामले पाए गए । इसके अतिरिक्त 4 व्यक्तियों में संभावित अन्य कैंसर के मामले पाए गए जिसमें से जांचोपरांत 3 मामले कैंसर के नहीं पाए गए । इस प्रकार इस शिविर में एक ही नए कैंसर का मामला पाया गया । संस्थान द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी प्रतिवेदित है कि सत्तर कटैया प्रखण्ड में कैंसर की दर अत्यधिक नहीं पाई गई ।

इसके पूर्व वर्ष 2018 में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के दल ने यह शिविर के माध्यम से जांच की थी । वर्ष 2020 में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के विशेषज्ञ दल ने भी जांच शिविर आयोजित किया था जिसमें कुल 11 कैंसर के मरीज पाए गए थे । वर्तमान में प्राप्त सूचनानुसार सत्तर पंचायत के कुल 17 वार्डों में कुल 25 कैंसर मरीज हैं जिनमें से एक की मृत्यु हई है । उपरोक्त पंचायत में पीने के पानी में कैंसर कारक तत्व आर्सेनिक की भी जांच की गई थी जो सामान्य पायी गई थी ।

यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार कैंसर का निदान एवं इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा राज्य में उपलब्ध हो इसके लिए कृत संकल्पित है । इस संबंध में उठाए गए कुछ नए कदम निम्न हैं :-

1- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 100 बेड के स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है जिसमें कैंसर के निदान एवं इलाज की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

2- श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई एवं भारत सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त अस्पताल के निर्माण की योजना है । इस अस्पताल के निर्माण से पूर्व ही यहां अन्य माध्यमों से 130 बेड की सुविधा उपलब्ध कराकर मुख, गर्भाशय मुख, स्तन एवं कुछ अन्य कैंसर के इलाज कीमोथेरेपी एवं शल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त पैलिएटिव केयर एवं प्रीवेनटिव केयर की सुविधा भी उपलब्ध है ।

3- राज्य में कैंसर मरीजों के आंकड़ों की वास्तविक स्थिति जानने हेतु मुजफ्फरपुर एवं पटना में कैंसर रजिस्ट्री की सुविधा प्रारंभ की गई है ।

4- सुदूर प्रखंडों एवं पंचायतों में कैंसर मरीजों की पहचान, निदान, चिकित्सा एवं जन जागरूकता के उद्‌देश्य से राज्य के 14 जिलों में कैंप होमी भाभा कैंसर सेंटर के सहयोग से आयोजित किये जा रहे हैं । यह कार्यक्रम 4 फरवरी, 2021 से शुरू कर वर्तमान में मुजफ्फरपुर, सीवान, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, आरा (भोजपुर), नालंदा, औरंगाबाद, गया और बेगूसराय जिलों में संचालित है और इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों में अद्यतन कुल- 2676 स्क्रीनिंग कैम्प आयोजित किये गये हैं जिसमें 187072 व्यक्तियों (पुरुष- 84555, महिला- 102517) की स्क्रीनिंग की गई है जिसमें कैंसर के सम्पुष्ट मामले 265 पाये गये । इनमें से 72 मरीजों की शल्य चिकित्सा हुई तथा 57 व्यक्तियों की कीमोथेरेपी माध्यम से एवं 28 मरीजों का अन्य माध्यमों से सफल इलाज किया गया । कुल 38 व्यक्तियों का इलाज के क्रम में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये । शेष मरीजों की चिकित्सा की तैयारी की जा रही है ।

5- अगले वित्तीय वर्ष से यह कार्यक्रम विस्तारित करते हुए राज्य के शेष सभी जिलों में प्रारंभ किये जाने की योजना है ।

6- पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में स्तन कैंसर की पहचान हेतु डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की स्थापना लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से की गई है । इसी अस्पताल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी भवन का निर्माण कराया जा रहा है । जिसमें कैंसर के इलाज हेतु अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध होंगी । यह भवन माह दिसंबर, 2022 तक संचालित हो जाने की संभावना है ।

7- इसी कड़ी में पहचाने गए कैंसर मरीजों की चिकित्सा हेतु राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 10-10 बेड के कीमोथेरेपी वार्ड एवं पैलिएटिव केयर वार्ड के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा सुविधा अगले 6 माह में प्रारंभ किए जाने की योजना है ।

8- कैंसर प्रभावित गरीब एवं मजदूर वर्ग के व्यक्तियों के इलाज में गरीबी बाधक न बने । इस हेतु राज्य में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है जिसमें पात्र परिवारों को कैंसर की उच्च स्तर की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक एवं संवेदनशील है तथा

राज्य में कैंसर के इलाज हेतु विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

माननीय सदस्यों की भावना के आलोक में आगामी अप्रैल माह में होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुजफ्फरपुर, के सहायोग से सत्तर कटैया प्रखण्ड के सभी पंचायतों में क्रमवार कैंसर मरीजों की पहचान एवं जन-जागरूकता हेतु शिविर आयोजित किय जायेंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, वहां के गरीब सारे गरीब है सारे लोग मजदूर हैं और वे कैंसर से पीड़ित है । इनको जो रिपोर्ट आया है उसको हम चुनौती नहीं दे रहे हैं लेकिन हमको उसमें भी शक जरूर दिखायी पड़ता है, अभी दो दिन पहले भी दो व्यक्ति मरा है लेकिन सवाल उठता है कि जो रिपोर्ट है वह है । हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि पूरे प्रखंड में सभी पंचायत में वहां के सभी मजदूरों की जांच हो और कैंसर चिन्हित हो और पचगछिया में जो पी0एच0सी0 है, वह बहुत अच्छा पी0एच0सी0 है । वहां कुछ व्यवस्था कर दें ताकि वहां गरीब का ईलाज हो जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबसे बड़ी बात यह कहना चाहते हैं कि जितने मजदूर हैं, कैंसर हो जाता है उसको हैसियत नहीं है कि वह पटना आ सकता है, उसकी हैसियत नहीं है कि वह दरभंगा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है तो सबको कार्ड बना हुआ नहीं है । अभी डी0एम0 गये सत्तर कटैया और जाकर बोले हैं कार्ड बनाने के लिए लेकिन वह भी कार्ड अभी नहीं बन पाया है । वह गरीब खाने के लिए तरसता है, वह बाप मॉ को लेकर कहां से जायेगा एम्स में और दरभंगा में ।
(क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/17.03.2022

..क्रमशः..

श्री गुंजेश्वर साह : इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कृपा करके उनलोगों के इलाज की व्यवस्था आप सरकार के माध्यम से करवा दीजिये, जॉंच करवाइये, इलाज का माध्यम करवा दीजिये । यह मेरा व्यक्तिग्रत आग्रह आपसे है ।

अध्यक्ष: ठीक है । इलाज करवाना चाहते हैं ?

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मैंने बहुत विस्तार से हर प्रश्न का जवाब और जो भी संभावित पूरक प्रश्न थे, सबके जवाब दिये थे । माननीय सदस्य ने यदि ध्यान से सुना होता तो मैंने अपने जवाब में इस बात की भी चर्चा की है कि कैंसर मरीजों की चिकित्सा हेतु राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 10-10 बेड के किमोथेरेपी वार्ड एवं

पॉलीऐक्टिव केयर वार्ड के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा सुविधा अगले छः माह में प्रारंभ की जायेगी ।

वहीं पर बगल में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी है । महोदय, जब यह सुविधा शुरू होगी तो वहाँ भी होगी । तुरंत में जो माननीय सदस्य और उनके साथ अन्य और सदस्यों की जो भावना थी, उसके आलोक में भी मैंने कहा कि अप्रील के महीने में सभी पंचायतों में, सत्तर कटैया प्रखंड के हर पंचायत में हम जाँच शिविर अप्रील के महीना में करा देंगे । तो माननीय सदस्य की जो इच्छा है और जो भावना है, हम भी उसके प्रति संवेदनशील और चिंतित हैं और काम करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका इसमें हस्ताक्षर नहीं है । श्री विनय कुमार चौधरी जी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने सही से बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है लेकिन सवाल उठता है कि आयुष्मान भारत की भी इन्होंने चर्चा की है, अभी हमारे गुंजेश्वर भाई ने कहा है कि सभी का कार्ड नहीं बना है । इसके अतिरिक्त दरभंगा में विवेकानंद कैंसर अस्पताल है और जनजीवन अस्पताल है, ये दोनों आयुष्मान भारत से वहाँ पर टैग नहीं हैं। उसकी भी व्यवस्था इनको करनी चाहिए ।

साथ-ही, डिजिटल मेमोग्राफी की इन्होंने चर्चा की है । यह सिर्फ एक नहीं बल्कि हरेक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब जो महिलाएँ हैं उनका सही ढंग से इलाज हो सके ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री विनय कुमार चौधरी : पूरक यह है कि डिजिटल मेमोग्राफी की व्यवस्था की हर मेडिकल कॉलेज में और आयुष्मान भारत का संबंधन विवेकानंद कैंसर अस्पताल और जनजीवन अस्पताल बेनीपुर में कब तक कराना चाहते हैं ? यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, संभावित पूरक प्रश्न का भी जवाब इसमें डाला था । मैंने कहा था कि मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक एवं संवेदनशील है तथा राज्य में कैंसर के इलाज हेतु विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं । महोदय, चरणबद्ध रूप से जो प्रयास होंगे उसमें वे सारे चीज हैं जिसकी चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मैंने तो माना ही है कि मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दिया है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक और चरणबद्ध का तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जायेगा । कैंसर ऐसी बीमारी है, दरभंगा जिला में हमारे बेनीपुर और गौराबौड़ाम विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही भयानक स्थिति है । वहाँ पर आर्सेनिक जल की

भी समस्या है । वहॉ पर पी0एच0ई0डी0 की पानी की जो व्यवस्था, वह बंद है । इसलिये वहॉ पर आर्सेनिक की भी परेशानी हो रही है । महोदय, इसलिए इसपर ध्यान देने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : ध्यान दीजियेगा ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : ठीक है ।

सर्वश्री पवन कुमार जायसवाल, श्यामबाबू प्रसाद यादव एवं अन्य पॉच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पथ निर्माण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, राज्य में पथ निर्माण विभाग के पथों का रख-रखाव OPRMC एवं CMBD योजना के तहत किया जाना है । OPRMC के तहत पथ के मरम्मति की शिकायत पर 48 घंटों के अंदर पथ को दुरूस्त करने का एकरारनामा संबंधित संवेदकों के साथ है । पथ प्रमंडल, ढ़ाका / मोतिहारी अन्तर्गत मोतिहारी से बेलवा घाट, ढ़ाका से घोड़ासहन, पचपकड़ी से गुरहेनवा, पुरनहिया से झरौखर तथा ढ़ाका से फुलवरिया पथों की स्थिति बेहद जर्जर है । लगातार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ।

अतएव पथ प्रमंडल, मोतिहारी / ढ़ाका सहित राज्य में OPRMC एवं CMBD के तहत पथों के रख-रखाव में असफल संवेदकों को Black List करने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वैसे पथों का अन्य एजेन्सी से कार्य कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : समय चाहिये ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति शून्यकाल समिति ।

श्री चन्द्रहास चौपाल(सभापति, शून्यकाल समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत शून्यकाल समिति का गृह विभाग से संबंधित 95वॉ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूॅ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय भी दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 55 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	- 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	- 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	- 02 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	- 02 मिनट
सी0पी0आई0	- 02 मिनट

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 58,19,02,50,000/- (अठ्ठावन अरब उन्नीस करोड़ दो लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री छत्रपति यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

महोदय, पथ निर्माण विभाग के लिए मेरी पार्टी की ओर से माननीय सदस्य, श्री भूदेव चौधरी जी बोलेंगे लेकिन महोदय, इनका पथ निर्माण विभाग का हम एक विषय मात्र संज्ञान में माननीय मंत्री जी को आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपका ओ0पी0एम0आर0सी0 के तहत दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया में जो संवेदक के बारे में पता चला है कि राजा कंस्ट्रक्शन कर के कोई काम कर रहा है । महोदय, एक दिन भी कोई कार्य नहीं हुआ है और राशि की निकासी हो रही है और इनका कोई कार्य नहीं हो रहा है । सरकार के संज्ञान में पहले से भी है । अब सरकार किस कारण से इसको छिपा रही है और सरकार बचाव कर रही है, सरकार जवाब देगी महोदय । हमारी पार्टी की ओर से श्री भूदेव चौधरी जी बोलेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी जी, बोलिये ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही शालीनता से और सरलता से हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय सदस्य श्री ललित बाबू ने मुझको दायित्व दिया है इसके लिए मैं श्री ललित बाबू के प्रति कृतज्ञ हूँ और जिन विषयों पर मुझे बोलने के लिए आपके द्वारा अनुमति मिली है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

''जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ।''

अध्यक्ष महोदय, जिन ऋषियों की चर्चा आज मेरे माध्यम से होनी है, यह बात सही है कि निकास नहीं तो विकास नहीं और यह मुझको कहने में गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेय जी ने इसकी शुरूआत की थी और कहा भी था कि जब तक बिहार और भारत में निकास नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है । पूज्य बापू महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौट कर इसी हिन्दुस्तान की धरती पर आये थे तो सबसे पहले वे अपने गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और जब गोखले से मुलाकात हुई तो उन्होंने 1917 ई० में गोखले से कहा था कि मैं अफ्रीका और दुनिया की स्थिति को देख कर मैं आपसे सलाह-मस्वीरा करने आया हूँ । गोखले ने कहा गांधी तुम तो अच्छे काम में तल्लीन थे, अच्छा काम कर रहे थे वकील थे, अफ्रीका में वकालत तुम्हारी अच्छी चल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब भारत गुलामी की जंजीर से कैसे टूटे, कैसे छूटे, मैं चाहता हूँ कि यह देश आजाद हो, गोखले ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा था गांधी तुम अफ्रीका से आये हो, पता है किसके विरोध में तुम

बगावत करना चाहते हो, अदावत करना चाहते हो, उस सराकर के विरोध में तुम अदावत करना चाहते हो, विरोध करना चाहते हो, जिसकी सत्ता इतनी मजबूत है, इतनी सरकार इसकी मजबूत है कि दुनिया में उसका सूर्यास्त नहीं होता है । दुनिया में जिसकी सत्ता और सरकार हो, जिसके पास बम–बारूद, सिपाही, पुलिस, दारोगा, इंस्पेक्टर हो, स्टेनगन और मशीनगन हो, उसकी ताकत के सामने गांधी तुम कैसे विरोध करोगे उस अंग्रजी हुकूमत का । गांधी ने कहा कि मेरे अंदर एक जज्बा जगा है, जुनून पैदा हुआ है, का तलाश करो हिन्दुस्तान की गलियों में, घरों में, शहरों में, राजधानियों में जा कर तुम पूछताछ करो, लोगों का भरोसा लो किन्तु शर्त यही है कि एक दिन में सिर्फ एक शहर में ही निवास करना है । पूज्य बाबू महात्मा गांधी ने अपने गुरू गोखले के आदेशानुसार पूरे भारत का भ्रमण किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन निराशा और हताशा हाथ लगी । वे फिर अपने गुरू गोखले से मिले । उस समय भी हॅसी आ रही थी, मजाक सा अनुभव हो रहा था कि ये गॉधी, सीधा–साधा गॉधी कैसे इस देश को आजादी दिलायेगा, फिर मुस्कुराते हुये कहा कि क्या गॉधी बोलो, अभी भी तुम्हारे अंदर वही हिम्मत और ताकत है, भरोसा है, उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा अटल है, संकल्पित हूॅ कि इस देश को मैं आजादी दिलाउंगा, कैसे दिलाओगे, किस राज्य ने हिम्मत किया, कहा कि मैंने भारत के हर राज्यों का दौरा किया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम, महाराष्ट्र, बम्बई, हर जगह गया, कहीं भी मुझको हिम्मत और साहस नहीं मिली लेकिन जब मैं बिहार की धरती पश्चिमी चम्पारण की धरती पर गया तो मुझको यह अहसास हुआ कि यह देश आजाद हो सकता है और इसी बिहार की धरती से यहॉ की चिंगारी, आजादी की चिंगारी फूटी । जब वे आये थे दोनों ने देखा था और यही बिहार से उन्होंने एक धोती को ग्रहण किया था, उनको लग रहा था कि हालत यहॉ की नाजुक है, जिस रोड की चर्चा हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं जब रोड को देखता हूॅ तो लगता है कि यह रोड बहुत खूबसूरत बना है लेकिन कभी भी उसकी तहकीकात नहीं की कि जिस रोड को जिस पुल को बनना चाहिए डेढ़ करोड़ में, वह 9 करोड़ में बन रहा है, उसका प्राक्कलन 9 करोड़ है । जिन सड़कों को 300 करोड़ में बन जाना चाहिए, वह 1700 करोड़ प्राक्कलन में बना हुआ है । यह कौन देखेगा ? उसी ठीकेदार का इंजीनियर है, उसी ठीकेदार का जूनियर इंजीनियर है, उसी ठीकेदार का सुपरवाइजर है । कौन सुपरवीजन करेगा ? कोई है हिम्मत वाला जो कह सकता है कि रोड पर जो ठीकेदार काम कर रहा है, कोई प्रतिनिधि कि तुम बताओ, इसका प्राक्कलन क्या है ? किस मात्रा में तुम दे रहे हो छड़, सीमेंट, छर्री, कहॉ है मजदूर, कैसे तुम कितना इंच इसको डीप करते हो, यह पूछने वाला कोई नहीं है ? जब मैं प्राक्कलन देखता हूॅ तो मुझको हैरत होती है कि

इतने में तो चार रोड बन जाना चाहिए, चार पुल बन जाना चाहिए । नहीं बनता है । हर बार, मैं तो कई बार अपने जूनियर इंजीनियर को, पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को, एक्सक्यूटिव इंजीनियर को तहकीकात करता रहता हूँ कि वहाँ गड्ढे हो गये हैं, जरा देख लीजिये । एकमात्र दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से, जिस धोरैया से मैं आता हूँ, मात्र एक सड़क है जो हाल-फिलहाल मेरे ही उस समय के विधायक थे, उनके प्रयास से एक रोड, वह भी उबड़-खाबड़ है । हर बार मैं निवेदन में, शून्यकाल में सिर्फ और सिर्फ सड़कों की ही बात करता हूँ इसलिये कि मुझको लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी ने जो कहा था कि निकास तब विकास, शायद उनका सपना चूर-चूर हो रहा है । सड़कें नहीं हैं गाँवों में, गाँव में सड़कें नहीं हैं ।

जिसका गुमान नहीं था वही बात हो गई,
तेरी शहर शहर न रही, रात हो गई,
देश में अच्छे दिन तो आये नहीं
मगर तेरे बुरे दिन की शुरूआत हो गई ।

मुझको गर्व है कहने में, अच्छे पुल, अच्छी सड़क देखता हूँ, कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, कहाँ विकास हुआ ? आज तो मैं अनुसूचित जाति जनजाति के विषयों पर भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जब अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है तो लगता है कि मैं उन इंसानों की चर्चा करना चाहता हूँ जो पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, प्रताड़ित है, समाज में टूटा हुआ है, वह इसी पंक्ति का आदमी है, आज उसी की चर्चा इस विधान सभा सत्र में होने वाली है ।

....क्रमश:...

टर्न-11/शंभु/17.03.22

श्री भूदेव चौधरी : क्रमश: मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ कि 17 अरब से बहुत अरब आ गया । देखा है आपने जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रावास हैं, कभी उसकी चौकियों को देखा, कभी उसके शौचालय को देखा, कभी उसके छत को देखा, उसके पंखा को चलते हुए देखा ? मैंने करीब से देखा है कि एक-एक चौकी पर दो-दो छात्र सोते हैं और पैसे- पैसे तो आपने जितना सिमुलतला हाईस्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में देते हैं, जितना पैसा आप नेतरहाट में स्कूलों को और शिक्षकों को पढ़ाई के लिए देते हैं उतना ही पैसा तो आप अम्बेदकर आवासीय छात्रावास के छात्रों को देते हैं । कभी आपने जाँच किया ? क्यों नहीं तहकीकात किया कि इतने लंबे दिनों के बाद आवासीय छात्रावास में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे आइ0ए0एस0, आइ0पी0एस0 नहीं हो रहे,

कभी तहकीकात किया कि सिमुलतला के छात्रों के लिए उसके भविष्य के लिए जहां 85 से 90 प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिविजन पास करते हैं और यहां के बच्चे-यहां के बच्चे की हालत खराब है । कभी आपने देखा अनुसूचित जाति के छात्रावास को जाकर वहां लड़कियां रहती है, दिन में भी रहती है और रात में भी रहती है । वहां आपने एक भी डाक्टर, एक भी नर्स की व्यवस्था की है । यदि रात में लड़कियां बीमार पड़ जाय, लड़के को भोमेटिंग होने लगे तो कहां जायेगा वह, कहां जायेगा । उसकी तहकीकात करने की जरूरत हो तो जीवन से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है । अभी-अभी छठ पूजा हुआ, देखा होगा आपने वह सूप बनाने वाला डोम आज भी आखरी आदमी है, गांव में भी डोम जाति के लोग रहते हैं उसको शादी समारोह में कोई निमंत्रण नहीं देता, अगर इत्तेफाक से उस डोम की तरफ से कोई निमंत्रण जाता है तो जाने से लोग कतराते हैं । आज भी 75 वर्षों की आजादी के बाद आज की तारीख में भी यह स्थिति, परिस्थिति बनी हुई है जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं, जिसको अनुसूचित जाति, जनजाति कहते हैं । यह स्थिति हो गयी है, कोई आइ0ए0एस0, आइ0पी0एस0 नहीं बन रहा है, क्या हालत है । आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा । अध्यक्ष महोदय, मालूम है आवासीय छात्रावास में 1752 शिक्षक के पद सृजित हैं और हैं कितने ? हैं मात्र 550 के आसपास, वहां पढ़ाई होती होगी ? खाने की व्यवस्था तो आपने लिस्टों, सूचियों में, कॉपियों पर लिख दिया, किताबों में छाप दिया कि अंडे भी मिलेंगे, दूध भी मिलेंगे।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : सेब भी मिलेंगे, मांस-मछली भी मिलेंगे, लेकिन मिलता है कभी आपने देखा है । कभी उसकी जॉच नहीं की, लूट खसोट हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है । मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा- ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बहा ले जायेगा, सोचता हूँ आदमी इस दुनिया से क्या ले जायेगा । ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बहा ले जायेगा, सोचता हूँ आदमी इस दुनिया से क्या ले जायेगा । दोस्तों मत पूछ मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक तो मेरा रास्ता ले जायेगा ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री भूदेव चौधरी : इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा और पंचायत राज की व्यवस्था पर बोलना है बस 5 मिनट ।

अध्यक्ष : आपका समय बढ़ा दें ।

श्री ललित कुमार यादव : दो मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है बहुत दिन नहीं हुए । मुझको लगता है कि दो-तीन महीने पहले, चार महीने पहले पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, बड़ी सरगर्मी थी, बड़ा तनाव था और चुनाव के बाद- चुनाव के बाद जिनको सर्टिफिकेट मिल गया वहां बिना सामान के ग्राहक पहुंचने लगा- क्या हुआ है उप मुखिया बनने में, प्रमुख बनने में, उप प्रमुख बनने में, जिला परिषद् के अध्यक्ष बनने में, उपाध्यक्ष बनने में सर्वविदित है । मुझको लगता है यह कहने की जरूरत नहीं है कि खरीद-फरोख्त हुए हैं । खरीद-फरोख्त क्या है ? उसको साधारण भाषा में लोग घूस बोलते हैं । वह खरीद फरोख्त हुआ है इसको छिपाया नहीं जाता । महोदय, आज मुझे मतदान करने की ताकत, क्षमता मिली है तो 1952 से- किसके खून से, भगत सिंह के खून से, चन्द्रशेखर आजाद के खून से, अशफाकउल्लाह खां के खून से, पूज्य बापू महात्मा गांधी के खून से, बाबा साहब अम्बेदकर के खून से इन लोगों की जो उपलब्धि हुई, जिन्होंने लड़कर के झगड़कर के खून देकर आजादी दिलायी और वोट देने का अधिकार मिला । महोदय, सच पूछिए तो मैं व्यथित हूँ । इसलिए व्यथित हूँ कि अगर आत्मा अमर है, वैसे मैं नहीं मानता, लेकिन सर्वविदित है लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है तो मैं भी मान लेता हूँ कि आत्मा अमर है । सच पूछिए अगर पूज्य बापू महात्मा गांधी की आत्मा, डा0 भीमराव अम्बेदकर की आत्मा, सरदार भगत सिंह की आत्मा, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की आत्मा, चन्द्रशेखर आजाद की आत्मा, राजगुरू गुरूदेव की आत्मा, अशफाकउल्लाह की आत्मा की अगर बिहार के चुनाव पर नजर पड़ती होगी तो मुस्काती नहीं होगी, मुस्कुराती नहीं होगी, बल्कि यहां के इस पंचायत में होनेवाले चुनाव और उसके परिणाम और घूस को देखकर के, खरीद फरोख्त को देखकर के उनकी आत्मा हंसती नहीं होगी, मुस्कुराती नहीं होगी, विलाप करती होगी ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : आपने मुझे समय दिया है इसके लिए धन्यवाद । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करे और 10 रूपये की राशि उक्त राशि से घटाये । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ । अपनी पार्टी के नेता माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी और हमलोगों के उप मुख्य सचेतक जनक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ । सबसे ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ मधुबन की महान जनता का जिन्होंने मुझे आज यह अवसर दिया

कि कटौती प्रस्ताव पर आपके समक्ष खड़ा हूँ और सरकार का पक्ष रख रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, भूदेव जी ने चर्चा की है शायरी से और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और अटल जी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि अमेरिका और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर है वह सड़कों की स्थितियों को लेकर है, सड़कों के निर्माण को लेकर है । अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि 2005 में और अब में जो स्थिति हमारी सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो स्थिति आयी है । पथ निर्माण विभाग ने जहां 2005 में पहले ग्रामीण पथों की चिंता करता हूं, भूदेव जी ने गांव के सड़कों की चिंता की । जहां लंबाई मात्र 3112 कि0मी0 थी । आज माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, एन0डी0ए0 सरकार ने ग्रामीण सड़कों की लंबाई 3112 कि0मी0 से बढ़ाकर 1 लाख 2 हजार 306 कि0मी0 तक करने का काम किया है । पथ निर्माण विभाग ने करीब 19 हजार कि0मी0 नयी सड़कों का निर्माण किया है, 6047 पुल पुलियों का जाल बिछा है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूँ कि जहां 2005 में गंगा नदी पर केवल 4 पुल था, अब कुछ पुल तो बनकर तैयार हो गये और 14 पुल निर्माणाधीन, प्रस्तावित मिलाकर 14 पुल बनने की स्थिति में है । उसी प्रकार कोशी नदी में वर्ष 2005 में जहां 2 पुल था अब 7 पुल बनकर तैयार है, गंडक नदी में वर्ष 2005 में जहां सिर्फ 3 पुल था अब 6 पुल बनकर तैयार है, सोन नदी में जहां वर्ष 2005 में 2 पुल था वह वर्ष 2020-21 तक 4 पुल बनकर तैयार है, बागमती नदी में उत्तर बिहार के इलाके में, नेपाल से सटे इलाके में गांधी जी की बड़ी चर्चा हुई और मैं चम्पारण की धरती से आता हूँ । महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही है । उसी बागमती नदी से हमारे यहां आना जाना मुश्किल हुआ करता था । जहां केवल 3 पुल हुआ करता था 2005 में और वर्ष 2021 तक आते-आते 9 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है । फल्गु नदी मोक्ष की धरती गया- फल्गु नदी जहां सिर्फ एक पुल हुआ करता था और आज 7 पुल बन चुके हैं । टोले-टोले सड़कों का निर्माण हुआ है, टोलों को गांव से, पंचायतों से जोड़ा गया, पंचायतों को प्रखंड मुख्यालयों से जोड़ा गया, प्रखंड मुख्यालयों को अनुमंडल से जोड़ा गया, अनुमंडल को जिले से जोड़ा गया और जिले को राजधानी पटना से जोड़ा गया । चाहे गांव की सड़क हो, चाहे राजधानी की सड़क हो, सड़कें चकाचक बन रही है और कहते हैं कि विकसित सड़कें जो होती है वह दूरदर्शी सोच का परिणाम होती है । आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा ।

क्रमशः

टर्न-12/पुलकित/

(क्रमशः)

श्री राणा रणधीर : सड़कों को सड़कों से जोड़ने का, स्वर्णीम चतुर्भज योजना बनाने का और आज बिहार जैसे और हमलोग जैसे सुदूर देहाती इलाकों में जहां पहले डिबरी जलती थी, लालटेन जलता था अब जमाना सी0एफ0एल0 का चला आया । अध्यक्ष महोदय, पहले जहां सात बजे, आठ बजे अंधेरा छा जाता था अब वहां सी0एफ0एल चमकती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह लक्ष्य रखा था कि हम कहीं भी सुदूर इलाके से छह घंटे में पहुंचेगे । आदरणीय नन्द किशोर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया था उस लक्ष्य को घटाकर उसको आज नितिन नवीन जी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आज यह लक्ष्य रखा गया है कि किसी कोने के अंदर पांच घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति पांच साल, छह साल पहले पटना आया होगा, पटना में बुलेट ट्रेन भी चलायेंगे । पटना की सड़कों को देखकर पटना में डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने की योजना हो, आज कोई व्यक्ति गांव से आयेगा या शहर का व्यक्ति भी जो पांच, छह वर्षो के बाद पटना भ्रमण करेगा तो उसके समझ में आयेगा कि विकास किस तरह से दूरदर्शी सोच का प्रकटीकरण हुआ है और किस स्तर पर विकास हुआ है । मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके मार्गदर्शन में पथ निर्माण की जो सड़कें हैं, अध्यक्ष महोदय, तीनों सड़कें मिला दी, जो एन0एच0 की सड़क होती है, एस0एच0 की सड़क होती है और एम0डी0आर0 सड़क होती है । कुल मिलाकर जहां वर्ष 2005 तक सिर्फ 14692 किलो मीटर सड़कें निर्माण हुआ करती थी आज वह बढ़कर 24384.18 किलो मीटर लम्बाई बढ़ गई है । इसके लिए हम अपने माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को बधाई देते हैं और उनके लिए कहते हैं । भूदेव जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां पढ़ी है तो पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, सदन के लिए पढ़ता हूं:-

''कि परों को खोल जमाना, उड़ान देखता है
जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है ।''

अध्यक्ष महोदय,

''जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का ।''

हमने टोले-टोले में सड़कें बनाने का काम किया है । हमने सड़कों को राजधानी पटना में बनाने का काम किया है ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, मैं आज माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं गांधी जी के चम्पारण में गांधी जी ने जहां बुनियादी स्कूलों की स्थापना की । उस चम्पारण में, उस मधुबन में जाकर पथ निर्माण की एस0एच0 की एक अति महत्वपूर्ण सड़क को चौड़ीकरण का काम भी करने का निर्णय भी लिया है जिसकी निविदा हो गई है और उसका शिलान्यास यथा शीघ्र होने वाला है । इसके लिए भी माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का भी आज बजट है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का भी बजट है और कला, संस्कृति विभाग का भी बजट है ।

मैं पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं और जिस तरह से पहली बार पंचायत के चुनावों में बड़े पैमाने पर ई0वी0एम0 का इस्तेमाल हुआ । जिस तरीके से पंचायतों का चुनाव सम्पन्न हुआ । पहली बार यह गांधी जी का सपना था और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांधी जी के शब्द रहे कि ''तेरे शहर का पेट मेरे गांव की मिट्टी से पलता है।'' गौरतलब रहे कि देश अपना गांवों में बसता है । इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांधी जी के सपने को दीन दयाल जी के सपने को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी ने काम किया है, उनके लिए दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिस हौसले के साथ उन्होंने काम किया है ।

''जब हौसला बुलंद हो तो, सफलता चलकर आती है,
समुन्द्र राह देता है, चट्टाने थरथराती हैं ।''

उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रयोग था, इतने बड़े पैमाने पर । दुनिया देख रही थी कि पंचायतों में ई0वी0एम0 का इस्तेमाल करना । पंचायतों की सारी व्यवस्था एक भवन के नीचे करना । पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करना । गांव का यह देश कब बढ़ेगा जब गांव समृद्ध होंगे । गांवों में कौन-कौन लोग रहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, गांव में हमारे किसान रहते हैं, गांव में हमारे खेती करने वाले भाई रहते हैं, मजदूर भाई रहते हैं । एक तो बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, सड़कों के निर्माण ने उस क्रांतिकारी परिवर्तन को नई दिशा दी है, नई उड़ान दी है । पंचायती राज व्यवस्था पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से गांव की समस्या, गांव में और उस पंचायत सरकार भवन में सबकी

व्यवस्था । वहां सभा भवन बनाना, न्याय की व्यवस्था करना । वे चकाचक बनाने का भी काम करेंगे ।

श्री महबूब आलम : पंचायत भवन भूत बंगला बन गया है ।

श्री राणा रणधीर : हम केवल योजना, रचना नहीं बनाते बल्कि हम उस योजना, रचना पर काम भी करते हैं । आज थानों में जो भवन का निर्माण हुआ है । आपने इसकी कल्पना नहीं की थी, उपाध्यक्ष महोदय, प्रखंडों में जिस तरह से आई0टी0 भवन का निर्माण हुआ है । पंचायत सरकार भवन में जिस तरह से सभा भवन का निर्माण हुआ है । कई पंचायत सरकार भवन में आप जायेंगे तो लगेगा कि जैसे किसी कलेक्टेरियट के सभा भवन में हम आये हैं । जिस तरह से फर्नीचरों का निर्माण हुआ है ।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये, आप बोलते रहिये । बोलना आपका अधिकार है । कहते हैं कोई सपना देखो और उसमें यकीन रखों तो जरूर पूरा होता है । सपना देखा था हमने सड़कों के निर्माण का, सपना देखा था हमने अच्छी सड़कों के निर्माण का और पिछले एक साल में जिस प्रकार से काम पथ निर्माण विभाग ने किया है । आज कोई विदेश से हमारा कोई भाई आता है, अटल पथ फेज वन देखकर उसको लगता है कि जो कल्पना हमारी होती थी, फोरलेन सड़कों की कल्पना हमारे मन में होती थी । हम सब देहात, सुदूर इलाके के लोग हैं, हमने फोरलेन सड़के नहीं देखी थी । फोरलेन सड़के देखने के लिए हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता था । लेकिन आज पटना शहर में जिस तरह से अटल पथ फेज वन का निर्माण हुआ है, जी0पी0ओ0 गोलंबर से भिखारी ठाकुर फ्लाई ओवर बाया आर ब्लॉक जिस तरह से काम हुआ । एन0एच0 33 बी0के0 मुंगेर, गंगा रेल सह पुल के पहुंच पथ का निर्माण हुआ है और कुल 3390 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन जे0पी0 गंगा पथ परियोजना का बुडको से 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय संपोषण कराकर इस महत्वाकांक्षी योजना के निजी निर्माण में तेजी लाई गई है । पटना शहर की चिंता की गई है । पटना शहर को और सुंदर बनाने के लिए, पटना शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 422 करोड़ रुपये की लागत से 2.2 किलोमीटर लम्बे कारगिल चौक से पटना सांइस कॉलेज तक महत्वाकांक्षी फोरलेन । महबूब साहब, डबल डेकर फ्लाई ओवर निर्माण की स्वीकृति का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । बख्तियारपुर, ताजपुर के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल परियोजना को फरवरी, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । हम योजना, रचना भी बनाते हैं और योजनाओं को पूरा करने का काम भी करते हैं । चकिया, केसरिया, सत्तर घाट पथ के आरेखण पर अवस्थित गण्डक नदी पर निर्मित सत्तर घाट पुल हम सब के लिए

चम्पारणवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और माननीय मंत्री जी ने यह देने का काम किया है । विगत एक वर्ष में 503 किलोमीटर लम्बाई के कुल तीन राष्ट्रीय उच्च पथ, मंत्री जी इसको और डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन मुझे जो लगा एक वर्ष में इतना काम हुआ है वह माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहिए और यह जानकारी भी होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सरकार समाज के हर वर्गों को लेकर चलने का काम करती है, समाज के अंतिम वर्गों की चिंता करना जैसे लोहिया जी ने किया, जय प्रकाश जी ने किया । दीन दयाल जी की अंतिम आदमी की अंत्योदय योजना रही । अंतिम आदमी को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास रहा है और उसके लिए न केवल चिंता की है । आदरणीय मांझी जी बैठे हैं, हमलोगों ने मिलकर एन0डी0ए0 की सरकार ने किस तरह से गांव में रहने वाले गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों, बेटियों की चिंता की और सभी समाज के बेटियों की चिंता करते हुए । हमलोगों ने जब हमारी हर कोई बेटी इंटर पास करेगी तो उसको 25 हजार रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है और वह बेटी हमारी, बहन हमारी ग्रेजुएशन पास कर जायेगी तो उसको 50 हजार रुपये देने की योजना सरकार ने बनाई । जो हमारा भाई, आज सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने इंटर में टॉप करने का काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से उन बच्चों को भी बधाई देने का काम करता हूं और उन प्रतिभाओं के लिए गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया । गरीब आदमी का बच्चा जब बी0पी0एस0सी0 का पी0टी0 क्वालिफाई करेगा तो सरकार 50 हजार रुपये उसको आगे की पढ़ाई करने का काम करेगी । यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा में जो पी0टी0 पास करेगा सरकार उसको आगे की पढ़ाई के लिए एक लाख रुपया देने का काम करेगी । कई तरह की योजनाएं हैं अनाज से लेकर, छात्रवृत्ति पोषाक योजना लगातार सरकार दे रही है । अनुसूचित जाति योजना के तहत विकास मित्रों के माध्यम से, न्याय मित्रों के माध्यम से विकास के नए आयाम को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार ने विकास के नये आयाम को न केवल ग्रहण किया है, प्राप्त किया है बल्कि उसको स्थापित करने का काम किया है और बिहार ने देश के लिए नजीर बनने का काम किया है ।

(क्रमशः)

टर्न-13/अभिनीत/17.03.2022

श्री राणा रणधीर (क्रमशः) : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इन पुल-पुलियों के निर्माण के तहत एक और पक्ष रखना चाहता हूं । पंचायती राज विभाग का जो कार्य हुआ है कि कैसे कोई सपना देखिए, कोई लक्ष्य रखिए और उसको पूरा कीजिए । हर घर पक्की नली, सरकार की जो हमारा सात निश्चय पार्ट-2 है उसके भी तीन स्तंभ पंचायती राज विभाग के द्वारा पूरा होना है । हर घर पक्की नली योजना, पेयजल योजना और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव योजना के तहत पंचायती राज विभाग जो कार्य कर रहा है । हर घर पक्की नली योजना के अंतर्गत 1 लाख 70 हजार 991 वार्डों में पक्की गली-नली बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखी थी और सरकार ने 1 लाख 17 हजार 464 वार्डों को अच्छादित करने का काम कर लिया है । महोदय, पेयजल योजना के तहत बिहार के हर घर नल का जल में 1 करोड़ 62 लाख घरों को नल का जल उपलब्ध करा दिया गया है । सरकार ने गांवों में रौशनी उपलब्ध रहे, बिजली के क्षेत्र में 700 मेगावाट की क्षमता को बढ़ाकर 6600 मेगावाट किया । कितने सब स्टेशन बनाये, आज गांव में 20 घंटे, 22 घंटे और शहरों में 23 घंटे, 24 घंटे बिजली रहती है । ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह का काम हुआ, सड़कों के निर्माण में हुआ । अनुसूचित जनजाति, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का जो काम हुआ, पंडित दीन दयाल जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी, अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम जो सरकार कर रही है उसके लिए सरकार लगातार तत्पर रहेगी, लगातार काम करती रहेगी । अंत में अध्यक्ष महोदय अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार के लिए कहता हूं कि जब आंखों में अरमां लिया, मंजिल को अपना मान लिया । बिहार के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो संकल्प लिया है, जो सपना पाला है कि

''जब आंखों में अरमां लिया,
मंजिल को अपना मान लिया ।
फिर मुश्किल क्या, आसान क्या,
जब ठान लिया, तो ठान लिया ।।''

इसी जज्बे के साथ सरकार हर संकल्प को पूरा करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर ।

श्री चन्द्रशेखर : बहुत-बहुत आभार महोदय । मैं सत्ता पक्ष द्वारा पेश अनुदान मांग के विरोध में तथा प्रतिपक्ष द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, 10 रुपये की कटौती का आग्रह करता हूं सरकार से और आसन से ।

महोदय, मैं आज मधेपुरा की देव तुल्य जनता जिन्होंने धनबल, बाहुबल और सत्ता प्रतिष्ठान के मनसूबों को चकनाचूर कर और सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक विसंगती, जातीय विषमता के शिकार जेल में बंद लालू प्रसाद यादव जी और गत चुनाव में 32 उड़न खटोले पर सवार दर्जनों महारथियों को मात्र 32 वर्ष के युवक जिसने चुनौती दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं अपने मुख्य सचेतक ललित जी ने जो समय दिया इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूं ।

महोदय, बिहार एक अकेला राज्य है जहां 2016 तक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में अन्य राज्यों से पथ निर्माण का तुलनात्मक अध्ययन पेश किया जाता था । इस प्रतिवेदन में अन्य राज्यों को इसलिए छुपा दिया गया कि हम अपना मुंह दिखाने लायक शायद न रह पाये । महोदय, सड़कें बनती हैं एक बरसात नहीं चलती है ढुल जाती है । जब से सुशासन आयी है तब से एक कथा सर्वविदित है, प्रचलित है । हमारे साथी सदस्य भी बोल रहे थे और पक्ष के साथी भी बोल रहे थे । एक बरसात नहीं चलती है महोदय । आप भी शासन पर बैठे हैं, अपने उसी इलाके को देखकर, एक बरसात नहीं चलती है सड़कें ढुल जाती हैं । स्टीमेट घोटाले होते हैं, पांच करोड़ का काम पचीस करोड़ में, तीन करोड़ का काम पन्द्रह करोड़ में, इन घोटालों की राशि की अगर सच में, न फंसाता हूं, न बचाता हूं । भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में अगर हिम्मत हो जांच कराने की तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस राज्य के अभियंता, ठेकेदार और सरकार के लोग जेल में होंगे । महोदय, यह कम दु:खद नहीं है 12 करोड़ बिहार के आवाम की गाढ़ी कमाई का आप टैक्स लेते हैं । मोटरसाइकिल पकड़ाता है, हेल्मेट नहीं है, जूता नहीं है, हजारों-हजार पता नहीं आजकल 2000 से कम का फाईन ही नहीं चल रहा है सुशासन में और सड़कें हैं कि नहीं, हमको क्या मिल रहा है सड़क के बदले, अगर आपको देखना है महोदय, बिहार के अन्य कोने में जाकर देखिए और फिर मधेपुरा, सहरसा जिले को भी देखिए, आपको पता होगा कि स्थिति बहुत ही भयावह है । हम इसलिए यह बात कह रहे हैं कि यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । हमारे साथी आये दिन रोज जाते हैं । कहने के लिए कुछ भी कहें, यहां सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता पक्ष के बारे में अच्छा-अच्छा बोलेंगे, हमलोग यहां बैठे हैं इंसाफ भी बोलेंगे तो बुरा-बुरा, तो हमलोग इंसाफ के लिए खड़े हैं महोदय । पंचायती राज व्यवस्था की क्या हालत है ? पंचायती राज व्यवस्था में सात निश्चय की क्या स्थिति है ? नल-जल योजना की क्या स्थिति है ? जल-जीवन-हरियाली की क्या स्थिति है ? 25 हजार करोड़, 27 हजार करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी और शायद दिल्ली में ही कहीं किसी टैक्स में वह

समाहित हो गयी, दिल्ली से वह आयी ही नहीं । कहीं साउथ इंडिया के लोग टंकी छोड़ कर भाग रहे हैं, काम करने के लिए बेरोजगार युवा को दे दिया, कहां खोजेंगे, माननीय सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जरा खोजिए भाग रहा है । पंप छोड़कर आपका भाग रहा है, सच्चाई यही है नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं । कहीं टोटी लगा हुआ है तो पानी नहीं निकलता है, कहीं पानी निकलता है तो निकलते रह जाता है । महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी प्रखंड के पांच पंचायत की जांच करा ले सरकार, बिहार के किसी भी प्रखंड का, नालंदा की ही जांच करा ले, अगर पांच पंचायत की जांच हो जाय तो सच सामने आ जायेगी और सारे लोग जेल में बंद होंगे । महोदय, स्थिति बहुत भयावह है, चिंताजनक है महोदय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साजिश कौन सी हो रही है, अब देखिए जो सड़कें स्टीमेट घोटाले की भेंट चढ़ती हों, 12 करोड़ बिहार के आवाम की राशि का अपमान होता हो इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? इस लोकतंत्र के मंदिर ने लोकतंत्र को शर्मसार होते देखा है । हम सभी लोग आते हैं, इंसाफ मांगने इस लोकतंत्र में आते हैं, आपका आसन बड़ा होता है महोदय, यह माना जाता है कि अगर सरकार पर नकेल कसनी है तो लोकतंत्र का मंदिर ही एक अच्छा मंच है लेकिन इसको भी शर्मसार किया जाता है महोदय । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों को कहना चाहता हूं क्या है आज स्थिति । आज अगर मैं यह कहूं, रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में चौपाई है महोदय, बहुत ही भयावह है । मनवाद उसी का पोषक, तुलसी दास, रामचरित्र मानस, ''अधम जाति में विद्या पाये भयहु यथा अहि दूध पिलाये ।'' अधम जात में विद्या पाकर आदमी वैसा ही जहरीला हो जाता है जैसा कि दूध पिलाने के बाद साॅप । लालू यादव जहरीला हुए? जेल में बंद हैं । गरीबों का, वंचितों का, छूतों का सम्मान बढ़ाये और किंग मेकर की भूमिका में जेल में बंद हैं । शहीद जगदेव प्रसाद जी वंचितों की आवाज बने गोली खा लिए । डॉ भीम राव अम्बेदकर, इस दुनिया में अगर कोई एक आदमी 100 वर्ष के इतिहास में, ओबामा प्रशासन ने मूल्यांकन कराया, सर्वेक्षण कराया महोदय, आपका सीना गौरव से फुलेगा कि हमारा बेटा, हमारा पुरखा, देश का बेटा हमारा पुरखा डॉ भीम राव अम्बेदकर एक ऐसी शख्सियत पैदा हुए, महोदय, उससे पहले कहना चाहता हूं । प्रभु, परमात्मा, खुदा, ईश्वर किसी जात का दास नहीं है, जात तो बनाया हमारे पुरखों ने किसी गलती से और यहां आरोप मनु पर लगता है और उसको हमलोग ढ़ोह रहे हैं ।

-क्रमशः-

टर्न-14/हेमन्त/17.03.2022

(क्रमशः)

श्री चंद्र शेखर : दुनिया के किसी देश में हिंदुस्तान, नेपाल और मोरिशस, जो बिहारी लोग जाकर बस गये हैं, जहां कथित हिंदुवाद चलता है । 6,647 जातियां गजट में हैं और पता नहीं आज तक से साक्षात्कार हो रहा था जनगणना पर, जो कोलैब कर रही है सरकार जनगणना पर, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप हमारे नेता से कह रही थी 48 हजार जातियां हो गयी हैं, कैसे होगा सर्वेक्षण ? गाय-भैंस का सर्वेक्षण हो जायेगा, बकरी-छकरी का सर्वेक्षण हो जायेगा मगर वंचितों का सर्वेक्षण नहीं होगा । महोदय, अत्यंत दुखद है । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधम जाति में विद्या पाये अंबेडकर साहब और इस देश के पहले व्यक्ति हुए जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में झंडा फहराये हिंदुस्तान का । लंदन ऑफ इकोनोमिक्स में झंडा फहराये हिंदुस्तान का । कोई स्वर्ण नहीं, कोई ऊंची जाति का लोग नहीं । अछूत जाति में पैदा होने वाला ऐसा एक इंसान, हमारा पुरखा, जिस जाति के आदमी को कलकुइयां छोड़िये, पोखर में भी पानी नहीं पीने दिया जाता था, गले में हांडी बांधकर चलना पड़ता था, ये मनुवाद के दंश हैं और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, वह बेटा पहला, हिंदुस्तान का पहला । याद करिये, पहला कह रहा हूं तो पहला । इसीलिए महात्मा फूले हों, पेरियार हों, संविधान को रौंदा जा रहा है और कहां रौंदा जा रहा है पार्लियामेंट के उस गलियारे में रौंदा जा रहा है, जलाया जा रहा है । कौंन है इसके पीछे ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को महिमामंडित किया जा रहा है महोदय । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं

(व्यवधान)

मेरे पास समय है महोदय ।

उपाध्यक्ष : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप बैठिये ।

श्री चंद्र शेखर : महोदय, मेरा समय ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठिये न, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है ।

श्री चंद्र शेखर : महोदय, महात्मा फूले, पेरियार को गाली मिली, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली खानी पड़ी । सामाजिक न्याय के योद्धा और 27 वर्षों से, 22 वर्षों से आरक्षण को दबाकर रखने वाले के खिलाफ अगर हमारे पुरखे बी0पी0 सिंह साहब ने आरक्षण दिया, एक साल तक नंगा नृत्य मनुवादियों ने किया था महोदय और आपके लिए भी संजय बाबू, इसी रामचरितमानस में है -''जे बनराधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा ।'' उत्तरकांड में है महोदय, इसी का वे लोग पोषक कर रहे हैं ।

तेली, कुम्हार, किरात, कोल सब अधम और नीच जाति के हैं, इसी को मानने वाले लोग हैं और इतना ही नहीं, यादवों के बारे में क्या कहा है ''आभीर जमन किरात खस स्वपचआदि अति अघिरूप जे ।'' ये यादव लोग भी जो नीची जाति के हैं, तो यादव से लेकर मेहतर तक को नीच बनाने वाले मनुवाद और उसके संपोषण करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं मैं समय चला गया, छाती में हिम्मत है, तो सड़क पर आना, समय दूर नहीं है जब झंडा फहरायेगा वंचितवाद और आपसे कहना चाहता हूं महोदय..

(व्यवधान)

अरे भइया, मैं ये कहूं आप पंचायती राज को देखते हैं । पंचायतों की क्या स्थिति है । मैंने पहले ही कह दिया । एक दारूबंदी आया, दारूबंदी क्या आया महोदय, घर-घर दारू चल रही है । एक इंसान आदमी, गांव का प्रमुख आदमी घर से निकलता था, तो लुच्चा-लफुआ सड़क छोड़ देता था, आपको भी पता होगा । लेकिन आज की तारीख में लुच्चा, लफुआ, शैतान सड़क पर होता है, इंसान घर में दुबका रहता है, इंसानों को छोड़िये महोदय, सज्जन को छोड़िये, माननीय विधायक जो सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं इनकी हैसियत-कुव्वत नहीं है कि शैतानों और लुच्चा-लफुआ को देखकर उसका सामना कर ले । इनकी स्थिति यही है और हमारी भी स्थिति यही है । इतने बुरे हाल में शासन व्यवस्था को ले जाने वाले लोग आज अगर इतरा के बोलते हों, शर्मसार करने वाला है । महोदय, पथ निर्माण में, आपको कहना चाहता हूं कि दरभंगा जिला में अललपट्टी से गंज तक की सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 की है, लेकिन हालत बहुत खराब है । आधी आबादी दरभंगा की उसी सड़क से होकर जाती है और नाला के गलत निर्माण के कारण जांच भी करवाये, सड़क बाधित है, पानी जमा हुआ है, डेढ़ ही किलोमीटर है मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है महोदय । मंत्री जी संज्ञान में लेंगे । दूसरी रोड है साढ़े पांच किलोमीटर की दरभंगा में ब्रह्मपुरा से बहुरवा तक, इसकी स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है और इसकी जांच करवानी चाहिए । इसमें सारे लोग संलिप्त मिलेंगे महोदय । मैं आप सभी से कहना चाहता हूं । महोदय, अगर आप सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखेंगे 2013-14 के बाद 2020-21 की रिपोर्ट है माननीय मंत्री जी । 2013, 2014 के बाद, 2016 के बाद एक भी कम्प्रेटिव डाटा नहीं है कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है । मैंने पहले भी कहा । दूसरा, 2013-14 के बाद कोसी नदी को एक मिलोमीटर रोड का उत्क्रमण नहीं हुआ है । 2013-14 में जो हुआ आज तक वही चल रहा है, तो कोसी नदी पथ निर्माण विभाग की उपेक्षा का दंश झेल रही है महोदय और आपसे कहना चाहता हूं कि यह मैंने इसलिए कहा कि अधम जाति में पाये, साजिश है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को

देखेंगे महोदय और नव भारत टाईम्स 29 नवम्बर, 2021 के अखबार को देखेंगे, तो दलितों का जो ड्रॉप आऊट रेट है 2018-19 में 55.78 से 62.40 हुआ । लगभग 7 प्रतिशत बच्चे लड़की उच्च पढ़ाई से वंचित रह गयीं । महोदय, लड़के भी 5 प्रतिशत और संयुक्त रूप से लगभग 4 प्रतिशत का ड्रॉप आऊट है । ये माना जायेगा, यह जो संघ मनुवादी गठजोड़ की सरकार है वह साजिशाना ढंग से अधम जाति के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती है । जय हिन्द, जय बिहार । बाकी..

(व्यवधान)

फिर कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह मेरा ड्राफ्ट है, जरा मैं इसको सदन में पेश करना चाहता हूं, आदेश चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष : सभी पार्टी के, चूंकि समय फिक्स रहता है । इसीलिए किसी भी सदस्य का प्रोसीडिंग में नहीं जायेगा ।

श्री नंद किशोर यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इतना बढ़िया भाषण चंद्र शेखर जी ने दिया, बिना दो लाईन सुनाये हमको चैन मिलेगा महोदय ?

उपाध्यक्ष : बोलिये ।

श्री नंद किशोर यादव : दो लाईन सुना देते हैं इनको

''जिस सूरज की आस लगी है शायद वह भी आये, पर तुम कहा कि खुद ही तुमने कितने दीये जलाये ।''

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय सिंह ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : आ रहे हैं क्या फिर ?

श्री नंद किशोर यादव : आये हुए हैं, आये हुए हैं, यहीं हैं । चाचा के बाद भतीजा है, दूसरा नहीं है । घबराइये नहीं ।

उपाध्यक्ष : शांति, शांति । सुनिये, नये सदस्य बोल रहें हैं, माननीय विजय सिंह ।

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर सरकार के पक्ष में मैं अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि बिहार सरकार ने सड़क संपर्कता के लिए अभूतपूर्व कार्य किये हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जहां एक ओर राज्य के किसी जिले से राजधानी पटना पहुंचने के लिए शुरू में 2005 के बाद 6 घंटा का समय निर्धारित करते हुए प्रतिबद्धता के साथ काम किया, वहीं इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अब पथ निर्माण विभाग 5 घंटे में ही राजधानी पटना की दूरी तय करने के लायक सड़क की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर

आवागमन की उत्तम सुविधा मिली है । उपाध्यक्ष महोदय, 2005 से जनवरी 2021 तक की सड़क निर्माण की स्थिति मैं सदन के समक्ष रख्ना चाहता हूं । बिहार में 2005 में पथों की जो लंबाई मात्र 3624 किलोमीटर थी, वह आज बढ़कर 2021 में 5475 किलोमीटर हो गयी है । उसी प्रकार राज्य उच्च पथ की लंबाई 2005 में मात्र 2177 किलोमीटर थी, जो आज 2021 में 3713 किलोमीटर हो गयी है । बृहद जिला पथ की लंबाई 2005 में 8891 किलोमीटर थी, परंतु 2021 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने प्रतिबद्धता से काम करते हुए 15195 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है । यदि इन सभी सड़कों की कुल लंबाई की तुलनात्मक स्थिति देखी जाय तो 2005 में जहां 14692 किलोमीटर सड़के थीं, वह आज बढ़कर 2021 में 24384 किलोमीटर की सड़कें हो गयी हैं । उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग की उपलब्धियां बेमिसाल है । विगत एक वर्ष में देखा जाय तो जिन महत्वपूर्ण

(क्रमशः)

टर्न-15/धिरेन्द्र/17.03.2022

क्रमशः....

श्री बिजय सिंह : महोदय, पथ निर्माण विभाग की उपलब्धियां बेमिसाल है । विगत एक वर्ष में देखा जाए तो जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करते हुए लोकार्पण किया गया है, उसमें अटल पार्क फेज-1, जी0पी0ओ0 गोलंबर से भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर भाया आर0 ब्लॉक, एन0एच0-333बी के मुंगेर गंगा रेल-सह-सड़क पुल का पहुंच पथ महत्वपूर्ण है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल 3390 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन जे0पी0 गंगा पथ परियोजना के निर्माण में तेजी लाई गई है । इस परियोजना का निर्माण हुडको से दो हजार करोड़ रुपये के वित्तपोषण से कराया जा रहा है । यह योजना अप्रील, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटना शहर को जाम से मुक्त करने की दिशा में 422 करोड़ की लागत से 2.20 किलोमीटर लंबे कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक महत्वकांक्षी फोरलेन डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर कार्य आरंभ कराया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा झारखण्ड राज्य में अवस्थित साहेबगंज को बिहार में मनिहारी के साथ सम्पर्कता प्रदान करने हेतु गंगा नदी पर 4-लेन सेतु का निर्माण जो हमारे ही जिला में है का 1901 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसे जल्द ही चालू कर दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग के द्वारा धार्मिक गलियारा के तहत उच्चैठ (मधुबनी) से महिषी (सहरसा) के बीच निर्माणाधीन एन0एच0-527ए

के मार्गरेखन पर मधुबनी जिले के भेजा एवं सुपौल जिले के बकौर (परसरमा) के बीच कोशी नदी पर 10.20 कि0मी0 लम्बे पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो देश का सबसे लम्बा नदी पुल है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय चूंकि सरकार बहुत काम कर रही है और पथ निर्माण विभाग के माध्यम से हम अपने माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जिस जिले से हम जीत कर आते हैं कटिहार जिला, बरारी विधान सभा अंतर्गत एक काढ़ागोला घाट है, काढ़ागोला से पीरपैंती की ओर जो सड़क जाती है, 1962 में जो चाइना की लड़ाई हुई थी तो सेना ने उसी मार्ग का उपयोग किया था । हम चाहते हैं कि उस विधान सभा में काढ़ागोला घाट से पीरपैंती के बीच एक पुल का निर्माण हो ताकि वहां से लोग सुगमतापूर्वक एक जिला से दूसरा जिला जा सके । साथ-ही-साथ बरारी विधान सभा में कुरसैला प्रखंड में एक पंचायत है गोबराही दियरा जहां 10 हजार की आबादी है और यदि वहां पर एक किलोमीटर खेड़िया से गोबराही दियरा में पुल का निर्माण हो जाता है तो जो दियरा है, उस दियरा में आतंक की तरह लोग, खेत किसी का, जमीन किसी का, जोत कोई और करते हैं वहां पुलिस प्रशासन को जाने में भी दिक्कत होती है । हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि उसे विभाग के द्वारा, पुल विभाग के द्वारा उस पर पुल निर्माण कराया जाय और दूसरी बात जो मैं काढ़ागोला घाट की मांग किया हूँ, काढ़ागोला घाट पर भूमि अधिग्रहण की कोई समस्या नहीं है, वहां सरकार की जमीन ही काफी है । उसमें लागत कुछ लगना नहीं है, सिर्फ पुल का निर्माण होना है, जमीन अधिग्रहण में कोई खर्चा नहीं है । हम माननीय मंत्री जी चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी काम करने वाले व्यक्ति हैं और यह सरकार काम करती है । आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पथ निर्माण विभाग के नेतृत्व में पूरे बिहार में तो काम हो रहा है । खासकर मैं बरारी विधान सभा में भी मांगता हूँ । जय हिन्द, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय-जय बिहार । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आपने जो मुझे समय दिया मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी, सचेतक श्री राजेश भाई को धन्यवाद देता हूँ ...

(व्यवधान)

एक शब्द हम गलत नहीं बोलेंगे । मैं जिस धरती से आता हूँ वह संतो, ऋषियों और महर्षियों की धरती है बक्सर और बक्सर भगवान बावन की जन्मस्थली, माता

गंगा का नैहर और भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है और मैं आप सबों को उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ वही बक्सर है जो कि काशी के बाद उसका दूजा नाम बक्सर, जिसको दूजा काशी भी कहा जाता है । भगवान श्री राम के द्वारा जो रामेश्वर भगवान की स्थापना की गई मैं उस बक्सर से हूँ । मैं अपने गुरुदेव लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के श्रीचरणों में कोटिश: चरण बंदना करते हुए अपने वक्तव्य को धार देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ साथियों । मेरे मित्र पंकज भारद्वाज के द्वारा रचित एक कवीता है महोदय–

''जी हाँ, अब सच बोलना देश से गद्दारी है,
और मुँह खोलना तो जुर्म बहुत है भाई,
इस हुक्म पे एतराज जताओ नहीं मियां,
एहतराम करो इसका ये हुक्म सरकारी है,
बेमौत मरते अपने और दम तोड़ते सपने,
इसके लिए सत्ता का हर आदमी आभारी है ।''

महोदय, आज कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पंचायती राज, पथ निर्माण विभाग का आज बजट है महोदय और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है । हमारे सत्ता पक्ष के साथीगण बहुत तारीफ बांधते हैं पुलों का, बहुत तारीफ बांधते हैं महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ आपके आसन के माध्यम से पथ निर्माण मंत्री महोदय को कि 20 परसेंट, 25 परसेंट बिलों पर काम होते हैं, दिये जाते हैं उन ठेकेदारों को, उन संवेदकों को । काम में गुणवत्ता कहां से आयेगी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ । बनने को पुल–पुलिया और सड़क तो बन रहे हैं बिहार में, बंधु थोड़ा गौर फरमाइयेगा, बनने को पुल–पुलिया और सड़क तो बनते हैं महोदय, उद्घाटन होता है महोदय लेकिन मात्र दो से तीन महीने के अंदर वह दम तोड़ देते हैं । महोदय, ये सरकारी आंकड़ें आपके हकीकत में हो सकते हैं लेकिन हम सभी उन पगडंडियों पर, उन राहों पर, उन स्थानों पर जाने का काम करते हैं । हमलोग संघर्ष कर के इस विधान सभा में आये हैं, हमलोगों ने किसी, अपने बाप की बपौती मेरा यह सीट नहीं है, मैं अपनी बदौलत, अपने दम के बदौलत और अपनी व्यवस्था के बदौलत यहां पर जीत कर आता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बक्सर की जनता को कि उसने दूसरी बार इस पवित्र मंदिर में मुझे भेजने का काम किया है । धन्य हो बक्सर की जनता, मैं उनकी चरण बंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, पथ निर्माण मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी का यह सपना हुआ करता था कि 21वीं सदी में भारत की सड़कें चलेंगी

और महोदय, उसका आकार देने के लिए यू0पी0ए0-1 और 2 की सरकारों ने जिस समय बाबू रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बजट का आकार बिहार के लिए यू0पी0ए0 की गवर्नमेंट ने बढ़वाने का काम किया था और उसका एक सही सांचा और खांका आज बिहार में सड़क की जाल बिछ गई है । उन्हीं का देन है और यू0पी0ए0 का देन है महोदय । हम तो शेखी बघारते हैं, कहते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया लेकिन इन 7 वर्षों के काल में आपने देश को क्या दिया है, अपनी हकीकत को अपनी छाती पर हाथ रखकर अगर कोई बयां करे तो महोदय इस देश के साथ सिर्फ छलावा किया गया है, इस देश और राज्य के साथ । महोदय, किसी ने इस देश और राज्य के साथ अपना हक देने का और लेने का काम नहीं किया । हकीकत है हमारे पंचायती राज के मंत्री सम्राट भाई बैठे हैं, इस हकीकत से रूबरू हैं महोदय । महोदय, गांव की गलियां और नलियां तो बन रही हैं लेकिन जो नलियां कोड़ दी गई हैं, खोद दी गई हैं उसमें, नल-जल योजना में कहीं टोंटी गायब है महोदय, उसकी जांच हो जाय । मैं तो गांव का नाम देता हूँ, पंचायत का नाम दूंगा, मैं पंचायत का नाम दूंगा अगर अभी आदेश कर दें तो मैं पंचायत का नाम देता हूँ, ऐसा कोई पंचायत नहीं है बक्सर का जहां घटिया समान की सप्लाई नहीं की गई हो । कहीं पाईप लीक है, कहीं टोंटी लीक है, कहीं कमजोर है । महोदय, नली-गली को छोड़ दिया गया है, कोई ढकने वाला नहीं है, बच्चे गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं लेकिन इसका सुद लेने वाला कोई नहीं है । महोदय, राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज कि केन्द्र से अगर एक रुपया चले तो एक रुपया उन पंचायतों को मिले । ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी का सपना था और उसको धार देने का काम यू0पी0ए0 की 1 और 2 गवर्नमेंट ने किया था । महोदय, जिस तरह से पंचायतों में सचिवों की कमी, एक पंचायत सचिव चार-चार पंचायतों को संभालने का काम कर रहे हैं महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को आपके आसन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि क्या वह लूट का एक मात्र संसाधन पंचायत बन चुका है....

क्रमशः....

टर्न-16/संगीता/17.03.2022

...क्रमशः...

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : एक पंचायत सचिव चार पंचायत का मालिक बनकर बैठा है महोदय । पंचायत सचिवों की घोर कमी है महोदय इसको मैं दूर करने की मांग करता हूं आपके माध्यम से महोदय । महोदय, जो सोलर लाइट लगाने की राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा जा रही है हम सभी विधायकों को उस अनुशंसा को करने का अधिकार भी मैं आपके आसन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से कर रहा हूं कि सोलर लाइट की भी अनुशंसा की योजना जो जा रही है राज्य सरकार के द्वारा हम सभी विधायकों को उस योजना में हमलोगों का हिस्सा देने का काम माननीय मंत्री जी करें । महोदय, मनरेगा के कामों में भारी अनियमितता हो रही है महोदय । देखने को यह मिल रहा है, 60, 40 के अनुपात में तो काम हो रहा है लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका मजदूरी तो भुगतान हो जाता है लेकिन सही समय से अभी तक महोदय यह जांच का विषय है । मेटेरियल जो संवेदक काम कराता है उन मेटेरियल का भुगतान आज तक और अभी तक नहीं हो पाया है महोदय, इसकी भी जांच मैं सदन से कराने की मांग करता हूं और प्रखंडों में करोड़ों करोड़ लंबित है महोदय और मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इसकी स्वयं जांच आप करायें तो आपको यह पता लग जायेगा कि मनरेगा में कितने घोटाले हुए हैं अभी तक और जो संवेदक को काम दिए जाते हैं वह संवेदक काम करने के लिए राजी नहीं हो पाता है महोदय इसकी क्या वजह है इसकी भी जांच होनी चाहिए ।

महोदय, आज मैं खासकर के कला एवं संस्कृति पर बोलने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे बैठे हैं पीछे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वर्ष 2020-21 में माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कला महाविद्यालय और खेल महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी । मैं आपको बता दूं श्री मणिशंकर अय्यर जी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने उस समय एक योजना लायी 2013 में कि हरेक गांव, पंचायतों में स्टेडियम बनने का काम होगा लेकिन महोदय, सरकार ने भी घोषणा की थी लेकिन आज तक एक पंचायतों में हकीकत में कोई भी माननीय विधायक खड़ा होकर कह दे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कि एक भी पंचायतों में स्टेडियम बनाने का काम आज तक नहीं हो पाया है । ब्लॉक में ही कोई बता दे, कोई बता दे ईमानदारीपूर्वक, कहीं नहीं बना है महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि सरकार जो कहती है वह करने का काम करे, धरातल पर उसे उतारने का काम करे महोदय तब जाकर के बिहार में सच्चाई से काम होगा अन्यथा ये तो तारीफ का पुल बांधते रहेंगे महोदय और तारीफ का पुल बांधने से बिहार का विकास नहीं होगा महोदय, हमेशा अवरूद्ध रहेगा । मैं आपको बता दूं जिस तरीके में जिस हाल में आज के नाटककर्मी हैं, आज के रंगशालाएं हैं कहीं भी वह खस्ता हालत में पड़ी हुई है महोदय, खस्ता हाल में हैं

नाटक कर्मियों को कोई पूछने वाला नहीं है, महोदय मैं तो पूछता हूं कोरोना काल में उन कलाकारों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई राज्य सरकार के द्वारा । आवेदन कराकर के यह भद्दा मजाक किया गया उन कलाकारों को एक पैसा देने का काम राज्य सरकार ने नहीं किया । हमारे यहां कलाकार हैं महोदय, हमारे भोजपुर जिला शाहाबाद जिला में एक से एक कलाकार हैं, भरत शर्मा जैसे सुर सम्राट हमारे यहां वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं उनका पैतृक घर है महोदय । पूरा हिन्दुस्तान नहीं दूसरे देशों में भी जाकर वे भोजपुरी लोक गायन का काम करते हैं, वैसे सुर सम्राट को आज तक विधान परिषद में कलाकारों के लिए जगह होती है महोदय, एक जगह एक कलाकारों को अगर सरकार बता दे कि एक कलाकार को भी विधान परिषद में मौका दिया है हमारी सरकार ने । एक वादक को, एक धावक को, एक नेशनल प्लेयर को क्या राज्य सरकार ने कभी विधान परिषद में मनोनयन का काम किया है महोदय, अगर नहीं किया है तो मैं आपके आसन के माध्यम से मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए महोदय विधान परिषद में इसका एक काम सुनिश्चित कराने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

महोदय, हमारे जिला में एक से एक धावक हुए, जिसमें बाबू शिवनाथ सिंह जी का नाम जो बेस्ट ओलंपियन थे महोदय और उनको अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था और वे पैर में बोरा बांधकर बाबू शिवनाथ सिंह उन गंगा के रेत पर दौड़ा करते थे अब महोदय आज वह व्यक्ति अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित व्यक्ति मोहताज है उस जिला में, मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमारे यहां खेल का मैदान, किला का मैदान है उसका नाम बाबू शिवनाथ सिंह स्टेडियम रखने की मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करता हूं । महोदय, उन कलाकारों के लिए जो सम्मानित हमारे कलाकार हैं उनके साथ राज्य सरकार ऐसा भद्दा मजाक नहीं करे । महोदय, चित्रकला में हमारे मिथिलांचल में तो चित्रकला मिथिलांचल की मशहूर है लेकिन मंजूषा अंगप्रदेश की बदहाल स्थिति में है महोदय । बदहाल स्थिति में शाहाबाद प्रक्षेत्र का वहां की चित्रकला जैसे कोहबर है महोदय, पिरिया है महोदय वह चित्रकला आज विलुप्ति की कगार पर है महोदय मैं आपके माध्यम से पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र को उन चित्रकला से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे शाहाबाद को देने की कृपा की जाए महोदय...

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रौशन ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लाये गये बजट के समर्थन में और विपक्ष के साथियों के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन उससे पहले मैं पातेपुर के उन तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होनें लोकतंत्र के मंदिर में मुझे यहां भेजा साथ ही मैं अपनी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सदन में हम जैसा आदमी को लाने के लिए उन्होंने लाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । अभी विपक्ष के साथी बोल रहे थे बिहार में सड़क नहीं बनी, आंकड़ा तो बहुत आ गया महोदय, अभी बक्सर के साथी ही बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम ले रहे थे लेकिन थोड़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ श्रद्धेय अटल जी का भी नाम ले लेना चाहिए था चूंकि जो व्यक्ति ने अपने कार्य में सड़कों का जाल बिछा दिया उनका नाम तो लिए ही नहीं केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम लिए । इनके लिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : बैठ जाइये । उपाध्यक्ष महोदय मैं इनके लिए कहता हूं । मैं इनके लिए देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी हुई कविता से इनको मैं शुरू करता हूं । देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कविता से,

''अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए
हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें ।
ये नवयुग है यह नवभारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें
हम निकल पड़े प्रण करके, अपना तन-मन अर्पण करके ।
जिद है एक सूर्य उगाना है, अम्बर से ऊंचा जाना है,
एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है ।''

(व्यवधान)

आज विपक्ष के साथी, आपके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं...

आज विपक्ष के साथी हमें लग रहा है हमलोग जब घर से तैयार होकर निकलते हैं तो आइने के सामने खड़ा होते हैं, हमलोग जब घर से तैयार होकर निकलते हैं तो आइने के सामने, दर्पन के सामने अपना चेहरा लेकर खड़ा होते हैं लेकिन मित्र मैं आपको बताना चाहता हूं...

...क्रमशः...

टर्न-17/सुरज/17.03.2022

...क्रमश...

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : चेहरा चाहे आप जितना सजा लीजिये जैसा आपका चेहरा होगा दर्पण के सामने वैसी ही आपकी तस्वीर दिखाई देगी, यही बिहार की तस्वीर है । आपको विकास देखने के लिये आपके आंखों पर जो चश्मा है उस टूटे हुऐ चश्मे से आपको बिहार का विकास नहीं दिखाई देगा । इसलिए अगर बिहार का विकास देखना है सुदूर गांव से लेकर पंचायत को जोड़ा गया, पंचायत से लेकर प्रखंड को जोड़ा गया, प्रखंड से लेकर अनुमंडल को जोड़ा गया, अनुमंडल से लेकर जिला को जोड़ा गया । आज बिहार सरकार के माध्यम से, एन0डी0ए0 सरकार के नेतृत्व में पथ निर्माण मंत्री, नितिन नवीन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इनके नेतृत्व में आज सड़कों का जाल पूरे बिहार के अंदर बिछा दिया गया और बिहार के किसी भी कोने से जब माननीय साथी आप आते हैं तो चार से पांच घण्टे के अंदर आप पटना में, राजधानी में और लोकतंत्र के मंदिर में आप आ जाते हैं यह एन0डी0ए0 सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं धन्यवाद देता हूं पंचायती राज मंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी का उन्होंने जो काम किया बिहार के पंचायतों में उनके द्वारा स्ट्रीट सोलर लाईट की व्यवस्था करके गांवों में जो सड़कें बन रही है उन सड़कों के किनारे स्ट्रीट सोलर लाईट की व्यवस्था कराके रोशनी से जगमगाते हुए ऐसा लग रहा है सम्राट चौधरी जी रोशनी से ऐसा जगमगाने का किये लगता है लालटेन युग के ताबूत की यह अंतिम कील साबित होगी । यह सम्राट चौधरी जी की देन है मित्रों । आज आप गंगा नदी पार करते हैं पहले क्या था धैर्य से सुनिये, हम कभी बेधैर्य नहीं होते हैं सुनिये, सुनिये । गंगा नदी पर पहले एक पुल दिखाई देता था आज क्या है उत्तरी बिहार में जाने के लिये दर्जनों पुल बनकर खड़े हो गये हैं एक बात और बता दें आपको सभी उत्तरी बिहार के साथी रोज आते हैं उस अटल पथ पुल से । अटल पथ से जब हमलोग आते हैं और गाड़ी पर जैसे ही शीट पर अपने माथे को लगाकर आराम से, थोड़ा सा चैन की नींद सोते हैं तो लगता है कि अटल पथ पर आने के बाद आपको नींद पड़ जाती होगी । यह एन0डी0ए0 सरकार का विकास आपको दिखाई नहीं देगा । मैं, आप सभी साथी पथ निर्माण मंत्री जी के यहां हम सब लोग भी जाते हैं अपना आवेदन, अपनी लिखित अनुशंसा भी देते हैं और हर गांव में सड़क बन रही है कि नहीं जितने भी विधायक हम सब लोग हैं वह हर विभाग में आज पथ निर्माण के माध्यम से जो सड़क बनती है, शिलान्यास करते हैं फीता काट करके अखबारों में फोटो और चेहरा चमकाने का काम करते हैं और आज आपको रोड का विकास दिखाई नहीं देता । यदि सड़कों के जाल बिहार में बिछाये जा रहे हैं तो एक बार दिल पर हाथ देकर धन्यवाद दे दीजिये । चूंकि यह सरकार काम करने वाली है हमें लग रहा है अपने टूटे हुये चश्मे से आपको

2005 के पहले का विकास बिहार में दिखाई देगा, अपना चश्मा बदल लीजिये तो 2021-22 के बिहार का विकास आपको दिखाई देगा । इसलिये मैं कहता हूं आज जो है पंचायती राज मंत्री जी हमारे बैठे हुये हैं आज पंचायत में जो काम हो रहे हैं वह पूरे बिहार के लोगों को और ब्लॉक में जाति, आय, आवासीय किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिये ब्लॉक का चक्कर लगाना नहीं पड़े उसके लिये पंचायत में ही समुचित व्यवस्था करने के लिये इन्होंने यह काम किया, इसके लिये मैं पूरे बिहार की जनता की ओर से पंचायती राज मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । हम सब लोग यह काम कर रहे हैं मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा किया और गांव में कुशल विकास हो और गांव में जब तक विकास नहीं होगा तब तक शहर के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं । यह जो महात्मा गांधी जी ने कहा था वह सपना साकार हुआ, वह सपना पूरा हुआ है । एक बार मैं आंकड़ा पर आ जाता हूं 2005 से पहले बक्सर में दो लेन का पुल था, महात्मा गांधी सेतु पर चार लेन का, राजेन्द्र सेतु पर दो लेन का पुल और विक्रमशीला सेतु पर दो लेन का पुल । 2005 से पहले 10 पुल पूरे बिहार के अंदर थे आज क्या है, आज 38 पुल पूरे बिहार के अंदर है । आज महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार फोर लेन का हुआ, कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन का पुल सहित रोड बन रहा है । कोई साथी अभी उधर से जाइयेगा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिये तो बड़े आनंद से सिक्स लेन के पुल से जाने का काम कीजियेगा तब बिहार का विकास आपको दिखाई देगा । बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन का पुल और साहिबगंज-मनिहारी चार लेन का पुल । 2005 से पहले मात्र 10 पुल का निर्माण हुआ था और आज पूरे बिहार में 38 पुलों का निर्माण हो चुका है । यह बिहार और एन0डी0ए0 सरकार का विकास है । उसके बाद भी यदि आपको विकास दिखाई नहीं देता है तो एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चले जाइये । 2005 से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग में केवल 3624 किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज क्या है 5475 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो गई है । राज्य उच्च पथ में 2167 किलोमीटर का 2005 तक था आज 3713 किलोमीटर कुल सड़कें बन चुकी है । इसलिये मेरे मित्रों मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बिहार में जो विकास है वह बिहार में आपको दिखाई देगी बशर्ते ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रखकर विकास देखियेगा तब आपको विकास दिखाई देगा...

(व्यवधान)

नहीं एक आपके पीछे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं उनसे कलेजा ले लीजिये बीरेन्द्र भैया दे देंगे कलेजा । इन्होंने बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर का नाम लिया और डॉ0 भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज सदन में एक दलित का बेटा शेर की तरह गरज रहा है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । लेकिन एक बात प्रण कर लीजिये लोकतंत्र के मंदिर में आपने अछूत शब्द कहा है बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर के विषय में । कम से कम XXX की तरह आप अछूत कहना बंद कर दीजिये, आपके रग-रग में XXX भरा हुआ है, आपके तन-मन में XXX भरा हुआ है । बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर के खानदान के लोग दलित का खून.

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर के वंशज शेरों की तरह दहाड़ने वाले हैं...

उपाध्यक्ष : जो असंसदीय वर्ड है उसे हटा दिया जाय ।

(व्यवधान)

बोल दिये हटाने के लिये, बोल दिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : और अइन्दा कभी अछूत शब्द का नाम नहीं लीजियेगा । यह लोकतंत्र का मंदिर है ।

(व्यवधान)

इसलिये मैं कहता हूं । साथियों आपको विकास दिखाई देगा...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

शांति, शांति ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : यह एन0डी0ए0 की सरकार है । देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है इसलिये आपको विकास दिखाई देगा । मैं बख्तियारपुर के साथी को धन्यवाद देता हूं...

उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया । अब समाप्त कीजिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट, एक मिनट । कल ही...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति, शांति ।

(व्यवधान जारी)

शांति, शांति ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : कल ही...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये माननीय सदस्य को । बैठिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : इसलिये मैं पुनः एन0डी0ए0 सरकार को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांत हो जाइये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवद देता हूं । पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को और पंचायती राज मंत्री, सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं...

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये अब । माननीय सदस्य समाप्त कीजिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : बिहार का जो चहुंमुखी विकास हुआ...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

XXX -आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न-18/राहुल/17.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार जी ।

(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार जी ।

(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाये गये...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठ जाइये ।

श्री सतीश कुमार : कटौती प्रस्ताव के समर्थन में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं । सबसे पहले दलितों, शोषितों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने नेता

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री सतीश कुमार : तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं और मखदुमपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं कि एक अनुसूचित जाति के संघर्ष करने वाले बेटे को सदन में भेजने का काम किया है और आज हम बजट पर बहस में भाग ले रहे हैं साथियो । हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पथ निर्माण विभाग का और अनुसूचित जाति, पंचायती राज और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का बजट पेश किया गया है लेकिन न्याय के साथ विकास की जो सरकार है वह अनुसूचित जाति के, एक दलित के बेटे को मंत्री तो बनाती है लेकिन इस लायक भी नहीं समझती है कि आगे की रो में बैठकर के अनुसूचित जाति का बजट पेश कर सके । हम यह बताना चाहते हैं कि आज भी उनको पीछे बैठाया जाता है क्योंकि वह अनुसूचित जाति है, यह है मनुवादी का, यह है मनुवाद का उदाहरण, यह है ब्राह्मणवाद का उदाहरण कि उनको आगे की रो में बैठकर के बजट पेश करने का अधिकार नहीं है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये वे लोग हैं जो बाबा साहब का तो नाम लेते हैं लेकिन जय भीम और जय संविधान कभी नहीं बोलते हैं, कभी-भी इस सदन में जय भीम और जय संविधान का उद्घोष इन लोगों ने नहीं किया । हम यह कहना चाहते हैं कि सड़क जो बन रही हैं, बड़े ही जोरशोर से प्रचार किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉडल की सड़कें बन रही हैं । प्राक्कलन तो, स्टीमेट तो इंटरनेशनल स्तर का बन रहा है लेकिन सड़कें तो बिहार स्तर की और झारखण्ड स्तर की भी सरकार नहीं बनाई जा रही है । आज भी किसी भी पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर जब आप 50 की स्पीड से ऊपर गाड़ी लेकर चलियेगा तो कमर में ही दर्द होगा और कुछ दूसरी चीज नहीं होगी । इसीलिए सारे नेता बेल्ट लगाते हैं और ऐसी आराम वाली गाड़ी में बैठना चाहते हैं जिससे कमर में दर्द नहीं हो, ये हैं बिहार की सड़कें, 17 साल में ये बनाये हैं । आज किसी भी रोड की जांच कर ली जाय प्राक्कलन के अनुसार रोड नहीं बनता है । आज रोड का इंडोलेशन देखियेगा कहीं भी लगता नहीं है कि वायब्रेटर और रॉलर से काम लिया है । रोड पर कहीं भी आपको ओ0पी0आर0एम0सी0 में है कि रोड एमुलेशन हमेशा रोड पर नजर आना चाहिए । बिहार के किसी भी पथ पर रोड एमुलेशन नजर नहीं आता है जो गढ्ढ़ों को भरने का काम करता हो महोदय । महोदय, दूसरी चीज है बिहार में पहाड़ की लीज खत्म हो रही है । जहानाबाद, गया इन तमाम जगह के लोगों मानपुर का गेरे है वहां से लीज मिलती है लेकिन वहां पहाड़ की लीज खत्म कर दी गई है

उनको झारखण्ड और दूसरे राज्यों से पत्थर लाकर सड़क बनानी पड़ रही है । लीज देते हैं आप गया का और पत्थर आता है चतरा का तो रोड कैसा बनेगा तो इन तमाम को सरकार को दुरुस्त करना होगा । सबसे महत्वपूर्ण बात हम अनुसूचित जाति की बात हुई है, अनुसूचित जाति का आज बजट है हम उस पर बोलना चाहते हैं । हम बोलना चाहते हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास वाली सरकार है लेकिन इसी सदन के मुखिया रहे जीतन राम मांझी जी, जिनको एक सिरफिरे ने एक पार्टी के सिरफिरे ने जीभ काटने की बात की और किसी ने एक शब्द नहीं बोला, ये जीतन राम मांझी यहां बैठे हुए हैं । महोदय, यह है दलितों का सम्मान बिहार में । यहां के चीफ सेक्रेटरी रहे सुधीर कुमार जी पूरी फाईल लेकर के थाने में बैठे रहे क्योंकि वह दलित थे, उनकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं होती है यह है बिहार की हकीकत । ये तमाम चीजें, बजट पर क्यों बोलें, हम तो बजट पर यही कहेंगे, होली का दिन है होली की शुभकामना भी देते हैं कि गोलमाल होते-होते माल गोल हो जाता और अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा पाता, यह स्थिति है । महोदय, बजट पेश होते-होते सब उसी में घोटाला हो जाता है यह स्थिति है । महोदय, बिहार में दलितों के साथ जितना अन्याय हुआ है इस देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ । हम पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित उप योजना अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाई गई है लेकिन अनुसूचित जाति के विकास के पैसे को दूसरे विभागों में डायवर्ट कर दिया जाता है, यह है बिहार की हकीकत । कितना पैसा डायवर्ट हुआ है हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भले ही 17, 295 करोड़ रुपये का बजट मंत्री जी ने पेश किया यहां पर लेकिन अनुसूचित जाति की वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 10 प्रतिशत आबादी है, अगर उनकी आबादी को ही आधार बना लिया जाय तो 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट अनुसूचित जाति के लिए पेश होना चाहिए था लेकिन 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करते हैं और उसमें किस तरीके से फिर अनुसूचित जाति के लोगों को जो ठगने का काम होता है वह बताना चाहते हैं । वर्ष 2015 से लेकर के 2019 के बीच की कहानी बताते हैं कि 8800 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति का दूसरे विभाग में कंवर्ट किया गया है इसकी जांच कराई जाय । महोदय, बिजली विभाग को 2076 करोड़ रुपया दे दिया गया अनुसूचित जाति का पैसा ऊपर से 460 करोड़ रुपया बिजली विभाग को अलग से लोन दिया गया अनुसूचित

जाति विभाग से, उसके साथ-साथ बिहार में जो चमचमाती हुई सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण के लिए अनुसूचित जाति के विकास का 3061 करोड़ रुपया ट्रासंफर किया गया, उसके अलावा 1202 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण पर अनुसूचित जाति का पैसा खर्च किया गया और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह से पैसा नहीं मिला तो अनुसूचित जाति का 1222 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज बनाने में खर्च किया गया, दूसरा महोदय, 776 करोड़ रुपया हमारे यहां कृषि विभाग में बिल्डिंग बनाने के लिए अनुसूचित जाति के पैसे को डायवर्ट कर दिया गया तो अनुसूचित जाति का विकास कैसे होगा ? अनुसूचित जाति के मंत्री तो बना दिए जाते हैं लेकिन पैसा जब डायवर्ट होता है तो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है चुपचाप साईन कर देते हैं, यह स्थिति है । हमारा पैसा, जबकि अनुसूचित जाति इस ब्राह्मणवादी संस्कृति में, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच-नीच की व्यवस्था में सदियों से उत्पीड़ित है, सदियों से प्रताड़ित है । आज भी उनको घोड़ा चढ़ने पर प्रतिबंध है । आज भी जीतन राम मांझी जी जैसे मंदिर में जाते हैं तो मन्दिर को धोया जाता है । यह संस्कृति आज भी जब व्याप्त है, ऐसी स्थिति में उनके लिए विशेष योजना चलाकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को, जो सारा पैसा डायवर्ट करते हैं । हम पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और पथ निर्माण विभाग का बजट एक साथ लाया गया है । क्या एक भी अनुसूचित जाति का बेटा पथ निर्माण विभाग में कांट्रेक्टर का काम करता है ? नहीं करता है महोदय। कुछ खास विशेष जाति के लोग कांट्रेक्टरी पर कब्जा बनाए हुए हैं । जीतन राम मांझी जी ने वर्ष 2014 में शुरूआत की थी कि 75 लाख तक के जो टेंडर होंगे उसमें रिजर्वेशन लागू होगा लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया अब अनुसूचित जाति के बेटों को टेंडर में ठेका नहीं मिलता है तो मांझी जी पता नहीं कैसे उस तरफ इनको नींद आती है हमको भी, जितना भी अनुसूचित जाति के बारे में मांझी जी जितना भी अनुसूचित जाति के बारे में मांझी जी सेचते थे बोलते हैं लेकिन उस तरफ कैसे नींद आती है हमको उनकी सेहत को लेकर चिंता होती है । हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में वर्ष 2014 से पहले, मांझी जी थे तब भी और 2016 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की व्यवस्था थी और वर्ष 2016 के बाद बिहार के दलितों के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नहीं मिल रही है । प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं ।

क्रमशः

टर्न-19/मुकुल/17.03.2022

....क्रमशः...

श्री सतीश कुमार : आप तमाम लोगों के लिए हम बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2017 में, चार सालों का उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिला, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2018, 2020, 2021 में 3474 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से 53 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी, पश्चिम बंगाल में 279 करोड़ रुपया दिया गया जिससे 15 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी, वहीं तमिलनाडु में 2887 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने दिया जिससे वहां के लगभग 29 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी । महोदय, लेकिन बिहार डबल इंजन की सरकार, जो डबल स्टैंडर्ड की सरकार साबित हो रही है, मात्र 47 करोड़ रुपया दिया गया, सोचिए उससे कितने छात्रों का विकास होगा, मात्र 47 करोड़ रुपया, क्योंकि बिहार सरकार को 40 प्रतिशत पैसा मिलाना पड़ेगा इसलिए केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति का पैसा इन्होंने लिया ही नहीं । महोदय, इस तरह से यह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं । इस बात को नोट किया जाए मंत्री महोदय, आप भी दलित परिवार से हैं, आप भी गरीब परिवार से हैं । बिहार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जैसे मांझी जी चला रहे थे, वैसे आप भी उनके बेटे हैं उस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को आगे बढ़ाइये, तब जाकर बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन में जायेंगे, तब जाकर बिहार के बच्चे मेडिकल कर पायेंगे, इंजीनियरिंग कर पायेंगे, बीटेक कर पायेंगे, यह स्थिति है । महोदय, इसलिए इंजीनियरिंग में कोई नहीं जा पा रहा है और इनकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे केन्द्र सरकार ने चालू किया है और वह है फ्रीशिप कार्ड योजना । फ्रीशिप कार्ड योजना वर्ष 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जिसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल सरकार ने लागू किया है । महोदय, फ्रीशिप कार्ड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बच्चों को वह कार्ड दिया जायेगा और उनको जहां भी एडमिशन मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/सरकारी संस्थान में एडमिशन लेंगे तो उनको एक रुपया भी नहीं लगेगा और उस फ्रीशिप कार्ड के एवज में उनका एडमिशन होगा, एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे के खाते में पैसा आयेगा और एक सप्ताह के बाद वह बच्चा उस इंस्टीच्युशन को पैसा ट्रांसफर करेगा । लेकिन बिहार सरकार ने इस योजना को भी लागू नहीं किया है, महोदय तो दलितों के साथ में यह न्याय करने वाली सरकार, क्या न्याय कर रही है यह साफ-साफ आंकड़ों से झलकता है, महोदय । बिहार से जो बाहर राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात जहां पर हम से कम आबादी अनुसूचित जाति की है लेकिन 60 लाख से ज्यादा बच्चे अनुसूचित जाति

के आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 60 हजार बच्चों को हम आवासीय विद्यालयों तक पहुंचा पाये हैं, महोदय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, 60 हजार बच्चों को ही आवासीय विद्यालयों तक पहुंचा पाये हैं, यह है न्याय के साथ विकास का खाका । महोदय, इस सरकार को चाहिए था कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रखंड स्तर पर विद्यालय खोले जाएं और महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जोर-शोर से चर्चा हुई है, जोर-शोर से चर्चा हुई है पिछले तीन वर्षों में इंदिरा आवास मद में 2143 करोड़ रुपया बिहार को अनुसूचित जाति के लिए प्राप्त हुआ लेकिन इस सरकार ने इन पैसों का इस्तेमाल अनुसूचित जाति के आवास बनाने पर नहीं किया बल्कि इसको दूसरे मद में ट्रांसफर कर दिया । इसी वजह से यदि वह 40 परसेंट मिलाते तो 3 हजार करोड़ रुपया होता, इसी वजह से 3 साल में डंके की चोट पर कह रहे हैं, महोदय । मात्र 61 अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है पूरे बिहार में, यह स्थिति है । महोदय, अनुसूचित जाति के पैसों का बंदर-बांट हो रहा है इसलिए हम चाहते हैं इस सदन से कि अनुसूचित जाति के पैसे की मॉनिटरिंग के लिए विधान सभा की एक कमेटी बननी चाहिए ताकि उसके पैसे को कहीं डायवर्ट नहीं किया जा सके, हम यह चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर अनुसूचित जाति के तमाम फंड के क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी बननी चाहिए, महोदय और जो...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री सतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, हल्ला-गुल्ला में शुरू में मेरा समय बर्बाद हुआ था । महोदय, हम बोलना चाहते हैं कि जो भी अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बिहार में चल रहे हैं, मंत्री जी तो नहीं घूमते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी घूमते थे, महोदय । मैं घूमता हूं, यदि 384 बच्चों का नामांकन है तो मात्र 83 या 85 बच्चे उस विद्यालय में निवास करते हैं लेकिन खाना का पैसा 384 बच्चों का ही निकलता है, यह है घोटाला बिहार में, यह है अटेंडेंस घोटाला पूरे बिहार के आवासीय विद्यालयों में चल रहा है, इसकी जांच कराई जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात है कि बिहार में 80 हजार अनुसूचित जाति के बैकलॉग पद खाली हैं, उन्हें सरकार कब भरेगी ? यदि सरकार बैकलॉग को भर दे

तो हरेक घर को एक नौकरी मिल सकती है, उस बैकलॉग को भरने का क्या सरकार के पास में कुछ न्याय के साथ विकास दलितों की तरफ भी पहुंचाने का है कि नहीं । इसलिए हम यह कहना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

श्री सतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में एक लाइन बोलकर हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं कि दलितों की जो स्थिति बिहार में बन गई है, वह निराला जी की कविता है, महोदय ।

''चाट रहे थे जूठे पत्तल, वह सड़क पर खड़े हुए ।
और झपट लेने को उनसे, कुत्ते भी थे अरे हुए ।।''

महोदय, यह स्थिति बिहार में बना दी गई है । इन्हीं बातों के साथ हम आपका, इस पूरे सदन का आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत कुमार सिंह ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तीन-चार विभागों पर आज बातचीत है । मुझे लगता है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार को भी इस विभाग के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसलिए मैंने आज तमाम विभागों में से इसी विभाग को चुना है और मैं इसी विभाग पर अपनी बात को रखना चाहता हूं । महोदय, संस्कृति का प्रश्न आर्थिक प्रश्न से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । किसी भी व्यक्ति या समाज की संस्कृति उसकी जीवनदायी शक्ति को बढ़ाता है, दुर्भाग्य से बिहार सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है । कालिदास रंगालय, संगीत टाटा अकादमी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान आदि हमारी सांस्कृतिक विरासतें अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं । महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां की जन्मस्थली है । जब बक्सर में गंगा के किनारे वे शहनाई बजाते थे तो पूरी दुनिया में उनकी धुन गुंजती थी, उस महरूम उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म डुमरांव में हुआ था लेकिन महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि एक भी डुमरांव में ऑडिटोरियम या कुछ भी आज तक उस महान कलाकार के नाम पर नहीं है, यह दुखद है । बिहार के इतने बड़े विरासत को, बिहार की सरकार ने न सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तक मिला उनके नाम पर कुछ भी नहीं है । हमने पिछले दिनों उस्ताद बिस्मिल्ला खां के

नाम पर कला विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी लेकिन लगता है कि उसको भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया । उस्ताद बिस्मिल्ला खां विश्वविद्यालय...

(व्यवधान)

पास तो बहुत कुछ है, बनता कितना है, बात तो बनने पर होनी चाहिए और यह तो आपकी बात बता रही है कि आप सिर्फ आंकड़े देते हैं कि वर्ष 2013 में पास है लेकिन वर्ष 2022 तक नहीं बना तो यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है, जिसको आप खुद बता रहे हैं तो महोदय, यह कला विश्वविद्यालय नहीं बना । महोदय, पटना म्युजियम को यूनेस्को द्वारा इसको चिन्हित किया गया और दुनियाभर में विख्यात है, हम बिहार से आते हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार बुद्ध की सरजमीं है, बुद्ध जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा, विनम्रता, प्रेम और मोहब्बत की पाठ पढ़ाई, वह बुद्ध जिसने कहा कि युद्ध जरूरी नहीं है, बड़े-बड़े समस्याओं को प्रेम से हल किया जा सकता है । उसके पहले किसी ने भी प्रेम का इस तरह का प्रयोग नहीं किया जिस तरीके से बुद्ध ने किया और बुद्ध पूरी दुनिया में विख्यात हुए । हालांकि, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुद्ध को लेकर थोड़ा सा चिंतित जरूर हैं लेकिन उनकी चिंता इतनी नहीं है कि बुद्ध के समय के साहित्य और संस्कृति को संरक्षित रख सकें । महोदय, पटना संग्रहालय में यहां के सबसे बड़े विद्वान ज्ञानी महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जिनको दुनियाभर में लोग जानते हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-20/पुलकित

(क्रमशः)

श्री अजीत कुमार सिंह : उन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की तो तिब्बत में बौद्ध के साहित्य और संस्कृति की खोज में गये और बहुत सारी पाण्डुलिपियां खच्चरों पर लादकर तकरीबन छह हजार खच्चरों पर लादकर पटना लाया गया, पटना संग्राहालय में उन पाण्डुलिपियों को रखा गया । पटना संग्राहालय न सिर्फ पाण्डुलिपियों की वजह से बल्कि एक बेहतरीन स्थापक की कला के मामले में भी दुनिया भर में प्रचारित है । आज बिहार म्यूजियम बनाकर, उसको एन0जी0ओ0 के अंदर देकर सरकार पटना म्यूजियम की उस शानदार विरासत को तहस-नहस कर देना चाहती है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पटना संग्राहालय जो दुनिया का अप्रतिम संग्राहालय है और जहां वे सब चीजें रखी गयी है जिसकी जरूरत आने वाले समय में बिहार के शोधार्थियों को उसकी जरूरत होगी उसको नष्ट नहीं किया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह मांग करूंगा कि उसकी सुरक्षा की वे गारंटी करे । महोदय,

मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूं । भोजपुरी पर हमें बहुत गर्व होता है और भोजपुर पर मैं अपनी बात भोजपुरी में ही कहना चाहता हूं ।

(भोजपुरी का अनुवाद हिन्दी में)

हुजूर, भोजपुरी का विस्तार न सिर्फ, देश के अंदर दूर-दर्जन जिलों में हैं बल्कि दुनिया में मॉरिशस, ट्रिनिदाद, टोबेगो, सूरिनाम और कई देशों में हैं । महोदय, भोजपुरी का इतिहास है । आप लोग सुनिये । हम लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर अंग्रेज देश से बाहर ले गये तो हमने माफी नहीं मांगी बल्कि हम वहां के राजा हो गये । हमने राज किया लेकिन आज हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति की कोई बात नहीं हो रही है । प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे लेकिन इतनी समृद्ध विरासत की भाषा होकर जहां के वीर कुंवर सिंह, तेग बहादुर आज भी जब पूरा बिहार होली गाता है तो यही गाता है कि बाबू कुंवर सिंह, तेग बहादुर यहीं से शुरू होता है । उस सरजमीं की आज कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है हम कहना चाहते हैं भोजपुरी को लेकर बिहार में कोई काम नहीं हुआ । भोजपुरी का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, भोजपुरी का एक भी कॉलेज नहीं है । वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक विभाग है लेकिन उसमें भी कभी पढ़ाई होती है, कभी बंद हो जाती है । महोदय, हम मांग करते हैं कि भोजपुरी की पढ़ाई लोकल विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक में हो । दूसरे, भोजपुरी संस्कृति की जो विरासत है, अभी हाल ही में आप जानते हैं भिखारी ठाकुर जिनको शेक्सपियर की संज्ञा दी गई, जिनके नाटक में उस घड़ी के प्रतिरोध की संस्कृति झलक रही थी । उसी नाटक मंडली के एक व्यक्ति रामचंद्र मांझी 90 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी मिला लेकिन महोदय, यह कहते हुए मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है कि बिहार की सरकार उन रामचंद्र मांझी का हालचाल तक पूछने नहीं गई । जो रामचंद्र मांझी बिहार ही नहीं, भोजपुर ही नहीं बल्कि देश के अंदर नाट्यकला को प्रदर्शित किए थे । महोदय, लौंडा नाच आज बर्बाद हो चुका है । जो लौंडा नाच भोजपुरी की संस्कृति की सभ्यता की, उस समय की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतिरूप था । हम मानते हैं कि लौंडा नाच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बजट में प्रावधान लाए । हुजूर, कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है, विधायक बनने से पहले हम छात्र नेता थे। पटना आर्ट कॉलेज में एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, शब्द हो सकता है असंसदीय हो जाय बहुत खराब निकल रहा है, उसको प्रभावी बना दिया । वहां 19 महीना आंदोलन चला लेकिन बहुत दिनों के बाद बात सुनी गई, आज नाट्क करने

वाले विद्यार्थियों की खातिर किसी भी कला की व्यवस्था नहीं है । कहीं नाट्य कला के विद्यार्थियों के लिए बहाली नहीं है । एक कला के लिए 2013 में बहाली निकली थी अब जाकर पूरे होने वाली है लेकिन इसके अलावा 300 के अलावा पूरे बिहार में कोई बहाली नहीं हुई । ऐसे हम आपसे मांग कर रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में काम करने वाला, ललित कला के क्षेत्र में काम करने वाला, सब क्षेत्र में नाट्य कला के क्षेत्र में काम करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बहाल किया जाय और कलाकारों के लिए हर जिला में ऑडिटोरियम होना चाहिए । जहां लोक कला के विकास पर बात हो सके, जहां नाटक हो सके, जहां गीत, संगीत, नृत्य का माहौल हो सके । महोदय, आप बताइये कि कितने जिलों में ऑडिटोरियम बना है, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां कोई ऑडिटोरियम नहीं है । जहां कला, संस्कृति के अलावे किसी राज्य और समाज के विकास की आप कल्पना कर सकते हैं, हम समझते हैं कि आप कितनी नली बना लें, कितनी गली बना लें, कितनी रोड बना लें अगर संस्कृति न बची तो सब विनिष्ट हो जायेगा । आपका रोड और नली सब धरा रह जायेगा । यहां वह किसी काम नहीं आयेगा । इसलिए महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कला, संस्कृति के साथ युवा भी जुड़ा हुआ है । हमने एक बहुत पुराना शेर सुना है –

''कि जिस ओर जवानी जलती है, उस ओर जमाना चलता है ।''

आज युवाओं का क्या हाल है ? मैं किस युवा की बात करूं उस युवा की जिसकी नौकरी आप खा रहे हैं और जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनपर लाठियां चला रहे हैं या उस युवा की बात करूं जिसको रेलवे के आंदोलन में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया या उस युवा की बात करूं जिस युवा का ज्वाइनिंग लेटर आया है और आपका प्रशासन उसको वेल तक नहीं दे रहा है कि जाकर के वह नौकरी ज्वाइन कर सके । हम किस युवा की बात करें । हजारों, लाखों युवा जो टेट, बी0ई0टी0, सी0ई0टी0 दुनिया भर की नौकरियों की बहालियों के लिए रोज गर्दनीबाग में आकर के धरना देते हैं या उन युवाओं की बात करूं जिन पर रोज आपकी पुलिस लाठियां चलाती है । हुजूर, हम तो यह सोच रहे हैं कि क्या इस दौर में, इस रिजीम में युवा होना अपराध है । क्या, हम नौकरियों की मांग नहीं कर सकते हैं, इसलिए महोदय, हमारा सवाल और युवाओं की नौकरी के सवाल पर अगर बात करते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है । युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करना, आपने क्या किया, खेलो इंडिया का नाम लम्बे समय से प्रचारित हो रहा है लेकिन क्या आज तक आपने कहीं भी खेल के लिए किसी स्टेडियम का निर्माण कराया । हम देख रहे हैं कि कहीं भी किसी स्टेडियम का निर्माण नहीं

हुआ है । रोज बातें आती है हमलोग विधान सभा में सवाल उठाते हैं, सरकार कहती है सिर्फ जवाब में कि विचाराधीन है । आपका खेलो इंडिया कहां गया ? एक साल में खेलो इंडिया ने पूरे बिहार में एक भी काम नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं दावे के साथ यहां खड़ा होकर के इस बात को कह रहा हूं । किसी ने कुछ नहीं किया । इसलिए महोदय, अंतिम बात कहते हुए कि कला और संस्कृति को संरक्षण देना बिहार विधान सभा की जिम्मेदारी है । लेकिन हमने देखा कि बिहार विधान सभा का जो बोर्ड आपने लगाया है उसमें बिहार में जो उर्दू में नाम लिखा हुआ था वह गायब हो गया । महोदय, उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है और हम समझते हैं कि उर्दू के लब्ज हमारी बातों की शोभा को बढ़ाते हैं । इसलिए हुजूर एक शायरी बहुत छोटी सी है –

''हिन्दी और उर्दू में एक फर्क है तो इतना,
वो ख्वाब देखते हैं और हम देखते हैं सपना ।''

बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोहम्मद अनजार नईमी ।

मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, पथ निर्माण विभाग का आजकल बिहार में जमीनी विकास से ज्यादा कागजी विकास ज्यादा नजर आता है । विभाग सड़क की केवल निविदा देता है, काम कहीं नजर नहीं आता है । हम सीमांचल के किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज विधान सभा से आते हैं । हर साल कटाव से परेशान रहते हैं, बाढ़ के बाद सड़कों की स्थिति जर्जर हो जाती है । लेकिन उसमें आजतक डी0पी0आर0 का काम नहीं हो पाता है । महोदय, बिहार सरकार की पंचायती राज व्यवस्था में पावर की बात चल रही है । कभी बी0डी0ओ0 को दी जाती है, कभी बी0पी0आर0ओ0 को दी जाती है । महोदय, आपस में सब उलझ गया है, काम कहीं नहीं हो रहा है । सरकार की कागजी विकास पर मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं । महोदय, सीमांचल के लोग हर साल उम्मीद लगाये बैठे रहते हैं लेकिन होता क्या है ? महोदय, एक शेर कहना चाहता हूं –

''दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है,
लम्बी है गमों की शाम, मगर शाम ही तो है ।''

महोदय, सरकारे आती है, सरकारे जाती है लेकिन हर वर्ष सीमांचल के लोगों की उम्मीद बिखर जाती है । महोदय, अपने विधान सभा क्षेत्र बहादुरगंज सहित सीमांचल के कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं । बहादुरगंज से तेहराघाट

को जोड़ने वाली बस एक मात्र पी0डब्लू0डी0 की सड़क है अभी अपना बेबसी का रोना रो रही है । आये दिन दुर्घटना होती रहती है, महोदय लोग परेशान हैं । सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने के कारण हर दिन घटना होती रहती है । महोदय, इसका टेंडर वर्ष 2015 में हुआ था लेकिन आज तक इस सड़क का काम कम्प्लीट नहीं हुआ । महोदय, लोग परेशान रहते हैं । अगर सीमांचल की बात करें तो हर जगह वही हाल है, बायसी विधान सभा का एक मात्र ई0एम0बी0डी0 रोड आजतक अपनी बेबसी का रोना रोता है । दुर्घटनाएं आये दिन इसकी नीयति बन गयी है लेकिन इसमें आजतक विकास का कोई काम नहीं हुआ है । महोदय, जोकिहाट विधान सभा का भी यही हाल है जोकिहाट से दलमालपुर, पूर्णिया सीमा तक एवं उदाकिशुनगंज सड़क जिसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है इसके चौड़ीकरण की मांग काफी दिनों से हो रही है, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है ।

(क्रमशः)

टर्न-21/सत्येन्द्र/17-03-22

श्री मो0 अनजार नईमी(क्रमशः) कला संस्कृति विभाग की बात करें तो महोदय, भारत सबसे युवा देश है और बिहार सबसे युवा प्रदेश है । महोदय, हमारे यहां युवा कौशल के संसाधनों के न होने के कारण लाखों प्रतिभावान युवा हरेक साल या तो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं या तो बेरोजगारी बेगारी में घुम रहे हैं । महोदय, हमारा विधान-सभा क्षेत्र सीमावर्त्ती इलाका में आता है और हमारे यहां दलितों की अधिकांश आबादी बसती है । हमारे यहां बहादुरगंज में एक भी एस0सी0 एस0टी0 का होस्टल नहीं होने के कारण हमारे यहां के बच्चे सही से, हमारे जो एस0सी0एस0टी0 के बच्चे हैं वे सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ सरकार से कि हमारे क्षेत्र में एस0सी0 एस0टी0 का एक छात्रावास बनाया जाय जिससे हमारे क्षेत्र के आदिवासियों का विकास हो सके । धन्यवाद ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझीः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग की ओर से लाये गये बजट का मैं समर्थन करते हुए विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, आज महादलित आयोग की ओर से जितना काम किया जा रहा है एस0सी0एस0टी0 के बीच और आदरणीय नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी काबिलेतारीफ जो काम किये हैं उसके लिए हम उनको बिहार की जनता की ओर से, एस0सी0एस0टी0 की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं । साथ ही साथ बिहार में

जो पथ निर्माण का कार्य किया गया है वह तो और देखने की बात है । महोदय, जब हम बिहार की सड़कों पर चलते हैं, दिन में चलते हैं तो अब रफ्ता रफ्ता की बात नहीं होती है हम तेजी से चलते हैं और जब गाड़ियां चलती है और जो सड़क की सुंदरता और बनावट है वह देखने लायक होती है, खासकर जब रात में चलते हैं, पहले जब हम रात में चलते थे सड़क पर तो सड़क पर जिंदा भूत पाया जाता था वह आने जाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से तंग करता था वह भी जगजाहिर होता है और आज जब चलते हैं, रात में चलते हैं तो लगता है कि बिहार की सड़कों पर दिवाली का एक जश्न है । जगह जगह लाल और पीली बत्तियों का प्रकाश रोड पर आता रहता है तो व्यक्ति को अनुभव होता है कि रोड नहीं स्वर्ग का नाजारा है । साथियों, हंस लीजिये लेकिन सुन लीजिये

मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ।

साथियों, अभी हम बात कर रहे थे चूंकि हम एस0सी0 से आते हैं तो ज्यादा तो हम अनुसूचित जाति के बजट पर ही अपनी बातों को रखेंगे । साथियों, महादलित विकास मिशन की ओर से जो दलितों के बीच कार्यक्रम चलाया गया है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहें प्राक् शिक्षा के क्षेत्र में हो, पहले कोई जनता यह नहीं सोचती थी कि हमें पढ़ने के लिए जब हम बी0पी0एस0सी0 के पी0टी0 में आ जायेंगे तो 50 हजार रू0 सरकार देगी और जब यू0पी0एस0सी0 के पी0टी0 में आ जायेंगे सरकार एक लाख रू0 देगी । ये वर्त्तमान समय में ही होता है , पिछले दिनों की बात छोड़ दीजिये, क्या होता था हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे लेकिन वर्त्तमान समय में जो होता है जो बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हम उसको बतला रहे हैं और साथियों बहुत सारी बातें है उसको कहना है इसलिए हम आग्रह करेंगे अनुसूचित जाति के माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में 2300 रू0 प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे को खाने के लिए देती है लेकिन बहुत कम रेट पर 1300 या 1200 रू0 पर संवेदक द्वारा टेंडर डालकर ठीका ले लिया जाता है और वह भोजन ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्षः अब समाप्त कीजिये आप ।

श्री विजय कुमार चौधरीः महोदय, माननीय सदस्य ललित जी को सीधी रेखा और वक्र रेखा में फर्क समझना चाहिए । जैसे आपके सोचने का तरीका वक्र है वैसे ही ये देख रहे हैं, सीधे से, मैं कहीं क्रॉस नहीं किया है, मैं सिर झुकाकर इधर से आया हूॅं इसलिए अपनी सोच की वक्रता को सदन में न लायें ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

(व्यवधान)

अब आपके सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी: उपाध्यक्ष महोदय, एस0सी0एस0टी0 के जो मामले देखते थे उसके लिए एक आरक्षण आयुक्त की बहाली की जाती थी उसके लिए आरक्षण आयुक्त होते थे लेकिन वर्त्तमान समय में हम आपके माध्यम से मंत्री जी आग्रह करेंगे कि आरक्षण आयुक्त की नियुक्ति की जाय । साथ ही साथ हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो यह ड्रिम प्रोजेक्ट था कि शिक्षा का दर बढ़ाया जाय अनुसूचित जातियों में उसके लिए शिक्षासेवक बहाल किया गया, उसके लिए विकास मित्र बहाल किया गया, उनका मानदेय बहुत कम मिलता है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाय । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती संगीता कुमारी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सचेतक श्री ललित जी को और धन्यवाद देना चाहूंगी अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और पार्टी को जिन्होंने मुझे मौका दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं अनुसूचित जाति जन जाति विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सड़कों की बात करनी है और चूंकि सरकार दावा करती है कि इतने राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे द्वारा इतने पुल का निर्माण किया जा रहा है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि सरकार जो सड़कों का निर्माण करवाती है, एक साल होते होते वह सड़कें अपना रूप दिखा देती है, दम तोड़ती हुई सड़कें दिखाई देने लगती है और जो रोड का डी0पी0आर0 होता है, प्राक्कलन होता है, उसके अनुसार रोड का निर्माण नहीं होता है । मैं जिस विधान-सभा क्षेत्र से आती हूँ वह है मोहनिया विधान-सभा क्षेत्र । वहां का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वहां सड़कें तो बनी है लेकिन एक घनी आबादी से होकर जो एन0एच0 उस क्षेत्र से गुजरता है, घनी आबादी वहां पर है जब वहां सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो वहां के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया । वहां की आबादी जो है, भभुआ रोड स्टेशन के उतर कर अगर किसी को अनुमंडल जाना हो तो उसे 20कि0मी0 का रास्ता तय करना पड़ता है , कभी कभी तो लोग सौर्टकट रास्ता पकड़ने के लिए एन0एच0 पार करना चाहते हैं जिससे कई युवा और लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं । महोदय, जब ये रोड बन रहा होता है तो उस समय अंडर पास निर्माण के लिए

क्यों नहीं सोचा गया, वहां के घनी आबादी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूॅ कि मोहनिया विधान-सभा के मोहनियां में अंडर पास निर्माण कराया जाय जिससे कि गर्भवती महिलाएं को उन्हें सरकारी अस्पताल में जाना हो तो उनको कम से कम आधा घंटा के जाम से निजात मिल जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कैमूर जिला में मॉ मुंडेश्वरी मंदिर भी है और वहां चांदनी चौक जो मोहनिया में आता है, वही एक रास्ता है जिससे होकर हम वहां मॉ मुंडेश्वरी मंदिर जा सकते हैं । एक वही रास्ता है जिससे होकर वहां की पूरी आबादी गुजरती है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी अगर हमारे क्षेत्र में दौरा के क्रम में गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हमेशा वहां जाम की स्थिति बनी रहती है । वहां बाईपास की व्यवस्था नहीं है, एक ही रास्ता होने की वजह से ऐम्बुलेंस वहीं रूक जाता है तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूॅ कि वहां पर जल्द से जल्द चांदनी चौक पर जाम की समस्या को कम करने के लिए बाईपास का निर्माण कराया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मोहनिया भभुआ रोड से अनुमंडल जाने के लिए वहां अंडरपास का निर्माण कराया जाय । नाला का सही निर्माण एन0एच0 के किनारे नहीं कराये जाने से कुदरा के पुसौली के फकराबाद में हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है और जब विभाग से बात किया जाता है तो सिर्फ टालमटोल किया जाता है । (क्रमशः)

टर्न-22/मधुप/17.03.2022

..क्रमशः..

श्रीमती संगीता कुमारी : तो मैं फकराबाद का भी जिक्र करना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी इसपर थोड़ा ध्यान देंगे । माननीय मंत्री महोदय, एक बात कहना चाहती हूॅ कि कुदरा प्रखंड हमारे क्षेत्र में आता है जहॉ पर कुदरा लालापुर क्षेत्र है, जहॉ से अगर लोगों को बाजार जाना हो तो उन्हें 3 कि0मी0 की दूरी का रास्ता तय करके जाना पड़ता है । मैंने प्रश्न भी उठाया है लेकिन मैं सरकार की और माननीय मंत्री जी की कृपा-दृष्टि इसपर चाहूॅंगी कि जल्द से जल्द अगर अंडरपास का निर्माण करा दिया जाता है तो वहॉ के लोगों को सुविधा मिल जायेगी ।

एक बात, सदन में जब पहली बार मैं पहुॅंची तो मैंने जिक्र किया था, कुदरा रामपुर पुल के निर्माण की बात की थी । मैं हमेशा से सुन रही हूॅ, विद्यार्थी जीवन से मैं सुन रही हूॅ कि इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, किया जा रहा है लेकिन आज तक वही स्थिति है । जब उस प्रश्न को मैंने विधान सभा में उठाया तो स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा, उस विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा गलत इनफॉरमेशन सरकार को दी गयी

जिसकी वजह से वह काम पेंडिंग है । महोदय, कुदरा रामपुर पुल का निर्माण कराने की मैं सरकार से माँग करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द कराया जाय जिससे लगभग 25 पंचायत का रास्ता है । यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी बस उधर नहीं जाती हैं । लोकल गाँव के लोगों ने अपने खर्च पर एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया है । जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में सड़कों की बात हो, गलियों की बात हो, पुल के निर्माण की बात हो, वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा हो तो निश्चित रूप से सरकार पर यह सवाल खड़ा उठता है कि सरकार किस तरह की 21वीं सदी की बात करती है ।

माननीय मंत्री महोदय, दरभंगा जिला के टालसराय मुरिया पथ में पक्की नाली का सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था 01 मार्च, 2017 को जो प्रश्न हुआ था, उसी समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था । विभाग द्वारा उसका प्राक्कलन भी बनाया गया लेकिन विभाग के लालफीताशाही के चलते आज तक काम नहीं हुआ । इसलिये उस सड़क में अविलम्ब नाला का निर्माण कराया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के बारे में भी बोलने का अवसर है । चूंकि मैं भी दलित परिवार से आती हूँ, मैं दलित परिवार की बेटी हूँ । एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि

''जूते फटे पहन कर आकाश पर चढ़े थे,
मेरे हौसले हमेशा हमारे औकात से बड़े थे ।''

महोदय, प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधनों पर समान रूप से सबका अधिकार दिया लेकिन जब मनुष्य विकसित होते गया, कालांतर में मानव के मस्तिष्क में जब बुराईयां विकसित होती गई तो समाज के कुछ लोगों ने प्राकृतिक संसाधन पर अपना एकाधिकार कर लिया और अपने साथ रह रहे लोगों को पशुत्व की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जिसे हम आज दलित कहते हैं और समाज में रह रहे जो प्रकृति की गोद में रहने को मजबूर हो गये लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर जिसका अधिकार नहीं हुआ जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं ।

महोदय, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिये गये संविधान के उन प्रावधानों की वजह से आज हम इस सदन में खड़े हैं । निश्चित रूप से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब देश की स्वतंत्रता की बात थी और देश में पहली बार 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की बात की, अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति की बात की, उस समय देश की स्वतंत्रता के समय हमारे देश के संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्यभार को सम्भाला, उस

समय के रहनुमाओं ने आरक्षण का प्रावधान किया, आरक्षण से उस जाति के लोगों को संरक्षण दिया । लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है । आरक्षण कोई भीख नहीं है । गाहे-ब-गाहे हमारे आरक्षण पर सवाल उठता है लेकिन यह कोई भीख नहीं है ।

मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, दलित अम्बेडकर छात्रावास की मैं बात करना चाहती हूँ, अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों की मैं बात करना चाहती हूँ, अभी विधान सभा की अनुसूचित जाति-जनजाति की पिछले साल की रिपोर्ट में यह पेश हुआ कि जो जेल में कैदी हैं उनसे भी बदतर स्थिति है अम्बेडकर छात्रावास में रह रहे बच्चों की । एन0जी0ओ0 के माध्यम से उन्हें जो अनाज दिया जाता है, खाने की व्यवस्था की जाती है, मैं उस मानसिकता की बात करती हूँ उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति के नाम के आगे जब दलित शब्द लग जाता है तो समाज की जो एक सोच है वह बदल जाती है क्योंकि यह दलित व्यक्ति है, उसकी सोच अलग होगी, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगता है, उसकी क्षमता का आकलन कम किया जाता है । आई0आई0एम0 की बात मैं करूंगी, प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करूंगी, अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति वहाँ प्रोफेसर हैं, अनुसूचित जाति के कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में तो शिक्षा का स्तर यह है जहाँ पर बच्चों को थाली और चम्मच दे दिया जाता है । पढ़ाई की गुणवत्ता की बात की जाय तो वहाँ नियोजित शिक्षक, सरकारी शिक्षक और टोला शिक्षकों को लेकर फँसाया जाता है ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : मैं सरकार से यह माँग करना चाहती हूँ कि टोला सेवकों को, विकास मित्र को, जो दलितों की बात करते हैं, टोला सेवकों के द्वारा आप जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करवाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल यह अच्छा काम है लेकिन टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया जाय, विकास मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाय ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्रीमती संगीता कुमारी : सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करे क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आज भी दलित बच्चे और बच्चियाँ ही पढ़ते हैं । 99 प्रतिशत दलित परिवार के बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । डॉ0 सत्येन्द्र यादव ।

श्रीमती संगीता कुमारी : कहीं न कहीं सरकार की मंशा रहती है कि शिक्षा ग्रहण नहीं कराने का कहीं सरकार का तरीका तो नहीं क्योंकि अगर जिस दिन दलित समाज शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वह समानता की बात करेगा, वह संविधान की बात करेगा, राइट टु इक्विलिटी की बात

करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दिये गये आर्टिकल 14 की बात करेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव, पंचायती राज और पथ निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, सरकार जिस तरह से दावा कर रही है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, हमारे साथियों ने बहुत सारे विषयों पर अपनी बात को रखा है लेकिन सारे विषय अपनी जगह हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग पूरे बिहार की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत के हिस्से में आते हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में खास तौर से भूमि का जो सवाल है, उनकी हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी बिहार के अंदर कम है और इसलिये आज आवास की जमीन उनकी प्राथमिकता में है । जमीन नहीं होने के चलते उनको आवास बनाने में कठिनाई हो रही है । सरकार आवास के लिए जमीन की योजना चला रही है, जमीन देने के बजाय कुछ रूपये की बात की जा रही है लेकिन सरकार जो रूपया देना चाहती है भू-अर्जन के लिये, उससे आवास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकता है । उसके साथ-ही, टोले बसावट जो दलितों की बड़ी आबादी है, आज भी उस तक कनेक्ट करने का सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के पास पैसे नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि आवास के लिए भूमि, उनके टोले के बसावट के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन का अभाव है जिसके चलते दलितों के आवास के लिए जमीन नहीं मिल रही है, उनके टोले का कनेक्शन नहीं है । इससे भी बड़ा भेदभाव कुछ नहीं किया जा सकता है । सभी के लिए बजट है लेकिन टोले बसावट के लिए हमारी सरकार कटोरा लेकर ब्रिक्स के पास पहुँची है कि हमको ब्रिक्स पैसा देगा 6 हजार करोड़ तो टोला बसावट को कनेक्ट करेंगे । हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए आवास की जमीन और टोले बसावट के लिए विशेष बजट का प्रोवीजन होना चाहिए ।

मैं कहना चाहता हूँ, पंचायती राज विभाग पर बड़ी चर्चाएँ हैं, पंचायती राज मंत्री अभी नहीं हैं, बिजली मंत्री नहीं हैं, एक बात बिजली मंत्री और पंचायती राज मंत्री को बताना चाहिए कि यह सोलर लाइट का जो प्रोजेक्ट लेकर आये हैं, इस सोलर लाइट की बिहार के अंदर अगर बिजली है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है । जरूरत नहीं है तो इस बात को नहीं करना चाहिए । बड़ा फोकस पंचायती राज मंत्री देते हैं सोलर लाइट पर। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सोलर लाइट पर जितना आपका फोकस है अगर पंचायत के अंदर आप कबीर अंत्येष्टि पर फोकस करते तो गरीबों के जो लाश उनके दरवाजे पर कफन के लिए पड़े रहते हैं लेकिन आपने प्रोवीजन किया कि...

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : ऑनलाईन होगा और ऑनलाईन एकाउंट में पेमेंट होगा । आप पैसा एक महीना बाद भेजोगे, उसके कफन के लिए लाश पड़ा रहेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग को अपने नियमों में संशोधन करके सीधे पंचायत को यह अधिकार दें कि कफन का पैसा, कबीर अंत्येष्टि का पैसा मौत के बाद तुरंत उसके परिजन को दिया जाय, ऑनलाईन प्रोवीजन खत्म किया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री सुर्यकांत पासवान जी ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि नल जल योजना जो चल रही है, उसको रिपेयर के लिए आपने पैसा दिया है, पहले भी आप पैसा बर्बाद कर चुके हैं ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

टर्न-23/आजाद/17.03.2022

श्री सूर्यकांत पासवान : उपाध्यक्ष महादेय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खडा हुआ हूँ । महोदय, आज राज्य की जो स्थिति है, खासकर के आज मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सवाल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । इस सरकार में सबसे खास्ता हाल हुआ है तो वह दलित है, अनुसूचित जाति है । इसी सरकार में दलित और महादलित बनाने का काम किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि दोनों को आपने अलग किया तो दलित को क्या दिया और महादलित को क्या दिया ? इसको तो आपने बनाया लेकिन इनको आज तक तवज्जो आपने नहीं दिया । आज बिहार के अन्दर अगर हमारे दलित को नौकरी में है तो उनको प्रोन्नति आपकी सरकार ने नहीं दिया है । महोदय, यह बात सच है कि उनका प्रोन्नति रूका हुआ है । आपने इस देश में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, उनको निजी क्षेत्र में दे रहे हैं और उनको आप बेच रहे हैं और झूठा आरक्षण का आप ढिढ़ोरा पीट रहे हैं । आरक्षण जब सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, तभी आप हमारे महादलित, दलित, अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी दे सकते हैं । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप जो बड़े-बड़े कम्पनी को सार्वजनिक क्षेत्र में दे रहे हैं, आप उसमें भी दलित और महादलित को आरक्षण दें, यह मैं सदन से मांग करता हूँ । आपने चर्चा किया है, हमारे मित्र ने बाबा साहेब अम्बेदकर का चर्चा किया, डॉ0 बाबा भीम राव अम्बेदकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान में आप छेड़-छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार के द्वारा इसमें छेड़-छाड़ करने की साजिश हो रही है । आपने पिछले दिनों याद होगा पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने पूरे हिन्दुस्तान का चक्का जाम

किया था, तब उस कानून को आपने वापस लिया । नहीं तो जो हालात हमारे इस देश के दलितों का होता । बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान के बदौलत आज हम सदन में बोल रहे हैं ।

महोदय, अब मैं पथ निर्माण की बात करता हूँ । मैं पिछले बार चर्चा किया था और इस बार पथ निर्माण मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बलिया से लेकर के डंडारी होते हुए, बखरी होते हुए, गरपुरा होते हुए रोसड़ा तक उस सड़क की चौड़ीकरण हो । महोदय, जब आपने मुंगेर घाट का पुल बनवाया है तो उस रूट से अगर गाड़ी चलेगी तो एस0एच0 पथ बनवाया जाय । इससे 40 से 50 कि0मी0 की दूरी कम होगी महोदय और आपलोग सीधे उत्तर बिहार की ओर कूच करेंगे ।

महोदय, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आवासीय विद्यालय का और एक उदाहरण देना चाहता हूँ । मेरे जिला बेगूसराय के अन्दर एकमात्र आवासीय विद्यालय भर्रा में है महोदय । मैं उस विद्यालय को अपने आँखों से जाकर देखा है । महोदय, भवन नहीं है, भवन जर्जर है, हमारे विद्यार्थी चौकी पर चौकी जोड़कर उस विद्यालय में रहने का काम करते हैं । न पठन-पाठन की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है । महोदय, स्थिति बद से बदतर है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी आवासीय विद्यालय बिहार के अन्दर हैं महोदय, उस विद्यालय की विधि-व्यवस्था दुरूस्त करने की ओर सरकार अग्रसर हो ।

महोदय, अब नल-जल की बात करते हैं । बिहार के अन्दर .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, एक मिनट । सरकार ने नल-जल योजना चलाया । आज पंचायत में पंचायत के अन्दर नली-गली रोड बना लेकिन नल-जल योजना के तहत उस रोड को खाई में तब्दिल कर दिया गया । महोदय, अंत में मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि आपका जो वार्ड सदस्य है, पंच है, सरपंच है .....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा ।

श्री सूर्यकांत पासवान : वह आपकी रीढ़ हैं और उनका मानदेय आज न्यूनतम मजदूरी से भी कम है । मैं मांग करता हूँ कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को न्यूनतम मजदूरी सरकार दे ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं सदन में विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, मैं सबसे पहले गरीब, गरीबों का मसिहा दलित, शोषित, पीड़ितों के उदारक आदरणीय श्री बाबू लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस सदन में भेजने का काम किया ।

महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बिहार के सबल प्रहरी विपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिन्होंने आज एक दलित मुशहर के बेटा को इस सदन में पहुँचाने का काम किया और अपनी बातों को रखने का समय दिया । महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय नेता श्री ललित कुमार यादव जी को जिन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया । महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ अलौली के उन महान जनता मालिकों को जिन्होंने मुझ पर अटूट भरोसा और विश्वास जताया । महोदय, इस बजट में सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्कीम मद में 1414.95 करोड़ रू0 स्थापना एवं प्रतिवर्ष व्यय मद में 314.65 करोड़ रू0 कुल 1729.60 करोड़ रू0 के बजट की चर्चा की गई है । हमने देखा है कि बजट के किताब में लिखा था - कोटिल्यशास्त्र की युक्ति - जो प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करना चाहिए, जो प्राप्त हो गया है, उसे संरक्षित करना चाहिए और जो संरक्षित हो गया है, उसे समानता के आधार पर बंटवारा करना चाहिए । महोदय, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपकी सरकार में इस तरह का नारा है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे में सबका साथ और सबका विकास आप कैसे कर सकते हैं, जब बजट में आप सबके लिए विवरण ही अन्यायपूर्ण है तो विकास आपका कैसे होगा ? महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था को न्याय कहेंगे तो अन्याय किसे कहेंगे ? हम कहना चाहते हैं कि आज राज्य में जो परिस्थितियां हैं, सुशासन और न्याय के बदले कुशासन और अन्याय कहना उचित होगा । इस बजट में यह भी आना चाहिए कि विगत वर्ष में कितना पैसा पास हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, बचा तो क्यों बचा और जो पैसा आपने बजट में दिया, वह पैसा जो है, वह पैसा सरजमीं पर खर्च हुआ कि नहीं हुआ ? यह भी बजट आना चाहिए और यह बजट के माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सरकार जो बजट देती है, वह पैसा खर्च करना यही आपका धर्म और न्याय है तो मैं सुशासन की सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप अन्याय किसे कहेंगे, कुशासन किसे कहेंगे ? अगर यही विषमतामूलक बंटवारा होते रहेगा तो सबका साथ और सबका विकास आपकी सरकार में कैसे हो पायेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ ? महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की राजनीति हमने सुना था कि प्रजा द्वारा प्रजा के लिए प्रजा की सरकार, लेकिन अब तो यह कहना होगा कि प्रजा द्वारा प्रजा को लूटने के लिए प्रजा की सरकार आपने बना दी है और आपने इसकी परिभाषा ही बदल दी है । लोकतंत्र का यही तकाजा होगा कि इसी लोकतंत्र के

हमलोग रक्षक हैं । हमलोग चाहते हैं कि किसी की आलोचना करने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि हम कहां के शिकारी हैं, हमारे पूर्वज आज तक मजदूरी करते आ रहे हैं । हम तो एकदम मालिक नहीं हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसी तरह के बजट में विषमतामूलक जमीन का बंटवारा, नौकरी का बंटवारा और शिक्षा का बंटवारा आपने किया तो विकास की बात करनी बेईमानी होगी । ऐसी राजनीतिक चरित्र को बदलना होगा, हम तमाम लोगों को बदलना होगा, आपलोग भी बदलिए । आप देश के नागरिक हैं, आप प्रेम, दया और मानवता रखिए । इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है । अगर यह धर्म नहीं है तो यहां लूटेरा भी धार्मिक है, बेईमान भी धार्मिक है, भ्रष्टाचारी भी धार्मिक है तो धार्मिक आप किसको कहेंगे ? आपने जो बजट की पुस्तक वितरण की है, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वर्ष 2022-23 में कुल 12375.7 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया,

..... क्रमशः .....

टर्न-24/शंभु/17.03.22

श्री रामवृक्ष सदा : क्रमशः लेकिन इसका व्यय किन-किन मद में कितना-कितना करेंगे, इसका जिक्र नहीं है । महोदय, आप ही की सरकार में दलित को दो भागों में बांटा और महादलित बनाया और महादलित विकास मिशन का गठन हुआ, लेकिन बजट में महालित विकास मिशन की चर्चा नहीं है । इसलिए आपकी सरकार दलितों के लिए बेमानी है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक जितना जुल्म दलित/महादलित पर हुआ है, दलित की महिलाओं पर जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है उतना जुल्म कभी नहीं हुआ है । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि छेड़ने पर मन भी बौचाल हो जाता है दोस्त, टूटने पर आइना भी काल हो जाता है दोस्त । मत करो हवन उतना दलितों के खून से, जलने पर कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज अनुसूचित जाति का जहां विद्यालय आपने बनवाया है वहां शिक्षक का अभाव है तो कैसे अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ पायेंगे ?

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार प्रारंभ करें।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांग को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि-

''हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम,
जख्म जितना गहरा हो, उतना मुस्कुराते हैं हम।''

मैं आपके प्रति और सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट पर पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया उसके लिए हम आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सीता प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी की महान जनता को जिसने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं को जो इतना सुंदर बजट पेश किया जो सर्वस्पर्शी और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत की अवधारणा पर चलनेवाला बजट जो सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया । महोदय, पथ निर्माण विभाग जब राजद की सरकार हटी और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी और आदरणीय नन्दकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री बनते हैं और जब मैं सीतामढ़ी से पटना की सड़कों पर गुजरता हूँ तो मुझे बाबा विश्वकर्मा याद आ जाते हैं क्योंकि सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा हैं तो इस पथ निर्माण विभाग के बजट के अवसर पर मैं पहले बाबा विश्वकर्मा का स्तुति करना चाहूंगा- विश्वेशम् विश्वकर्मा नाम विश्व निर्माण कार्यनाम् संयुक्तम् प्रमाम्यहम् । महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में (व्यवधान) आपलोग अलग से समय निकालकर आइयेगा मैथिली, हिन्दी सब भाषा में समझाऊंगा, आप जैसे समझना चाहियेगा सब भाषा में समझाऊंगा । महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में पथ निर्माण पर कटौती का प्रस्ताव ये विपक्षी लोग दे रहे हैं यह आश्चर्य है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं और इस्ट वेस्ट कोरीडोर सड़क का सपना देखकर, सपना को साकार किया जाता है । बिहार के सभी विधान

सभा क्षेत्र के लोग कहीं न कहीं उस चर्तुभुज स्वर्णिम योजना सड़कों को स्पर्श करते हैं और वहां से विकास की किरणें दिखती हैं बिहार की सरजमीन पर । महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में अटल पथ फेज–1, जी0पी0ओ0 गोलम्बर से भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर भाया आर0 ब्लॉक, राज्य उच्च पथ संख्या–102 जो बिहिया से जगदीशपुर का है, राज्य उच्च पथ संख्या–85 जो अमरपुर से अकबर नगर का है, राज्य उच्च पथ संख्या–84 घोघा पंजवारा तथा बिहारीगंज बाइपास, राज्य उच्च पथ संख्या–91 है । महोदय, राज्य के अधीन आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में पटना गया डोभी 127 कि0मी0, आरा मोहनिया 116 कि0मी0, नारायणपुर पूर्णिया 49 कि0मी0, बख्तियारपुर से रजौली 98 कि0मी0, पटना से बक्सर 92 कि0मी0, बख्तियारपुर से मोकामा 45 कि0मी0, सिमरिया से खगड़िया 60 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथों के फोरलेनिंग कार्य की अद्‌भुत प्रगति है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, विपक्षी की यह मांग है कि पटना से नागपुर बने उनके सपने को पूरा करेंगे, उनके सपने को भी पूरा करने का हम आश्वासन देते हैं । महोदय, जे0पी0 गंगा पथ परियोजना का वित्तीय संपोषण हुडको से तैयार कर इस महत्वाकांक्षी योजना के निर्माण में तेजी लायी गयी है । कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट पथ के निर्माण कार्य में प्रगति है, इन्डो नेपाल बोर्डर रोड परियोजना– जो कांग्रेस और राजद के लोग की भिजुअलिटी नहीं हो सकती थी, वैसा सपना सोच नहीं सकते थे, दूरदर्शिता नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भारत के सीमा की सुरक्षा के लिए और सीमावर्त्ती क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए इन्डो नेपाल बोर्डर परियोजना के 552.293 कि0मी0 के लिए 2502.72 करोड़ की लागत पर बिहार राज्य में भारत नेपाल सीमा के समानांतर टू लेन पथ का निर्माण करा रही है । सारण जिला के अन्तर्गत छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच डबल डेकर उपरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, राज्य सरकार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नौगछिया तेतरिया स्टेशन के बीच एल0सी0-11 एस0पी0एल0 पर, बक्सर जिलान्तर्गत चौसा बेरमो रेलवे स्टेशन के बीच एल0सी0-78(ए) पर, पटना जिलान्तर्गत दानापुर नेउरा रेलवे स्टेशन के बीच एल0सी0-38(बी) पर, सासाराम जिलान्तर्गत पहलेजा तरबंगिया स्टेशन के बीच एल0सी0-36(सी) पर, पूर्वी जिला अन्तर्गत एल0सी0-159, बक्सर जिलान्तर्गत एल0सी0-70(ए), सीतामढ़ी जिलान्तर्गत एल0सी0-56 ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए जो पथ निर्माण मंत्री ने अपना स्वीकृति दिया इसके लिए सीतामढ़ी की जनता की ओर से हम धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, बस एक लाइन है, मिथिला के क्षेत्र का है और उत्तर बिहार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है । सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिला के अन्तर्गत सीतामढ़ी, पुपरी, बेनीपट्टी पथ लंबाई 51.35 कि0मी0 के लिए भी हम पथ निर्माण मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को धन्यवाद देते हैं और दूसरा मुजफ्फरपुर जिला के अन्तर्गत हथौड़ी आथर बभनगामा जो वर्षों से चिर प्रतिक्षित पुल था, औराई पथ में आकर बभनगामा के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं । धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत, जय भारत माता ।

अध्यक्ष : सरकार के उत्तर के पहले माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, अपना पक्ष रखें ।

टर्न-25/यानपति/17.03.2022

श्री आलोक रंजन, मंत्री: महोदय, आपने कला संस्कृति एवं युवा विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं । हम आभारी हैं महोदय माननीय दो विधायक श्री अजीत जी और संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी जिन्होंने कला संस्कृति एवं युवा विभाग पर अपनी बातों को रखा है । उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं । महोदय, भारतीय संस्कृति दुनिया में अद्वितीय है । हमारा देश अपने

भौगोलिक संरचना की तुलना में सांस्कृतिक इतिहास से अधिक जाना जाता है । बिहार भारत की हृदयस्थली है । इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अतुलनीय है । कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और पूरे देश में एक मजबूत ''सांस्कृतिक जीवंतता'' बनाने के लिए तत्पर एवं कार्यरत है । बिहार की धरती ने दुनिया को पहला सम्राट अशोक भी दिया है । यहीं पर गुरू चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने अपने महान ज्ञान से पूरे भारत देश को एक सही मार्ग पर चलना सिखाया है । ज्ञान का आलोक परचम के तौर पर पहचान बनाने वाला नालन्दा विश्वविद्यालय भी कई वर्षों तक ज्ञान के उपासना का केन्द्र रहा । लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहली लोकतांत्रिक गणराज्य बिहार ने दिया है । इसी भूमि पर पौराणिक धरोहर स्थल जैसे- पावापुरी, विष्णुपद स्थल, बोधगया, कुम्हरार, फुलवारीशरीफ आदि स्थापित हैं । बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो भगवान भाष्कर की पूजा करती है, जहां डूबते सूरज की वंदना पहले किया जाता है तदोपरांत उगते सूरज का जो पूरे भारतवर्ष में रह रहे समुदाय को समाज के पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता प्रदान करने का संदेश देती है । बिहार की संस्कृति शिव शक्ति की महत्ता को भी दर्शाता है, जो हमें महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है । जैसे- बड़ी पटनदेवी एवं छोटी पटनदेवी, भुईयामाई, चाटीमाई, सिंधेश्वर स्थान आदि । संपूर्ण भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है महोदय, जहां अन्तर्राष्ट्रीय मानक का संग्रहालय (बिहार संग्रहालय) भी उपस्थित है । बिहार में हो रहे सांस्कृतिक विकास की गतिविधियां समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें, सरकार इस संकल्प को सार्थक करने की कोशिश में विभाग ने अपनी गतिविधियों को राज्य के सुदूर पंचायतों तक पहुंचाने की कोशिश की है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गतिशील नेतृत्व में न्याय के साथ समग्र और सतत विकास की राह पर आज बिहार अग्रसर है । हमें बड़ी खुशी है कि सरकार की विकास यात्रा में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग भी निरंतर क्रियाशील है और हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कुशल ओजस्वी नेतृत्व में हम निरन्तर नए लक्ष्यों और उपलब्धियों की ओर अग्रसर रहेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग में चार निदेशालय हैं जिसमें सांस्कृतिक निदेशालय के माध्यम से बिहार की समृद्ध

गौरवशाली विरासत से अवगत कराने के उद्देश्य से बिहार विधान सभा शताब्दी वर्ष समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सुनिश्चित कराई गई । विभाग के द्वारा पूर्व सांस्कृतिक क्षेत्र, कोलकाता, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद, भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद्, नई दिल्ली को बिहार राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कैलेण्डर के अनुसार जिलों में उत्सव एवं महोत्सव के आयोजन हेतु संबंधित जिला प्रशासन को राशि आवंटित कर उपलब्ध कराया जाता है । महोदय, राज्य में कलाकारों के कल्याण हेतु कलाकार कल्याण कोष योजना अंतर्गत कलाकारों को बीमारी से ग्रसित या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित से, इसके इलाज के लिए राशि दी जाती है । देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में उच्च अध्ययन शोध कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों आदि के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । राज्य में निबंधित स्वैच्छिक, सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान भी दी जाती है...

अध्यक्ष: संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री: प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में कलाकारों को सम्मानित करने के लिए बिहार कला पुरस्कार दिया जाता है महोदय । इतना ही नहीं कोरोनाकाल में, कोरोना जैसी महामारी काल में भी कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने आदि की योजना इस निदेशालय द्वारा चलाई गई । महोदय, माननीय विधायक श्री मुन्ना तिवारी जी कह रहे थे कि, हमको लगता है कि उनकी जानकारी में नहीं है कि, उनको हम बताना चाहते हैं महोदय कि कोरोनाकाल में जो कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राशि 2020 में हमलोग 1256 कलाकार अप्लाई किए थे उसमें 540 कलाकारों को हमलोगों ने उसमें दिया है 6 लाख 70 हजार रुपया और 2021 में जिसकी चर्चा वे कर रहे थे कि नहीं दिया गया, हमको लगता है माननीय विधायक जी को जानकारी नहीं है, 1009 आवेदन आये उसमें 228 सेलेक्ट हुए और 4 लाख 81 हजार रुपया हमलोग कलाकारों को जो है, देने का काम किए हैं । महोदय, हम बताना चाहते हैं, हमारा सांस्कृतिक, अभी माननीय विधायक अजीत जी कह रहे थे कि कहीं भी हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं है । महोदय, अभी हम सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में एक 600 सीट का प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी हमलोग बना रहे हैं और तीन जगह

जहां महात्मा गांधी की जगह से संबंधित था वहां 2000 की क्षमता का लगभग 41 करोड़ रुपये की लागत से एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं और 7 जगह पर 15 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं । महोदय, संग्रहालय, निदेशालय के माध्यम से कुल 28 संग्रहालय हमारे यहां हैं ।

अध्यक्ष: अब, प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री: महोदय, बस दो-तीन हमारा बहुत कम है । 28 संग्रहालय हैं महोदय और हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महोदय बहुत लंबा नहीं है ।

(व्यवधान)

ठीक है महोदय, इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

परिशिष्ट-द्रष्टव्य

सरकार का उत्तर, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के पथ निर्माण विभाग की मांग पर पक्ष-विपक्ष के 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है । मैंने सभी की बातों को नोट भी किया है और सभी माननीय अपने, विपक्ष के साथियों ने जिन-जिन विषयों को उठाया है, उनके सभी का जवाब हमारे पास है । और अगर वे हृदय से और धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक-एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और मैं सबसे पहले आज पथ निर्माण विभाग के इस बजट के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: मांग के साथ सबसे पहले मैं उस बात को याद करना चाहूंगा, कहा जाता है, एक कहावत है कि अगर किसी राज्य की समृद्धि देखनी है, किसी देश की समृद्धि देखनी है तो वहां की सड़कों को देखिए और मेरा मानना है कि सम्राट अशोक जी ने जब सड़कों के इस विषय पर काम किया होगा, आज उसी विजन को पकड़कर बाद में शेरशाह सूरी जी ने और बाद में हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क के क्षेत्र में जो क्रांति लाई उसका परिणाम हुआ कि आज पूरे देश में सड़क की चर्चा होती है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पूर्व के मंत्री श्री

नंदकिशोर यादव जी ने 2006 में जिन सड़कों के क्षेत्र का बीड़ा उठाया, आज पूरे बिहार में जो सड़कों का जाल बिछा है उसका पूरा-पूरा श्रेय माननीय नंदकिशोर यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है । उन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया है और मुझे एक अवसर मिला है उस रोड मैप पर आगे बढ़कर काम करने का । आज मैं इस विषय पर सबसे पहले अटल जी की उस कविता से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं ।

''क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही,
वरदान नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा ।''

मुझे लगता है अटल जी की वो कविताएं निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरणा देती हैं और खासकर के आज की युवा पीढ़ी को जिनको कभी कई चीजों को परिस्थितिवश देखना भी पड़ेगा और कई चीजों को संभालना भी पड़ेगा । आज सबसे पहले जब मैं चर्चा करता हूं तो राज्य के एम0डी0आर0 के सड़कों की चर्चा कर रहे थे । मैं केवल संक्षेप में एम0डी0आर0 की सड़कों पर आना चाहता हूं कि जब 2005 की चर्चा ये लोग कर रहे थे कि क्या सड़कों की स्थिति थी, आज हमारे पास सिंगल लेन की सड़कें जो 2005 के समय में 91 परसेंट थीं आज मात्र 41 परसेंट 2 लेन की सड़कें हैं, सिंगल लेन की सड़कें । आज इंटरमीडिएट लेन की सड़कें उस समय 6.25 परसेंट थीं, आज हमारे पास 42 परसेंट इंटरमीडिएट लेन की सड़कें हैं । जहां उस समय 4 लेन और 6 लेन में एम0डी0आर0 की सड़कों के बारे में सोचा और कल्पना भी नहीं किया जाता था आज 2 परसेंट से अधिक एम0डी0आर0 की सड़कें 4 लेन और 6 लेन में तब्दील हो रही हैं । सबसे बड़ी बात जो मैं इस वित्तीय वर्ष के लिए भी चर्चा कि आज वर्तमान में विभाग के पास 15273 कि0मी0...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: और जिसमें 2154 कि0मी0 की 2 लेन सड़कें हैं...

अध्यक्ष: अभी बहुत समय है, बैठ जाइये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: और मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष होता है कि 2021-22 में विभिन्न राज्य योजना के मद से आज 2021-22 में 176 कि0मी0 की सड़कें हमलोग एम0डी0आर0 के 46 योजनाओं के तहत कंप्लीट करा पाए हैं । हमलोगों ने केंद्र का सहयोग लेकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर सबसे अधिक बिहार को परेशानी आती थी उसमें भी केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार ने मिलकर इसपर काम किया जहां फेज-1 में हमलोग 903 कि0मी0 की सड़कों का काम करा पाए वहीं फेज-2 में हमलोग 590 कि0मी0 की सड़कों को लिया लेकिन हमलोग रुके नहीं और नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में दोनों डबल इंजन की सरकारों ने मिलकर काम किया उसका असर है कि आज नक्सल प्रभावित इलाकों में हर जगह दूर-दराज में भी सड़कों का जाल बिछा है । और इसी के तहत फेज-3 में भी हमलोगों ने करीब 190 कि0मी0 की योजनाएं ली हैं, 265 करोड़ की योजना से यह बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि जो पथ निर्माण की सड़कें जो बिहार के दूर-दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए थी वह पूरा फेज हमलोगों ने कंप्लीट किया है । अब नक्सल प्रभावित की जो बाकी सड़कें हैं वह आर0डब्लू0डी0 के तहत ली जाएंगी जिसका हमलोगों ने प्रस्ताव भेजा है । साथ ही साथ अब इसके बाद आते हैं स्टेट हाइवे जिसकी चर्चा मेरे मित्र सबलोग कर रहे थे, मुझे यह बात अच्छी लगी कि सभी मित्र कुछ सुझाव दे रहे थे और इस विभाग के बारे में भूदेव चौधरी जी एक विषय बोले । मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक चीज का जिक्र किया एस्टीमेट के बारे में ।

...क्रमश:...

टर्न-26/अभिनीत/17.03.2022

-क्रमश:-

श्री नितिन नवीन, मंत्री : मैं तो इस सदन का विधायक 2006 से हूं और मैंने कई चीजों को उस समय भी देखा, अब तो सबको मालूम है कि शेड्यूल रेट होता है, यह पूरे वेबसाईट पर जाता है और जो पुल-पुलिया का है उसको आई0टी0 और एन0आई0टी0 के इंजीनियर्स प्रमाणित करते हैं उस रेट को तब जाकर स्टीमेट और बाकी चीजों के प्रोविजन बनते हैं । यह वह समय नहीं है जो 2005 में था कि कागजों पर रिपोर्ट बनती थी, अब एक-एक चीज का वेरीफिकेशन होता है । मैं आपको इसलिए इस

बात को बहुत ही प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूं कि यह तो वेबसाईट पर है मित्रो । आप हमारे वरीष्ठ साथी हैं आप किसी भी वेबसाईट पर जाकर इसको देख सकते हैं । जहां तक स्टेट हाइवे के लिए बिहार में कई अलग-अलग फेज में काम किए गये, मैं इस बात का जिक्र केवल इसलिए कर देना चाह रहा हूं कि जब हमलोगों को मौका मिला तो माननीय नंद किशोर जी के समय में मात्र 44 परसेंट सिंगल लेन की सड़कें एस0एच0 की थीं । बाद में उसको हमलोग, इंटरमीडिएट लेन 52 परसेंट थी और दो लेन की सड़कें 2.37 परसेंट थी । आज हमलोगों ने सिंगल लेन को 12 परसेंट पर लाया और डबल और 67 परसेंट हमारी सड़कें एस0एच0 की टू लेन में परिवर्तित हुई हैं । ये अंतर हमारे बड़े पैमाने पर सिंगल लेन की सड़कों को इंटरमीडिएट लेन और इंटरमीडिएट लेन को टू ले करने से हुआ है । वर्ष 2021-22 में भी हमलोगों ने 130 मिलोमीटर राज्य उच्च पथ के उन्नयन की योजना को पूर्ण करने में सफलता पायी, जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय सदस्य के क्षेत्र की होगी, मैं उसके विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज की चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय नंद किशोर यादव जी ने जिस सोच के साथ डिपार्टमेंट ने काम किया और विभाग ने जिस तेजी से इस चीज को बढ़ाया कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमलोग हर, 2008-09 के बाद से हमेशा ऋण लेकर बड़े पैमाने पर एस0एच0 की सड़कों को लेते रहे हैं । प्रथम चरण में 824 किलोमीटर की सड़कें हमने लीं, द्वितीय चरण में 628 किलोमीटर की ली और तृतीय फेज में 231 किलोमीटर की सड़कें हमलोगों ने ली हैं । यानी 2008-09 के बाद से आप देख सकते हैं 1683 किलोमीटर की सड़कें स्टेट हाइवे की बनाने का काम बिहार सरकार ने की है । लेकिन हम यहीं नहीं रूके 2021-22 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का थर्ड फेज का ऋण लेने गये तो हमने 2727 करोड़ रुपये का ऋण लेकर करीब 285 किलोमीटर की योजना स्वीकृत करायी । यह बहुत ही इंपार्टेंट स्कीम है, मैं इसकी चर्चा आपके सामने इसलिए कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे । कठिहार-बलरामपुर बायसी की चर्चा कर रहे थे, बायसी-बहादुरगंज, माननीय सदस्य चले गये, उसकी निविदा भी हो गयी है, करीब 600 करोड़ की योजना है । अमरपुर बाईपास, मानसी फल्गो हॉल्ट, सिमरी-बख्तियारपुर 661 करोड़ की योजना है, बेतिया-नरकटियागंज 317 करोड़ की योजना है, मजबे-गोविदपुर 211 किलोमीटर की योजना है और अम्बेदेव-मदनपुर 184 करोड़ की योजना है । यानी हम स्टेट हाइवे को भी हर समय प्रयास करके और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में लगातार काम किया है और भविष्य में इसको हमलोग और आगे बढ़ाने जा रहे हैं । कई बार बातें आती हैं, ओ0पी0आर0एम0सी0 को लेकर हमारे माननीय सदस्य चिंता

कर रहे थे । मैंने देखा है कई सदस्यों ने जो विषय उठाये उन्होंने आजतक कोई कंप्लेन किया ही नहीं है ओ0पी0आर0एम0सी0 की सड़कों पर । यानी ओ0पी0आर0एम0सी0 में केवल मौखिक रूप से सदन में बोल देने से, आपके द्वारा किसी विषय पर कंप्लेन आता, मैं कह सकता हूं 2013 में जिस सोच के साथ इसे बनाया गया आज पूरे देश में इसकी चर्चा है । ओ0पी0आर0एम0सी0 की सड़कों का जब हमलो रिव्यू कर रहे थे, हमलोगों ने कुछ राज्यों में टीम भेजी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उनलोगों ने कहा ओ0पी0आर0एम0सी0 का जो आपका फार्मूला है, जो तरीका है इससे निश्चित रूप से रोड मेंटिनेंस में गति मिल रही है । 2013 में जब इसकी शुरूआत हुई तो हमलोगों ने करीब 9 हजार किलोमीटर की सड़कों को लिया था, फर्स्ट पैकेज में पांच वर्षीय मेंटिनेंस को लेकर । 2019 से 2026 के बीच में हमलोगों ने करीब 13 हजार किलोमीटर की सड़कों को मेंटिनेंस करने के लिए लिया । अब आपको बताते हुए खुशी होती है सभी माननीय सदस्यों को कि अगले एक महीने के अंदर अगले वित्तीय वर्ष में कमांड एण्ड कंट्रोल रूम से इसको हम जोड़ने जा रहे हैं । यानी ओ0पी0आर0एम0सी0 की जितनी भी सड़कें हैं उसको ऑन टाइम और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से हमलोग जोड़ेंगे । जब कभी भी कोई सदस्य सचिवालय आयेंगे तो वह अपनी सड़कों की स्थिति को मॉनिटर कर सकते हैं, वहां पर बैठकर देख सकते हैं कि उनकी सड़कों की स्थिति क्या है । सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निश्चित रूप से आई0टी0 को बढ़ावा मिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार सोच रही है कि अगर आपको काम करना है तो निश्चित रूप से आप आई0टी0 का पूरा लाभ लीजिए । उसी को देखते हुए हमलोगों ने, रोड एम्बुलेंस की चर्चा हुई, रोड एम्बुलेंस भी दो तरह के हैं । एक जो एक्सिडेंटल रोड एम्बुलेंस है उसको भी हम कंट्रोल एण्ड कमांड सिस्टम से जोड़ेंगे ताकि हमारी सड़कों पर कोई घटना घटे तो हमारे जो एम्बुलेंस हो वह सही समय पर पहुंच पाये । इसके बाद एक बात और बताते हुए हर्ष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां एक ओर लगातार सड़कों के क्षेत्र में बिहार को सहयोग मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार जो सोच रखी कि छः घंटे से पांच घंटे में कैसे परिवर्तित हो, उसके लिए उन्होंने सात निश्चत के तहत सुलभ संपर्कता पथ की योजना ली और इसके तहत भी हमलोगों ने इस वर्ष करीब 143 करोड़ की योजना जिसमें आठ प्रमुख बाईपास को हमलोगों ने लिया है और इसमें कुछ और बढ़ोत्तरी हमलोग करेंगे । अरवल जिला का कुर्था बाईपास, गोपालगंज जिला का कटिया बाईपास, वैशाली जिला में रामाशीष चौक से दिग्घी बाईपास, गया जिला में शेरघाटी बाईपास, नालंदा जिला में अरनौत से कोरनामा, पटना जिला में एन0एच0-30 से बिग्रहपुर करबिगहिया बाईपास,

कठिहार जिला में एन0एच0-81 से एन0एच0-31, दरभंगा जिला में जरिसो चौक से विष्णुपुर-बेनीपुर भाया बरमाजा पोखर तक । ये सारे बाईपास सुलभ संपर्कता की दृष्टि से लिये गये हैं निश्चित रूप से इसका लाभ आवागमन में जो शहरी क्षेत्र के जो बसावट हैं वहां के लोगों को निकलने में मिलेगा । अब हमारे कई साथी बोलते हैं एन0एच0 में डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ मिला ? मैं तो इस बात को इसलिए एन0एच0 के बारे में बोलने के पहले आपके सामने इस बात को रख रहा हूं जहां एन0एच0 के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पैकेज की चर्चा करते हैं मेरे मित्र लोग, 54 हजार करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी और आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज 1 लाख 25 हजार करोड़ से अधिक का काम एन0एच0 के क्षेत्र में बिहार में चल रहा है । माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है उसमें जो चीजें मुझे दिखती हैं When you focus on problem you will have more of problems. When you focus on possibilities you will have more opportunities. इसी ध्येय को लेकर हमलोग काम कर रहे हैं और इसका प्रतिफल भी हमलोगों को देखने मिला कि भव्य काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है वह कहीं न कहीं opportunity को बनाकर और possibilities के आधार पर बढ़ाया गया है । मैं एन0ए0 की चर्चा करने से पहले उस आंकड़ें को जरूर अपने मित्रों के सामने रखना चाहूंगा । क्या स्थिति थी एन0एच0 की ? आपके पास मात्र टू लेन और फोर लेन की सड़कें 2005 के पहले 21 परसेंट थी आज इसमें दुगुनी वृद्धि हुई है, करीब 40 परसेंट सड़कें आज टू लेन से फोर लेन में तब्दील हो चुकी हैं, मैंने पी0एम0 पैकेज की चर्चा इसलिए की । अब मैं एक विषय जो विभिन्न योजनाओं की चर्चा मेरे मित्र कर रहे थे, बख्तियारपुर-मोकामा की चर्चा कब खत्म होगी, मुझे इस बात को भी बताते खुशी हो रही है कि मुंगेर ब्रिज जो काफी समय से रूका हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष इनिसिएटिव लिया और करीब 60 करोड़ की योजना देकर उस अतिक्रमण को खाली कराया और आज मुंगेर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है । जहां एन0एच0 की बाकी योजनाओं की चर्चा हम करना चाह रहे थे, अभी करीब भारतमाला फेज-1 में 23 हजार 240 करोड़ की योजना का काम शुरू हुआ है, जिसमें सात प्रमुख परियोजनाएं करीब 5 हजार 86 करोड़ की योजना पर काम शुरू हो गया है । इसके अतिरिक्त पांच परियोजनाएं जिसका चयन किया जा चुका है जिसमें गोपालगंज फ्लाई ओवर, एन0एच0-28 का डुमरिया घाट गंडक पुल, आमद-दरभंगा का फोरलेनिंग, आमद-दरभंगा फोरलेनिंग पैकेज-2, एन0एच0-2 औरंगाबाद-चोरदाहा पदांश का सिक्सलेनिंग कार्य, ये करीब 5 हजार 298 करोड़ की

योजना का चयन किया गया है । तीन परियोजनाएं जो निविदा की प्रक्रिया में है, बेगूसराय शहर का एलिवेटेड फ्लाई ओवर, आमद-दरभंगा पथ का थर्ड फेज और फोर फेज करीब 4 हजार 553 करोड़ की यह योजना आलरेडी निविदा की प्रक्रिया में है । ये तो भारतमाला फेज-1 की चर्चा मैं कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात बताते हुए, कई मेरे मित्र मुझसे बातचीत के क्रम में कहते हैं कि सब जगह एक्सप्रेसवे आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां आमद-दरभंगा के माध्यम से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की कनेक्टिविटी को पहली बार हम कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर के करीब कनेक्टिविटी है आमद-दरभंगा और फोरलेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है । हमलोग यहीं नहीं रूके हैं और केंद्र सरकार की मदद से भारतमाला परियोजना फेज-2 में गोरखपुर- सिल्लीगुड़ी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिली है, जिसमें करीब 416 किलोमीटर का पदांश बिहार के क्षेत्र से गुजरेगा और पूरे उत्तर बिहार को कनेक्टिविटी मिलेगी । वाराणसी-कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, इसमें भी कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी और इसमें करीब 200 किलोमीटर की सड़कें बिहार के प्रक्षेत्र से गुजरेंगी । भारतमाला परियोजना फेज-2 मे ही एक और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम जिसकी स्वीकृति मिली है ।

-क्रमशः-

टर्न-27/हेमन्त/17.03.2022

(क्रमशः)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ये रक्सौल से पटना और पटना से पटना-कलकत्ता एक्स्प्रेस-वे बनकर जायेगा । यह बहुत बड़ा एक्स्प्रेस-वे, कह सकते हैं कि पूरे सिवान, पूरे कलकत्ता तक को जोड़ेगा और कह सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से भी यह बहुत बड़ी लोकेशन रहेगा । पटना-आरा-सासाराम ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस-वे की भी घोषणा की गयी है और 110 किलोमीटर की चार लेन में बनाया जा रहा है । मैं एक और चीज की चर्चा अपने सभी माननीय सदस्यों से करूंगा । माननीय नितिन गडकरी जी से जब हम लोगों ने राम जानकी पथ की चर्चा की । राम जानकी पथ पहले टू लेन था और हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी टू लेन और सिक्स लेन बन रहा है और हम लोगों ने इसके लिए आग्रह किया, तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और करीब 240 किलोमीटर की सड़कें, जो केंद्र सरकार की योजना से फोर लेन में चकिया, सिवान, सीतामढ़ी और पटना मोड़ को

जोड़ेगी और 240 किलोमीटर की सड़कें फोर लेन में तब्दील हो रही हैं । मुझे लगता है कि

(व्यवधान)

मैं उस पर भी आ रहा हूं ।

अध्यक्ष : सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : पुल प्रक्षेत्र में ब्रिज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चीजें रही हैं । राज्य सरकार ने पुल के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिये । सुल्तानगंज-अगवानी घाट पुल, जिसकी चर्चा मेरे माननीय सदस्य करते रहे हैं । मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि दिसम्बर 2022 तक इसको कम्प्लीट कर लेंगे । कच्ची दरगाह विदुहपुर पुल, जो करीब 4988 करोड़ रुपये की योजना से बन रहा है । इसकी लगातार हम लोगों ने मॉनिटरिंग की है और दिसम्बर 2023 तक इसको भी हम लोगों ने पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है । अध्यक्ष जी, एक योजना जो काफी समय से फंसी हुई थी । माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार ध्यान था उस ओर और एक पुरानी योजना थी, बख्तियारपुर, ताजपुर, जिसकी लागत 2825 करोड़ है । इस योजना को चालू करने में फिर से हम सफल रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की रही कि बख्तियारपुर और ताजपुर की योजना को हम लोग फिर से शुरू कर सके ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

2020 में जो बाढ़ आयी थी अध्यक्ष महोदय । 2020 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ में करीब एक हजार मीटर की लम्बाई से 00 का प्रावधान किया गया जिसमें 178 करोड़ की लागत से पहुंच पुल का निर्माण किया जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय अपोजिशन के सदस्य लोग इस बात से डरे हुए हैं और कोसी नदी पर पुल प्रक्षेत्र में, कोसी नदी मानसी, सहरसा के बीच में सरकार द्वारा स्वीकृत पुल की निविदा की गयी है । सोन नदी पर रोहतास जिला में पंडुका पुल जो बिहार और झारखंड को जोड़ेगा, उसके लिए 200 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चल रही हैं अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक योजनाओं की चर्चा

(व्यवधान जारी)

यह सारा काला चिट्ठा इनका है महोदय । इन सारे काले चिटठों का जवाब दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं । होली की शुभकामना तो लेते जाइये, बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अब मैं केंद्र की पुल के प्रक्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से करीब 9 बड़ी योजनाएं जो अभी चल रही हैं । बक्सर में अतिरिक्त दो लेन पुल, गांधी सेतु के समांतर फोर लेन पुल, राजेन्द्र सेतु के समांतर सिक्स लेन पुल, मनिहारी साहिबगंज के बीच में चार लेन पुल, जे0पी0 सेतु के समांतर दीघा-सोनपुर पर सिक्स लेन पुल, पटना रिंग रोड के अंतर्गत दिघवारा शेरपुर के बीच में भी सिक्स लेन पुल का प्रस्ताव स्वीकृत हो रहा है । इसके लिए भी बिहार सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपया का लैंड इक्वीजिशन का पैसा स्वीकृत कर चुकी है । विक्रमशिला सेतु के समांतर फोर लेन ब्रिज का काम काफी गति में है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को प्रारंभ करा पायेंगे । सोन नदी पर केंद्र सरकार द्वारा सिक्स लेन पुल का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है जो अगले वित्तीय वर्ष में जनता की सुविधा के लिए प्राप्त हो जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण फैसले और भी लिये हैं इसमें मीठापुर रामगोविंद हॉल्ट पर ऐलिवेटेड ब्रिज माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना से बन रहा है । उसमें भी कुछ नये डिजाइन्स के प्रोविजन किये गये हैं और एक हजार करोड़ की लागत से यह बन रहा है । पटना शहर में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज, जे0पी0 गंगा पथ जिसकी कल्पना बहुत पहले की गयी थी उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में बुडको से दो हजार करोड़ का ऋण लिया है । अटल पथ को जो हम लोग कनेक्टिविटी दिये हैं उसका लाभ यह मिलेगा कि दीघा आर ब्लॉक, जे0पी0 गंगा पथ, जे0पी0 सेतु, एम्स दीघा कॉरिडोर आपस में जुड़ जायेगा जिससे पटना के यातायात में सुविधा होगी ।

अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग ने अपने 248 अभियंताओं की नियुक्ति की है और उनको विशेष ट्रेनिंग देकर टी0टी0आई के दोनों ऑरियेंटेशन प्रोग्राम कराया गया है । साथ-ही-साथ हम लोग इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर और रेलिजियस सेंटर को भी कनेक्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं । समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि जो इस वित्तीय वर्ष की कुछ विशेष योजना जो हम लेने जा रहे हैं उसकी घोषणा आपकी अनुमति से हम करने जा रहे हैं । हम लोगों ने कुछ विशेष योजना ली जो 2022-23 हेतु हम लोगों ने ली हैं । सुपौल से अररिया जिलान्तर्गत एस0एच0 92 गणपतगंज से परवाह, यह 53 किलोमीटर की योजना हम लोग लेने जा रहे हैं । छपरा, सिवान जिलान्तर्गत मांझी-दरौली-गुटनी पथ जो काफी समय से काफी ट्रैफिक में रहा है, 71 किलोमीटर की यह योजना हम लेने जा रहे हैं । बक्सर जिला के अंतर्गत ब्रह्मपुर, कुरानसराय, इटारी, सरजा, जालीपुर इटारी-बक्सर सम्पर्क मार्ग को हम लोग लेने जा रहे हैं, यह 81 किलोमीटर की योजना है । नवादा और गया जिलान्तर्गत जेटियन,

गहलौर, भिन्सा पथ, यह एन0एच082 है, यह 41 किलोमीटर की योजना हम लोग लेने जा रहे हैं । भोजपुर जिलान्तर्गत आरा, एकौना, खैरा साहर पथ, 32 किलोमीटर की योजना हम लेने जा रहे हैं । मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी राजनगर, बाहुबरीर, पुटौना पथ, 41 किलोमीटर की यह योजना लेने जा रहे हैं । सीतामढ़ी, मधुबनी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी पथ, 51 किलोमीटर की यह योजना हम लेने जा रहे हैं । बांका, भागलपुर जिलान्तर्गत ढैरिया, इंग्लिश मोड, असरगंज पथ, 58 किलोमीटर की यह योजना लेने जा रहे हैं । मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी हथौरी, आथरबमन गामा औरयी पथ पर, बागमती नदी पर ब्रिज की, इस ब्रिज को भी लेने जा रहे हैं । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पटना के मंदिरी नाला को जे0पी0 गंगा पथ से जोड़ने जा रहे हैं । पटना अंतर्गत एन0एच0 83 पर अवस्थित, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष सोच थी कि पटना नाथोपुर है, जो पटना डोभी का पार्ट बना है उसको तो हम लोग जोड़ दिये, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था कि हम नाथोपुर से एम्स पटना ग्रीन फिल्ड को भी जोड़ेंगे । तो यह एक अल्टरनेट रिंग रोड के रूप में काम आयेगा । सैदपुर नाला के ऊपर हम एक पुल की योजना बना रहे हैं। साथ-ही-साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का परिसर और सेतु भवन और बिहार स्टेट डवलपमेंट का मुख्यालय का परिसर बनाने की भी योजना पर हम काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बस एक लाईन के साथ खत्म करूंगा कि Builds the roads jobs follow. मेरा यह मानना है कि अगर आप सड़क बनाते जायेंगे तो निश्चित रूप से आप रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्य श्री ललित प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 58,19,02,50,000/- (अठ्ठावन अरब उन्नीस करोड़ दो लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ सहधर्मी समाज के भी अंग हैं । हर मत में अलग-अलग ऋतुओं के अनुसार पर्व मनाने की परंपरा हमारे यहां है । आने वाले दिनों में हम ऋतुराज वसंत के आनन्द और उल्लास से सराबोर राग और रंग का त्यौहार होली मनाने जा रहे हैं । आज होलिका दहन है, इस अवसर पर हम अपने विकारों, अहंकारों, गिले-शिकवे और शिकायतों का दहन कर नये संवत में प्रवेश करें । नयी ऊर्जा, नयी उमंग, प्रेम और सौहार्द के रंगों में रंग जाने का संकल्प लें । क्लेश और द्वेष की तरफ पीठ कर शांति और सद्भाव को गले लगाने का प्रयास करें । इस अवसर पर लोकतंत्र और विधायिका की नयी मजबूती के साथ हम सभी अपनी जिम्मेवारी के सम्यक् निर्वहन के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की प्रेरणा प्राप्त करें । आगामी 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाने जा रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं । यह दिन हमारे राज्य में प्राचीन काल से चला आ रहा है । जन-गण के मन की आशाओं के अनुसार आगे बढ़ने वाली राज्य और समाज की व्यवस्था को रेखांकित करने का दिन है । बिहार दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उस महान धरती के अंग हैं जहां से शांति, सौहार्द लोकतंत्र की सीख दुनिया को मिली है ।

(क्रमशः)

टर्न-28/धिरेन्द्र/17.03.2022

क्रमशः....

अध्यक्ष : अतः हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी सबसे ज्यादा है। हमें विवाद से बैर की ओर न जाकर विश्वास की राह लेनी है, संवाद से समस्या की जगह समाधान की तरफ बढ़ना है । यही बिहार की इस महान भूमि और इसे गौरवान्वित करने वाले हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है । एक बार फिर शुद्ध मन और सकारात्मक भाव के साथ हम सभी जन-कल्याण के प्रति संकल्पित हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तथा पूरे सदन की ओर से देश और प्रदेश के जन-जन को होली तथा बिहार दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आपने जो आसन से भावना व्यक्त की है, हम सरकार की तरफ से आपकी भावनाओं के साथ सरकार की भावनाओं को जोड़ते हैं। आपने जैसे कि बातें तय हुई थी कार्य मंत्रणा समिति में कि शायद आप आज 23 तारीख तक के लिए सदन स्थगित करेंगे और इस बीच में हमलोगों का त्यौहार है । आज आपने कहा होलिका दहन है, कल या परसों होली दो दिन पड़ रहा है और 22 तारीख को बिहार का जन्मोत्सव है महोदय । बिहार दिवस हमलोग अपने प्रदेश का जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं चूंकि इस बिहार दिवस के कार्यक्रम का संयोजन शिक्षा विभाग करता है । आपने बिहार दिवस के साथ होली, होलिका दहन की शुभकामनाएं माननीय सदस्यों को और प्रदेश के लोगों को दे ही दी है तो हम सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से चूंकि हम बिहार दिवस के आयोजक हैं, नोडल डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, हम भी सदन के माननीय सारे सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि आज आप यहां से निकलेंगे फिर होलिका दहन से लेकर होली का त्यौहार अपने-अपने ढंग से जहां मन हो मना लीजिये लेकिन 22 तारीख को दिन में पटना जरूर तशरीफ ले आइये क्योंकि 22 तारीख से जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगा और आपको सुन कर अच्छा लगेगा कि अपने प्रदेश और अपनी मिट्टी का जन्मोत्सव मना कर हम तीन दिनों तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिसमें देशभर के प्रख्यात कलाकार आप बिहार वासियों का मनोरंजन करने पटना पधार रहे हैं और हम अपने बिहार के कलाकारों को भी प्रोत्साहित करने के लिए आपके बीच उनकी प्रस्तुति देंगे । इसलिए आप सबों को निमंत्रित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आप आज जायेंगे लेकिन 22 तारीख को दोपहर तक जरूर आ जाइये अनेक कार्यक्रम और बिहार का जन्मोत्सव आपकी प्रतीक्षा करेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 मार्च को 'द कश्मीर फाइल्स' के प्रदर्शन को देखने के लिए P&M मॉल में संध्या 6.30 बजे आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि P&M मॉल के हॉल में उसका प्रदर्शन होगा और शेष अन्य सूचनाएं दोनों सदन के माननीय सदस्यों को दी जायेगी।

अध्यक्ष : 25 मार्च को ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : जी, महोदय । 25 मार्च को संध्या 6.30 बजे और अंत में मैं आपके माध्यम से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने सभी सदस्यों को देता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री संजय सरावगी : टैक्स फ्री हो गया है ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : हाँ, आज से टैक्स फ्री लागू है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आज दिनांक- 17 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 49 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक- 23 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बजट वक्तव्य : 2022–23

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भारतीय संस्कृति दुनिया में अद्वितीय है। हमारा देश अपने भौगोलिक संरचना की तुलना में सांस्कृति इतिहास से अधिक जाना जाता है। बिहार भारत की हृदयस्थली है। इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अतुलनीय है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और पूरे देश में एक मजबूत "सांस्कृतिक जीवंतता" बनाने के लिए तत्पर एवं कार्यरत है।

बिहार की धरती ने दुनिया को पहला सम्राट (अशोक) भी दिया। यही पर गुरू चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने अपने महान ज्ञान से पूरे भारत देश को एक सही मार्ग पर चलना सिखाया। ज्ञान का आलोक परचम के तौर पर पहचान बनाने वाला नालन्दा विश्वविद्यालय भी कई वर्षों तक ज्ञान के उपासना का केन्द्र रहा। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहली लोकतांत्रिक गणराज्य बिहार ने दिया। इसी भूमि पर पौराणिक धरोहर स्थल जैसे– पावापुरी, विष्णुपद स्थल, बोधगया, कुम्हरार, फुलवारीशरीफ आदि स्थापित है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जो भगवान भाष्कर की पूजा करती है। यहां डूबते सूरज की वंदना पहले किया जाता है तदोपरांत उगते सूरज का जो पूरे भारतवर्ष में रह रहे समुदाय को समाज के पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता प्रदान करने का संदेश देती है। बिहार की संस्कृति शिव शक्ति की महत्ता को भी दर्शाता है, जो हमें महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। जैसे :– बड़ी पटनदेवी एवं छोटी पटनदेवी, गुईयागाई, चाटीमाई, सिंधेश्वर स्थान आदि। संपूर्ण भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां पर अन्तर्राष्ट्रीय मानक का संग्रहालय (बिहार संग्रहालय) भी उपस्थित है।

बिहार में हो रहे सांस्कृतिक विकास की गतिविधियाँ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें, सरकार के इस संकल्प को सार्थक करने की कोशिश में विभाग ने अपनी गतिविधियों को राज्य के सुदूर पंचायतों तक पहुँचाने की कोशिश की है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गतिशील नेतृत्व में न्याय के साथ समग्र और सतत् विकास की राह पर आज बिहार अग्रसर है। हमें बड़ी खुशी है कि सरकार की विकास–यात्रा में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग भी निरंतर क्रियाशील है और हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कुशल ओजस्वी नेतृत्व में हम निरन्तर नए लक्ष्यों और उपलब्धियों की ओर अग्रसर रहेंगे।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

इस निदेशालय के द्वारा बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक, लोक परम्परा एवं संगीत के क्षेत्र में नवोदित प्रतिभा को उभारने हेतु कार्य किया जाता है। राज्य के विभिन्न स्थानों में सांस्कृतिक विविधता को अक्षुण्ण रखने हेतु हम कार्य करते हैं।

- बिहार विधान सभा के शताब्दी वर्ष समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।
- पूर्व क्षेत्र संस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता/उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद/भारतीय सांस्कृतिक संबंद्ध परिषद, नई दिल्ली को बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्थानीय स्तर पर सहयोग करना।
- सांस्कृति कैलेण्डर के अनुसार जिलों में उत्सव एवं महोत्सव का आयोजन।
- कलाकार कल्याण कोष योजनान्तर्गत कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- निबंधित स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना।

- चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित करना।
- कोरोना काल में कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देना।
- 7 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में 600 क्षमता का आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य जारी।
- महात्मा गांधी के चम्पारण शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2500 क्षमता का प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य बेतिया, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में जारी।

संग्रहालय निदेशालय

बिहार की समृद्ध विरासत, गौरवशाली अतीत, महापुरूषों की विरासत को जन जन में पहुँचाने हेतु हमारा निदेशालय कार्य कर रहा है।

- बिहार में कुल 28 संग्रहालय स्थापित है जिसमें संग्रहालय निर्माण एवं पूर्व संचालित संग्रहालयों को पूर्ण संयोजित करने की योजना।
- वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य जारी। साथ ही प्रवेश द्वार एवं विकास हेतु सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत।
- बिहार संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले का आयोजन।

पुरातत्व निदेशालय

राज्य में हजारों वर्ष पूर्व के इतिहास, साम्राज्यों का उत्थान पतन, प्राचीन सम्यता आदि की खोज एवं संरक्षण हेतु यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

- राज्य में कुल 54 स्थल सुरक्षित घोषित है।
- पुरातात्विक एंव ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों/स्थापत्यों, कलाकृतियों अादि का अन्वेषण संरक्षण/अनुरक्षण, उत्खनन की योजनाएं।

- पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन एवं संगोष्ठी/कार्यशालाओं के आयोजन की योजनाएं।
- तेल्हाड़ा (नालंदा), गुलजारबाग प्रेस परिसर (पटना सिटी), भदरिया (बांका), गुआरी डीह(भागलपुर) एवं ~~पटना संग्रहालय परिसर के उत्खनन की योजनाएं।~~
- चीनी यात्री हवेनसांग की यात्रा पथ का पुरातात्विक अन्वेषण कराने की योजनाएं।

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय

राज्य में खेलकूद का विकास खिलाड़ी की पहचान, नवोदित प्रतिभाओं की खोज के क्षेत्र एवं राज्य को खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु हम कार्यरत हैं।

- राज्य स्पोर्टस एकेडमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का कुल 740 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य राजगीर में जारी।
- बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।
- माईनुलहक स्टेडियम, पटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया जारी।

23 जिलों में

- 41 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित।
- प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की योजनाएं संचालित।
- जिलों में मल्टी जिम, ओपेन जिम एवं खेल उपकरणों का अधिष्ठापन की योजनाएं।
- राष्ट्रीय खेल दिवस(29 अगस्त) के अवसर पर खेल सम्मान समारोह का आयोजन।
- खिलाड़ी कल्याण कोष की योजनाएं संचालित।

- खेलों इण्डिया योजनान्तर्गत राज्यों में आधुनिक खेल अवसंरचनाओं निर्माण की योजनाएं अब तक कुल 11 योजना स्वीकृत– 55 करोड़ व्यय 24 योजना प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि हेतु खेल मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित।
- बिहार काउट गाईड को स्थापना व्यय एवं अन्य कार्यक्रम हेतु 30 लाख की सहायता अनुदान।
- एन.सी.सी को को स्थापना व्यय एवं अन्य कार्यक्रम हेतु 44 करोड़ 74 लाख 8 हजार रूपया सहयता अनुदान ।
- एन.एस.एस के द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान।
- इण्डोर खेलों में खेल उपकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजनाएं।
- 31 जिलों में व्यायामशाला–सह–खेल भवन निर्माण की योजनाएं।
- इण्डोर खेलों में खेल उपकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजनाएं।
- 31 जिलों में व्यायामशाला–सह–खेल भवन निर्माण की योजनाएं।

अतः मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के बजट को पारित करने की कृपा करेंगे।